

SHRI S. M. BANERJEE: Because the proceedings will not be reported in the Press. The Supreme Court gave a judgement yesterday striking down the Central Government's order regarding the application of the Wage Board award to PTI employees. I feel because of that the PTI employees are extremely angry and they will not report even the Parliament's proceedings. So, the Government should intervene in the matter.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Banerjee, you are very clever, but I am not that dull.

Now we will proceed with the further discussion of the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture.

Shri Shivanath Singh to continue his speech.

13.55 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75-
Contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE—contd.

श्री शिव नाथ सिंह (जूगू) : उपाध्यक्ष जी जैसा मैं कल कह रहा था कि देश में हरित क्रांति हुई, खेती के मामले में प्रगति हुई लेकिन जितना काश्तकार को उस का लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। काश्तकार द्वारा पैदा की गई चीज की कीमत तय करने का अधिकार दूसरे श्राद्धियों को है, उस को खुद को नहीं है। जब कि इस के विपरीत उद्योग में जो माल पैदा होता है उस की कीमत स्वयं उद्योगपति तय करता है। यह ठीक है कि इन दिनों महंगाई की वजह से काश्तकार को कुछ ज्यादा पैसा मिलने लगा है, लेकिन फिर भी बिचौलिये काश्तकार की कमाई को खा रहे हैं। इस-लिए ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मामले में इन बिचौलियों को घाय दूर कीजिए और जितनी

भी फ़ेयर और रीज नेविन कीमत काश्तकार को मिल सकती है वह दीजिए। बीच के श्राद्धियों को निकालिये, और जो काश्तकार की प्रोड्यूस है उसका रीजनेबिल प्राइस पर मार्केट सरकार पैदा करे तभी काश्तकार को फ़ायदा मिल सकता है।

दूसरी बात यह कह रहा था आज काश्तकार को सरकारी संस्थाओं से कर्ज पर पैसा मिल रहा है और उसको साहुकार के यहाँ नहीं जाना पड़ता सरकार से पैसा मिल रहा है लेकिन जिन कामों के लिये किसान को पैसा दिया जाता है, चाहे कुएँ हों, या ट्यूबवैल हों उन का रिटर्न उसको फौरन नहीं मिलता और उस का कारण यह है कि उसको समय पर बिजली नहीं मिलती। काश्तकार को ट्वबैल के लिये, पम्पिंग सेट के लिये रुपया मिलता है लेकिन पांच, पांच साल तक उसको बिजली नहीं मिलती है जिसकी वजह से उसको अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलता है। इस तरफ सरकार ध्यान दे जिससे ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े।

ऐग्रीकल्चर के मामले में बहुत कुछ पैपर पर आगे बढ़ गये, जब कि वास्तविकता में उतने नहीं बढ़े क्योंकि हम देखते हैं कि ऐग्रीकल्चर सेक्टर में प्लान के अन्दर जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिये वह हर प्लान में कम हुआ है और वह इन्वेस्टमेंट घटते घटते 13 परसेंट रह गया है। अगर हम चाहते हैं कि ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े तो इस सेक्टर के लिये कम से कम 25 परसेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिये। इसके बगैर काम नहीं चलेगा।

माननीय शिन्धे माहब कह रहे थे कि ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती। मैं मानता हूँ कि जो आलरेडी डेबलपड कन्ट्रीज है वहाँ ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती। लेकिन भारत की तो एक ग्रोथिंग इकोनोमी है, आज हमारे यहाँ बहुत सी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, ऐसे इलाके हैं जहाँ मिचवाई के साधन न होने की वजह से खेती नहीं हो

[श्री: शिवनाथ सिंह]

सकती, ऐसी जमीनों को खेती के अन्दर लाया जा सकता है और ग्रोथ रेट बढ़ायी जा सकती है। इसलिये ग्रोथ रेट को बढ़ाने का प्रोग्राम होना चाहिये ताकि किसान को अधिक मदद दे सकें।

ग्राज किसान की यह हालत है कि इंडस्ट्री के लिये ग्राप बहुत कम रेट पर बिजली देते हैं, जब कि किसान को 13, 15 पैसे पर यूनिट पर देते हैं। वह किसान जो खुले आसमान में जाड़ा, गर्मी और बरसात में काम करता है 18, 18 घंटे लेकिन इंडस्ट्री में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अतः हमें किसान की बर्किन्ग कंडीशन को इमप्रूव करना पड़ेगा। उद्योग में काम करने वाले मजदूर का उतनी हार्डशिप नहीं होती जितनी कि काश्तकार को। लेकिन काश्तकार को उसकी मेहनत के अनुसार रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिये उस को सहूलियत देनी चाहिये।

खाद और दूसरे इनपुट आपको किसान को रिजनेबिल प्राइस पर देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा। कृषि के अन्दर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ। अगर आप 1060-61 से 1970-71 की फिगर्स को देखें तो पायेंगे पब्लिक एक्सपेंसेज का अमाउन्ट एग्रीकल्चर पर तिगुना बढ़ा, लेकिन इंडस्ट्री पर 5 गुना बढ़ गया है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 25, 26 परसेंट बढ़ा है इन 10 सालों में। तो जहां एक्सपेंडिचर तिगुना हुआ है, इंडस्ट्री के मुकामने में एग्रीकल्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट पब्लिक एक्सचेंजर से ज्यादा होना चाहिये था। आप कह सकते हैं कि-बड़े बड़े बाघ, बिजली की योजनायें, इनको भी एग्रीकल्चर में ही लेते हैं तो भी 290 करोड़ से 893 करोड़ पर पहुंचा है, जब कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 142 करोड़ की जगह 712 करोड़ पहुंच गया है।

आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश खाद्यान्न में सेल्फ-सफिशियेंट है हालांकि कामज पर ही यह है, लेकिन हम गांवों की हालत जानते हैं। पिछले साल भयंकर अकाल पड़ा और दोनों फसले खत्म हो गईं लेकिन फिर भी 4 मिलियन टन अनाज हम इम्पोर्ट कर पाए और बाकी सब हमारे काश्तकारों ने दिया। इस साल भी बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में आज भी अनाज का सरप्लस भंडार है और आगे आने वाले 6, 8 महीनों में अगर एक दाना भी न हो, तो भी सरप्लस अनाज है। इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाहर से जो हम अनाज मंगाते हैं उस पर हमें बहुत बड़ा एमाउन्ट खर्च करना पड़ता है। वह खर्च न कीजिये क्योंकि आज हमारे देश के अन्दर काफी भंडार है लेकिन ठीक तरह से उसको रेगुलराइजेशन हो और किसानों से कन्ज्यूमर्स के पास वह पहुंचे, इस के लिए आपके मिस्टम में सुधार की आवश्यकता है।

आपने खाद्यान्न के संबंध में एक नई पालिसी घोषित की है कि 105 रुपये प्रति बर्बीटल पर व्यापारी किसान से गेहूं लेगा और उसको 150 रुपये तक बेचने की आप ने छूट दी है। हमारे दल ने एक नीति निर्धारित की है और एक बफादार सिपाही के नाते मैं उस का पूर्ण समर्थन करता हूँ लेकिन मेरी कुछ अपनी शंकाएँ हैं। आप व्यापारी द्वारा 105 रुप में खरीद करने की बात मोचते हैं लेकिन हो सकता है कि 105 की बजाय व्यापारी को 125 या 130 रुपये प्रति बर्बीटल में वह मिले। आप व्यापारी को एक सरप्लस स्टेट से डिफिनिट स्टेट में सप्पाई करने की इजाजत देने वाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि और जानना चाहूंगा कि अगर एक काश्तकार आपकी लेबी की कंडीशन को पूरा कर देता है, आपको लेबी का 50

परसेंट गेहूँ दे देता है, तो उसको भी प्राप डेफिसिट स्टेट में गेहूँ लेजने और बेचने की सक्षमता देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? यह एक किलमर कट बात है। आज किसान के मन में बंका है कि सरकार यह चाहती है कि यह व्यापारी के हाथ में जाये। वह चाहता है कि व्यापारी को मुनाफा हुये बिना यह बिके और इसके लिये एक बहुत बड़ा एजीटेसन है। संजान में बहुत से किसान इसीलिये घनाज नहीं ला रहे हैं। वे कहते हैं कि व्यापारी हमारे बीच में क्यों प्राये। इसलिए सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिये कि जब प्राप किसान से 50 परसेंट लेवी लेने के बाद डेफिसिट स्टेट्स में घनाज बेचने की इजाजत देने वाले हैं, तो किसान को भी, अगर वह 50 परसेंट लेवी का गहूँ दे देता है, डेफिसिट स्टेट्स में अगर प्रापकय कता हो, तो घनाज बेचने की इजाजत हो।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तकने यह सोचा कि 105 रुपये में किसान से गेहूँ बिना जम्मा और 150 रुपये में व्यापारी उसे बेचेगा, तो वह संभवता सही नहीं है कि व्यापारी आपको सही रूप में 50 परसेंट लेवी का गेहूँ दे दे। वह एक इम्पसिबिल बात है और वह हो नहीं सकता इसलिये कि आज प्राप ने 133, 134 रुपये प्रति क्वींटल के हिसाब से जो मुकानदार हैं, उनके द्वारा घबनी सप्लाय करने का बाब रखा है, तो इसके कम पर प्राप को नहीं गेहूँ मिलने वाला नहीं है। प्राप क्या यह समझते हैं कि व्यापारी इसके इनामदार हैं कि वे 135, 136 रुपये के हिसाब से खरीद कर आपको 105 रुपये पर प्राप को दें। वे आपको सही फीसल देने वाले नहीं हैं। वह हो सकता है कि वे आपको बंधियों में से गेहूँ न खरीवे और नहीं और से खरीवें। इसके अन्दर बहुत बड़ा अन्वय होने वाला है। इस लिये वह पाकिष्ठी प्राप एक्सपेरिमेंट के और पर कीजिये लेकिन इस में सुधार करने की प्रापकय-कता है।

507 LS—10

एक आखरी बा। मैं यह निवेदन करना चाहता कि जिस तरह का समझौता प्रापने व्यापारियों के साथ किया है, क्या प्राप कोई और समझौता नहीं करने को तयार हैं। प्राप के हेडलिन चार्ज 26 और 27 रुपये प्रति क्वींटल प्राते हैं। क्या माननीय कृषि मंत्री जी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई 20 रुपये में इस को करने की गरन्दी दे, तो उस को प्राप यह काम दे देंगे। प्राप जो प्रापके 26 और 27 रुपये प्रति क्वींटल हेडलिन चार्ज प्रा रहे हैं यह बहुत ज्यादा है और इसके अन्दर सारी मशीनरी का बहुत बड़ा हाब है। और किसी भी व्यापार के लिये इस प्रकार की चीज संभव नहीं हो सकती क्योंकि इससे कम्प्यूमर को नुकसान है और कामतकार को भी बाटा है। इसलिये प्राप इन हेडलिन चार्ज को कम कीजिये क्योंकि 20 और 15 रुपये प्रति क्वींटल में यह हो सकता है। (बाँटी)

मैं उत्तर कर रहा हूँ। आखरी बात यह है कि अगर कोऑपरेटिव के मामले को सुझाविये। विशेष एकेनाकी में कोऑपरेटिव की मशीनरी उत्कृष्ट एक फाट बन गई है और सब काम उसकी गरफत हो।

इन सबमें के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगो का सम्बन्ध करता हूँ।

14.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister will reply at 4 P.M. There are thirteen more from the Congress Benches and a few more from the Opposition. The Whip of the Congress Party has requested me that the Congress Members may be given eight minutes each.

I would request them to cooperate with me and with him in keeping within the time.

Shri Ram Chandra Vikal.

जी राजवन्धु विकास (शरदपत्र) :
उपाध्यक्ष महोदय, कृषि अनुदानों पर हुई बहुत में जो आप ने मुझे बोलने का समय दिया, उस के लिए मैं आप का बहुत अनु-ग्रहीत हूँ। इस विभाग की मांगों का मैं सम्बन्ध करता हूँ। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विभाग से सम्बन्धित सारे कार्य जन-जीवन से धीरे इस देश के बहुत बड़े भाग से सम्बन्ध रखते हैं और सब प्राणी-मान्य उन पर आश्रित भी हैं।

शिव्दे साहब का ध्यान मैंने आखबारों में पढ़ा और मौर्य जी का भाषण मैंने यहां बैठ कर सुना और उन्होंने यह भाषा व्यक्त की है कि देश बहुत जल्द आत्म-निर्भर होगा आखबार के आगले में। उस के लिए मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। मैं आश्चर्य से कहता हूँ कि और आश्चर्य करता हूँ कि उन की यह भावना पूरी हो लेकिन देश के अन्तोत्पादक और देश के मजदूर जो खेत में और खान में काम करते हैं, ये सबकुछ हमारे देश के बे कौश हूँ जो इस देश में अर्थिक अन्ति लाने वाले हैं अगर उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि इस देश में जो आर्थिक विषमता फैली हुई है, जो अस्तमानता है और उसकी वजह से बाहरों तरफ प्रसंतोष और निराशा फैली हुई है, यह दूर हो। आज जो पैदा करने वाला है, उसमें अधिक मुनाफा मकल बदलने वाला चाहे उद्योगपति हो और चाहे जगह बदलने वाला व्यापारी हो और माघ में मैं जोर देता हूँ सरकारी कर्मचारी को भी उठाता है। ये ज्यादा सुखी और सम्पन्न हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और ज्यादा आराम से रहते हैं उसके मुकाबले जो कि पैदा करता है। अगर हमारे देश में आर्थिक क्रान्ति में कोई रोड़ा है तो ये तीन वर्ग हैं जो कि इन देश के महानतकशों को धागे नहीं बढ़ने देते और इस देश में जो आर्थिक विषमता है, उस को मिटाने नहीं देते और आर्थिक क्रान्ति करने वालों को सावर और सम्मान नहीं देते। यह एक विशेष कारण है।

अब मैं मंत्री महोदय से कुछ काफ़ूकी विकसित बताना चाहता हूँ जो कि व्यवहारिक नहीं है और अब वह समय आ गया है जब कि देश में बाहरों तरफ प्रसंतोष और निराशा फैली हुई है कि हम को यह सोचना पड़ेगा कि हम चन्द सरकारी कर्मचारियों के जो विचार हैं उनको अपने जुद्ध से सच में न कहें। अब हम को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये विचार व्यवहारिक नहीं होते। मैं धागे के साथ कहना चाहता हूँ और मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ कि ये व्यवहारिक नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक फैसला लिया गया था कि हम किसान को सहायता देने के लिये ऋण के रूप में चाहे वह पॉम्पब सैट के लिये हो, चाहे ट्रैक्टर के लिये, चाहे थ्रेशर के लिये और चाहे त्रशर के लिये हो या किसी भी मशीनरी के लिये हो, हम किसानों को सीधे बैंक देंगे और किसी फर्म या किसी दुकानदार के नाम से बैंक नहीं काटेंगे। यह फैसला बैंकों ने रोक दिया और उसको चर्च नहीं दिया। मैं वित्त मंत्री जी चर्चा से विनम्र में मिला और उन्होंने वित्त से यह कहा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये ही क्यों हो रहा है, यह तो हमारे देश के किसानों के हक में होना चाहिये। यह फैसला बड़ा व्यवहारिक है क्योंकि यह जो बैंक मिलता है फर्म को, तो उसमें सरकारी कर्मचारी भी सम्बन्धित होता है और उसमें खुले रूप में कफन है, भ्रष्टाचार है और किसानों को जो सही राशि है, वह नहीं मिल पाती। उसमें काफी भ्रष्टाचार है और सही राशि उसे नहीं मिल पाती और पता नहीं कितना उसको दफ्तरों में जा कर धकेलने जाने पड़ते हैं। धनी इस धारे में वित्त मंत्रालय का फैसला नहीं हुआ है। मैं कृषि मंत्रालय को इसलिये महत्वपूर्ण भागदाह हूँ कि जहां जन जीवन से इसका संबंध है, वहाँ कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिसका इससे सम्बन्ध न हो या जिसका प्रभाव इस विभाग पर न पड़ता हो चाहे वह वित्त मंत्रालय ही न

रेल मंत्रालय या धीरे-धीरे कोई मंत्रालय हो धीरे-धीरे चाहिए वह सिखाई मंत्रालय हो। सभी का किसी न किसी रूप में इस कृषि मंत्रालय पर अक्षर पड़ता है धीरे-धीरे वह लोट फेर कर इस देश के किसानों पर पड़ता है। तो वित्त मंत्री जी ने जो भाषाबासन दिया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक छोटा सा मुद्दा है धीरे-धीरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है मगर क्योंकि सरकारी अक्षर उसमें सामीप्य होते हैं धीरे-धीरे एक तौर से, मैं सबके लिये यह बात नहीं कहना चाहता, बहुत से अक्षर अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग इस को अमल में नहीं आने देना चाहते हैं।

इसी तरह में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आप ने यहीं दिल्ली में खोये और क्रिम पर पाबन्दी लगा दी है। एक छोटी सी बात है और मीय साहब से भी लोगों ने इस बारे में बात की है। और उन्होंने मीटिंग भी की है, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं दस साल से गिन्दे साहब से इस सवाल पर बड़ रहा हूँ कि आखिर आप दिल्ली में ही इस पर बैन क्यों लगाते हैं। बम्बई में खोया जा सकता है और वहाँ पर क्रिम बन सकती है जबकि वह दिल्ली में भी बड़ा शत्रु है लेकिन यहाँ पर आप ने दिल्ली में दूध के उत्पादकों पर खोया या क्रिम बनाने पर पाबन्दी लगा दी है। दिल्ली के अड़ोस-पड़ोस में जो बेचारे किसान सब्जी पाल कर अपना गुजारा करते हैं और जिनको इस अड़ोस, जून के महीने में थोड़े प्यासा पैसे मिल जाते, उन उत्पादकों के लिये आपने कानून बना कर दिया यह पाबन्दी लगा दी है। पहले तो दिल्ली के पास पास के दो जिलों,

मेरठ और बुलन्दशहर में खोया और क्रिम बनाने के लिये सिर्फ दो महीने के लिये पाबन्दी लगती थी, लेकिन अब की बार इस को बार महीने के लिए लगा दिया है और अब इस पर आपत्ति उठाई गई, तो इसको आपने धीरे-धीरे हरियाणा में शुरू कर दिया और तर्क के रूप में मुझे बताया गया है कि कानपुर और लखनऊ में भी इसको कर रहे हैं। यह एक गलत बात है और दिल्ली के लोग ही हमसे परेशान हैं। मैं इस तर्क के हक में नहीं हूँ कि अगर कानपुर और लखनऊ में पाबन्दी लग जायगी, तो हमसे हमारे यहाँ के किसान या भूमिहीन लोगों की कोई संतुष्टि होगी। आपकी आईस-क्रीम बन सकती है। क्योंकि बड़े लोगों की दावतों में वह सब की जाती है। कुल्फी बन सकती है, आईस क्रीम बन कर दिल्ली के बाहर जा सकती है और जा रही है, उस पर रोक नहीं है। दूध की फैक्ट्रियाँ हैं जो दूसरी चीजे उससे बनानी हैं चाहे फिर वे सहरानपुर हों या मुजफ्फरनगर में हों, मुरादाबाद में हों, भरतपुर में हों और चूक के बड़े उद्योगपति हैं इस वास्ते उन पर कोई पाबन्दी नहीं लग सकती है। छोटे-छोटे लोग जिनका दूध दिल्ली में नहीं आता है उन पर आप पाबन्दी लगा रहे हैं। कदा तक यह व्यवहारिक है इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अपने घर में कोई गाय पालता है तो वह क्यों खोया नहीं बना सकता है? जो पाबन्दी आपने लगाई है इससे बड़ा अज्ञान हो रहा है। पुलिस को पया देकर क्रिम भी बन रही है। खोया भी बन रहा है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और मुथर से वह दिल्ली हों कर बम्बई जा सकता है लेकिन

[श्री राम चन्द्र विक्रम]

दिल्ली में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। यह ममझ से बाहर की बात है। इस तरह में काम करके आपने पचास माठ हजार परिवारों की रोजी एक दम बन्द कर दी है चार महीने के लिए। आप सारी दिल्ली को दूध फिर भी नहीं दे सकते हैं। गैर सरकारी लोगों के मकाबले उनके बराबर आप उन लोगों को दूध भी नहीं देना चाहते हैं। अब उत्पादन करने वाला को कैसे प्रोत्साहन मिल सकता है। मिल्क स्कीम के अफसर चन्द इन गरीब लोगों का गला ही घोट देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मिल्क स्कीम की बात नहीं है। उत्पादन के गस्ते में जो अड़चने हैं उनको आपको दूर करना होगा। अष्टाचार के बोझ को भी समाप्त करना होगा। चूँकि ये चीजे मिल रही हैं इमलिये देश में आर्थिक क्रान्ति भी नहीं आ रही है। इस तरह की नीतियों को आपको बदलना होगा।

मैं यह चाहता हूँ कि किसान की फसल और उसके मवेशी का बीमा हो। यह नहीं हुआ है। कोई रूपरेखा इसके लिये तैयार आपने नहीं की है। चाभी याजना सम्पन्न हो गई है। पाचवी में तो आप हम चीज को कम में कम लागू करें। यह बहुत जरूरी है।

शोध कार्य चाहे कृषि संस्थाओं में हो या कृषि कालेजों में हो या फार्मों में हो उनके साथ आपको नजदीक के गावों को जोड़ देना चाहिए। इसमें शोध के प्रसार का जो काम है वह बहुत जल्दी गावों तक पत्रच जायगा और उन के ज्ञान से गाव वालों को लाभ होगा। और उससे देश की आर्थिक प्रगति होगी।

जो वर्कशाप खोले हुए हैं उन के साथ भी गांवों के किसानों का आपको सम्बन्ध जोड़ देना चाहिए।

जो घाटे के फार्म हैं या शोध कार्य हैं उनको आपको बन्द कर देना चाहिए। मैं अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि घाटे के कामों को बन्द करने की नीबत आती है तो वे मुनाफे में चलने लग जाते हैं। कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वे ममझते हैं कि उनकी राजी ता बनी हुई है और अगर वे घाटे में चलते हैं तो इससे उनको क्या फर्क पड़ता है लेकिन जब बन्द होने की बात होती है तो यह समस्या उनके सामने आती है कि उनका अब क्या होगा और तब वे मुनाफे में बदलने लग जाते हैं। अनेको उदाहरण इसके बारे में दिए जा सकते हैं। मैंने इनको अमल में लगाना था इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। कोई भी सरकारी काम घाटे में नहीं होना चाहिए।

एक बड़ी मांग है। कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग एक पुरानी मांग है। कृषि मंत्री ने इसके बारे में आश्वासन भी दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको अब शीघ्र पूरा करें।

भूमि के संरक्षण के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। पना नहीं हमारे देश के अर्थ शास्त्री और कृषि मंत्रालय में सम्बन्धित जो लोग हैं वे इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि किसानों की भूमि अर्जित करने का अधिकारी करने का जो तरीका है वह गलत है। दिल्ली या दूसरा कोई शहर ही उपजाऊ जमीन अर्जित कर ली

जाती है और वह जमीन खेती के काम में से निकल जाती है। फसल नहीं इसका भंडाबा बंधों नहीं लबाया जाता है। फिर जमीन ही नहीं निकलती है बल्कि किसानों की कठिनाइयां और परेशानियां भी बढ़नी हैं और सरकार जो ध्यानबासन बेती है उनको पूरा भी नहीं किया जाता है। इस और आप विशेष ध्यान हैं।

मौर्य जी ने बताया कि 53 करोड़ रुपया किसानों का मिल मालिकों की तरफ बकाया है। यह एक साल का है और गन्ने का मूल्य है। लेकिन ऐसी भी मिलें हैं जिन की तरफ किसानों का दो दो वर्ष का बकाया पड़ा हुआ है। क्या इसका मूद उनको मिलेगा? मिल मालिक तो गरीब नहीं हैं। किसान जो उधार लेता है, सरकारी ऋण लेता है, उनको अगर वह भदा नहीं कर पाता है तो मूद समेत उसके यहा कूड़की हो जाती है, मकेशी कूड़क कर लिए जाते हैं। लेकिन यहां किसान क्या करे। मैं चाहता हूँ कि मिल मालिकों से आप उनका पैसा उनको दिलवाए।

उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों ने गन्ने के बाब को रुपये विबटल कम कर दिए थे। मौर्य जी का मैं धाकतरी हूँ कि उन्होंने वहां और किसान और वह व्यवस्था की कि उनको सबा लेरह रुपये से कम बढ़ नहीं होने देंगे। यह जो उन्होंने वहां किसानों की मदद की है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

श्री शुकु की राज संजी (देहरादून) :
हमारे कृषि विभाग में तीन संजी है, जो

बहुत ही अनुभवही हैं, कर्मठ हैं, क्रियाशील हैं। उनके हाथ में यह महकमा है। तरकवी देश ने की है, काफी की है। इस में कोई सन्देह नहीं है। उनके अधीन किसानों से सम्बन्धित एग्रिकलचरल प्राइसिपल कमिशन भी है, एग्रिकलचर कमिशन भी है, कंसल्टेटिव कमेटी भी है। सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान की जो सही स्थिति है उसकी सही तसवीर हाउस के सामने बहुत कम आती है। किसान को कुलक कहा जाता है। लेकिन कभी किसी ने देखने या महसूस करने की कोशिश की है कि जमीन किस हिसाब से किसानों के पास है? सबा छः एकड़ से नीचे जिन के पास जमीन है वे सत्तर परसेंट किसान हैं। उसके बाद दस बारह एकड़ तक जमीन जिन के पास है वे 25 परसेंट होंगे। अब दो तीन परसेंट ही किसान ऐसे हैं जिनके पास इससे ज्यादा जमीन है। हमेशा कह दिया जाता है कि किसान तो कुलक है, किसान की इकोनॉमिक हालत अच्छी है, उनको बड़े जमींदार की तरह से बयान कर दिया जाता है। किसान कई तरह के हैं। वे हैं जो दिवाग में खेती करते हैं, किसानों में खेती करते हैं, काकजों में खेती करते हैं, वे भी हैं जो जमीन पर खेती करते हैं। अब जिन्होंने पढ़ लिख लिया, दिवाग लड़ाया, वैज्ञानिकों ने लड़ाया और आई सी ए प्रार जैसे जो महकमें है उन्होंने रिखर्च किया, अच्छे बीज निकाले अच्छे तरीके खेती के निकाले और जब उनकी व्यवहार में लाया गया तो किसान ने पैदावार को बढ़ाया। यह चीज तो

[श्री मूलकीराज सेनी]

जरूरी है ही लेकिन इसके साथ साथ में समझता हूँ कि इस क्षेत्र में हम को प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। जिन लोगों को खेती का तजुर्बा है और जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं उन में समन्वय स्थापित करके हमको खेती को तरक्की देनी चाहिये। समन्वित ढंग से इस काम को किया जाना चाहिये।

हमारे यहां मध्य श्रेणी के, छोटी श्रेणी के, बिना जमीन वाले, जिन के पास बैल हैं लेकिन जमीन नहीं है किसान हैं और उसके बाद खेत मजदूर हैं। इन खेत मजदूरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बारे में कभी कभी धम हो जाया करता है। मेरा नम्र निवेदन है कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि उस में गड़बड़ हो जाती है। आप कहते हैं कि 47 परसेंट कृषि मजदूर हैं गांवों में ऐसा हो गया है कि जिस किसी के साथ हरिजन शब्द लग गया उसको कृषि मजदूर कह दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिक्षा के प्रसार के साथ तथा रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध हो जाने के कारण उन में से बहुत से मिलों में काम करने लग गए हैं, बहुत से ट्रेड में आ गए हैं या दूसरे धंधे करने लग गए हैं। इस तरह से उनका व्यवसाय ही बदल गया है। मेरी राय में वे जो आंकड़े हैं वे गलत हैं, इन में गोलमाल है। इन में सही स्थिति का पता नहीं चलता है। असली किसान जो दो तीन प्रतिशत हैं उनको छोड़ कर शेष जो छोटे किसान हैं उनकी क्या आर्थिक स्थिति है इसको

आप देखें। आज के जमाने में कोई भी शान्त हवालात में जाना पसन्द नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों में से बहुत के हवालात में हैं। जिन्होंने कोओपरेटिव सोसाइटी से कर्जा लिया है, सरकार से कर्जा लिया है, साहूकार से कर्जा लिया है और एक बारीवाला होता है जिस की सूद की दर बहुत ऊंची होती है उससे कर्जा लिया है उन में से कई हवालात में है। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। कह दिया जाता है कि किसान की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। इसको सुन कर ताज्जुब होता है। एक बकील जो रोजाना पांच सौ रुपये एक एक मुकदमें में लेता है वह भी कहता है कि किसान की हालत बहुत बढ़िया है, एक डाक्टर जो मरीजों से एक एक हजार रुपया ले लेता है वह भी कहता है कि किसान की हालत बढ़िया हो गई है, किसान आज धनी हो गया है, उद्योगपति जो लाखों रुपया कमाता है वह भी वही कहता है। अब किसान की हालत का भंदावा इसी से लगाया जा सकता है कि पता लगाया जाए कि कितने किसान तहसीलों के अन्दर हवालात में इस बातसे बन्द कर दिए जाते हैं कि वे कर्ज की अवधि नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप किर्वाँ मंत्रालय जिलों से इसके बारे में और तब आपको पता चल जाएगा कि आज हजारों किसान हवालात में इसलिए बन्द पड़े हैं कि वे बीको का, सरकार का तथा दूसरों का पैसा नहीं दे पाए हैं। कौन आवनी है जिस की स्थिति अगर अच्छी ही तो वह हवालात में जाना चाहेगा ?

सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत किया जा सकता था और धाने भी बहुत करने को है लेकिन हमारे देश में एक रोटेशन व्यवस्था है। जब पैदावार अच्छी हो जाती है तो न छो उचित याम मिलते हैं और न ही दूसरी फेसिलिटीज मिलती है। इसका बर्तीजा यह होता है कि अगली बार किसान की उपज घट जाती है और कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। तब सरकार की निगाह उधर जाती है और दुबारा फिर वह किसानों को कुछ सहूलियतें देती है। फिर पैदावार कुछ बढ़ती है और फिर वही हालत हो जाती है कि उसको सुविधायें नहीं मिलती हैं, कीमत ठीक नहीं मिलती है और यह चक्कर चलता आ रहा है और सापरवाही होती रहती है। पांच छः साल में यह रोटेशन होता है, जिस में सरप्लस भी हो जाता है और डेफिसिट भी हो जाता है। इस सिलसिले में सरकार की कोई पालिसी नहीं है। उसको इस बारे में कोई पालिसी बनानी चाहिए।

हमारे यहां धान रेबोल्मन आया। देश आत्म-निर्भर हुआ और बहर से अनाज नमाना बन्द हुआ। लेकिन 1972-73 में सूखा पड़ा और फिर अकाल की स्थिति पैदा हुई। स्ट्राक कम होने से बाहर से अनाज नमाना पड़ा। 1973-74 में वर्षा फिर कुछ अच्छी हुई और उपज फिर बढ़ी। लेकिन आज हम कमी की स्थिति में से गुजर रहे हैं। सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, जिस से किसानों को वयक्त-सुविधायें मिलती रहे।

सुविधायों के बारे में आज क्या हालत है? सरकार और बैंक कर्ज देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व कृषि मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने किसानों की स्थिति को

सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कर्जा देने में छोटी सी सुविधा देना चाहती थी, लेकिन वह भी बैंकों ने रोक ली है। जिसको भारत के वित्त मंत्री भी देना चाहते हैं, वह भी बैंकों ने रोक ली है।

आज देश में अगर कोई सब से ज्यादा कम आमदनी वाला और दुबला व्यक्ति है, तो वह किसान है, या उपभोक्ता हैं। उन दोनों की गर्दन ध्यापारी के हाथ में है या सरकारी कर्मचारी और सरकारी अफसर के हाथ में है। आज ऐसी बुरी स्थिति हो गई है कि खेती बड़ी हो या छोटी, एक आदमी ऐसा उल्टा होना चाहिए, जो शहर में दफ्तरों की गमत लगाता रहे। अगर दस बीघे वाले किसान को भी खाद लेनी होगी, तो उसे पांच सौ बीघे वाले किसान की तरह शहर के चक्कर काटने पड़ेंगे। यह बात अलग है कि दस बीघे वाले को कम किलेगा और पांच सौ बीघे वाले को ज्यादा मिल जायेगा। खाद लेना ही या मिर्चाई के साधन बढ़ाने हों, खोन या बीज लेना ही, इन कामों को करने के लिए खेती पर एक आदमी फालतू होना चाहिए।

हम पिछले पच्चीस साल में किसानों की प्रोड्यूस के मार्केटिंग के लिए कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं। हम अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सके हैं कि किसान शहर में आ कर एक ही जगह से खाद, बीज, मिट्टी का तेल और डीजल आदि ले सकें। जहां किसान की प्रोड्यूस को लेने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उसको उचित मूल्य देना चाहिए, वहां कानज्यूमर गुडज और उसको खेती की उपज बढ़ाने की बाबा के बारे में ऐसी व्यवस्था धनी चाहिए कि होलसेलर कोई भी हो, लेकिन एक रिटेल डालर बाा दिया जायें, जहां से किसान को खाद, तेल और

[श्री मुल्की राज मैत्री]

बीज आदि सब चीजें मिल ज-यें और एक अलग आदमी को इसके लिए बार-बार न भागना पड़े।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी (हमीरपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रियों और हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कृषि के बारे में अच्छे मुझाव दिये हैं। यह ठीक है कि हमारे मंत्री लोग शलनी भी करते हैं। जो काम करना है, उस में शलनी भी होती है। लेकिन इस में मंत्रियों का क्या कुसूर है? आखिर हमारी विचार-धारा क्या है? हम क्या है? पूँजीवाद, साम्यवाद और गांधीवाद में से हम किस को मानते हैं? अगर हम पूँजीवाद है और पमरीका के पीछे चलना चाहते हैं, तो फिर श्री पीलू मोदी को मत्ता सौँ देनी चाहिए। अगर हम साम्यवादी हैं, तो श्री हीरेन मुकुर्जी या श्री ज्योतिर्मय बभु को मत्ता दे देनी चाहिए। तो फिर क्या हम गांधीवादी हैं? गांधीजी ने कहा था कि स्वराज्य होने के बाद एक कक्षम से गौहत्या बन्द हो जायेगी। क्यों न हुई? बिना गऊँओं के बिन कहीं से आयेंगे?

महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश में पचायती राज होगा। आज हमारी अदानतें—युवरीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि—कैसा न्याय करती हैं? हम देखते हैं कि मुट्ठी भर अनाज चुराने वाले या दो गन्ने तोड़ने वाले को नौ हकफडी लगा दी जाती है, लेकिन गन्त डंग से हजारों लाखों रुपये कमाने वाले पूँजीपतियों और व्यापारियों और अष्ट नरकारी अधिकारियों और मिनिस्ट्रों को हकफडी न लगाई जाती है। इस नीति को बदलना चाहिए। हम गांधीवाद पर चरना चाहिए। जमीन का बटवारा कायदे से होना चाहिए। लेकिन वह कहा हो पाया है? मैं देखता

हूँ कि गरीब आदिमियों के नाम जमीनों के पट्टे काले कोट पहनने वाले बकील डाकुओं द्वारा दाबे करा के खत्म कर दिये गये हैं। जिन लोगों की जमीनें हैं, वे खेतों पर काम करने वाले मजदूरों के साथ प्रत्याप कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो 'बा करेगा, वह खायेगा। ऐसा कहा हुआ है? इस में नीति का दोष है और इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

इस में सब जिम्मेदारी एम० पी० जी० की है। वे क्यों नहीं पार्टी में कहते हैं कि जो कुछ हम कहेंगे, वह पम होगा? आज ऐसा नहीं होता है। नेता लोग बैठ कर नय कर लेते हैं और हमारे पास आदेश आ जाते हैं। होता यह चाहिए कि हम पब्लिक की बात करें, हमारी बात कैबिनेट माने और कैबिनेट की बात प्रधान मंत्री मानें। आज उल्टा होता है। जो कुछ वे चाहते हैं, वह हम पर डूँसा जाता है। आज गरीब के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं।

गांधीजी ने कहा था कि शराब बन्द कर दी जाये। आज हमारे आदिमियों के मुँह से शराब की गंध आती है। शराब क्यों नहीं बन्द की जाती है? इसी तरह उम्माकू की पैदावार पर कानून रोक लगा देनी चाहिए, ताकि हम अधिक गस्ता पैदा कर सकें। फैंसी कपड़े को, जिस को हमारे लड़के-लड़कियाँ पहनते हैं, बन्द कर देना चाहिए। इसी तरह सिनेमा को खत्म कर देना चाहिए। टेम्पिजिन की भी कोई बन्दरत नहीं है। इन सब को बन्द कर के शराब खपा कृषि पर लक्ष्य करना चाहिए। पूँजीपति डाकुओं ने जो रुपया इकट्ठा कर रखा है, चाहे कोई अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, और चाहे इधर या उधर का कोई सवस्व हो, अगर उन्होंने अष्ट तरीके अपना कर रुपया कमाया है, तो उस सब रुपये को निकाल कर खेती में लगा देना चाहिए। हम लोग सँटल हाल में बैठ

कर बर्बाद करते हैं, रोते हैं। क्यों नहीं हम पार्टी में बैठकर यह सब करते हैं कि हम गांधीवादी हैं। अगर हम गांधीवादी नहीं हैं, और साम्यवादी हैं, तो श्री ज्योतिर्बाय बसु को प्रधान मंत्री बना देना चाहिए। अगर हम पूंजीवादी या अमरीकावादी हैं, तो श्री पीलू मोदी को प्रधान मंत्री बना दें। वह अमरीका की अच्छी वकालत करेंगे।

लेकिन मैं तो यह समझता हूँ कि हम लोग न पूंजीवादी हैं, न साम्यवादी या समाजवादी हैं और न गांधीवादी हैं। हम लोग तो कुर्सीवादी हैं। हम लोगों के दिमाग इन्हीं बातों में लगे रहते हैं कि बिहार में इनने मिनिस्टर पद दिये क्ये और इनने मिनिस्टर बना दिये गये, फलां को मिनिस्टर बना दिया गया, आदि। और कोई काम नहीं होता है। मेम्बरों का यह काम है कि वे नेता को कहें कि हमारी नीति गांधीवादी है और हम उस के अनुसार चलेंगे।

इस सदन में ज्यादातर उस वर्ग के लोग हैं, जो खेती नहीं करते हैं। मैं स्वयं किसान का लड़का हूँ। मैं 56 भाग से सन्यासी हूँ। मेरे महाविद्यालय में खेती होती है और एक कोसला है। मैं कैंस को नहीं छूता हूँ और अभी भी मांग कर खाता हूँ। यहाँ बहुत कम किसान होते हैं। कोई बनिया होगा। प्राये मे ज्यादा तो पंडित हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, जो भीख मांग कर खाते रहे हैं।

राज्य सभा को खत्म करना चाहिए। यह एक बलीबल्लना है। जो लोग हार जाते हैं, और यतीम हो जाते हैं, उन को उस में रखा जाता है। उस घर पैसा खर्च होता है। राज्य सभा में शक्ति नहीं हुई है। रोम जल रहा था और उस का राजा नीरो बंसी बजा रहा था वह हालत है। मैं यह कहता हूँ कि हम सारे मेम्बर और सारे विरोधी मिलकर, वे काहे के

विरोधी हैं, सब मिल कर किसानों को तैयार करें, किसानों की तरफकी करें और पूंजीवाद को खत्म करें, यह जो यतीमखाना बने हुए हैं इन को खत्म करें और नेताशाही को खत्म करें।

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to oppose the Budget demands of the Ministry of Agriculture Sir, today in our country we are faced with a crisis in particaly every sphere. There is crisis in our economy, in our industry and all these have resulted from the crisis in our agricultural sphere. As all are aware, over 70 per cent of our population live in villages and are dependent on agriculture. Unless there is an improvement in our agriculture and consequent improvement in the lives of the people living in the rural areas, there cannot be any progress in our country. But I regret to say that although we have completed our Fourth Five Year Plan, no improvement is noticeable in our country in the agricultural sphere. As the plans progress, we find that the number of agricultural labourers in the villages goes on increasing. Sir, we talk about land reforms. In some States like, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, West Bengal etc. Some legislation has been enacted in regard to land reforms. Though we do not consider those as much of a reform, we find that in spite of those legislation, the number of landless agricultural labourers in all these States are constantly on the increase. Sir, the Burdwan district is known as the granary of West Bengal. In 'Memari' thana of that district, where irrigation facilities are available and 3 crops are harvested every year, the statistics collected by the West Bengal Government show that the number of landless agricultural labour has gone up to almost 35 per cent in the course of the last 3 or 4 years.

[Shri Krishna Chandra Halder]

In 'Kanksa' thana of the same district, the number of landless labourers have outstripped the number of producers. We find that the people living in the villages are today faced with the severest crisis. There is food crisis after 26 years of independence due to the absolute failure of the Agricultural Ministry. Sir, while intervening in this debate the other day, Shri A. P. Shinde, hon. Minister of State furnished some figures and said that in the First Five Year Plan 65 million tons of foodgrains were produced. In the Second Five Year Plan the production went up to 75 million tons. In the third Plan the production was 81 million tons and in the Fourth Plan the production has gone upto 102 million tons. He has tried to impress that the production of foodgrains has gone up. But he did not mention what were the per-capita figure of consumption of foodgrains. He conveniently suppressed those figures because from that we will find that while the total production of foodgrains have gone up, the per capita allocation of food has continually declined.

Sir, I will not prolong my speech. I will only stress that the Government are depriving West Bengal in allocation of food. In the towns and villages of West Bengal the system of modified rationing has collapsed. In the city of Calcutta due steps are being issued by ration shops although the Government denied this. The people in the villages are starving. I visited 'Bankura' a few days ago. There I found that the villagers and 'Adivasas' are subsisting on the boiled leaves and roots of certain plants. Even the seeds of 'Shyao' grass which is used as fodder for the cattle is being eaten by them. A few days ago it was said by the Congress in West Bengal that nobody will be allowed to starve. Sir, in the issue of the 'Jugantar' paper dated the 21st April it has been published on be-

half of the West Bengal Congress that no body will starve. Two Ministers of West Bengal Government own this paper. They are Shri Prafulla Kanti Ghosh, Food Minister, and Shri Tarun Kanti Ghosh, Minister for Industries. But, Sir, in the issue of the same 'Jugantar' paper dated the 22nd April, news reports appeared under the caption 'Death by starvation'—'Young children sold and suicides committed' driven by want. This is the condition prevailing in West Bengal. I will not go into the details of these news reports I will only caution the Agriculture Minister and the Central Government that today early in the month of 'Vaisakh' rice is selling at Rs. 4/- or 4.50 a Kg. in Burdwan, Durgapur etc. The people of West Bengal will not stare helplessly if the Government pushes them towards starvation. Already the people of Gujarat, Bihar etc. have started struggle and have risen in revolt. The people of West Bengal will not lag behind if they are deprived of their legitimate share of food. The combined wrath of the deprived people will burst upon the Government and teach them the right lesson. I will warn the Government to take heed while yet there is time. With that Sir, I oppose the demands of the Agriculture Ministry and conclude my speech.

श्री जगताराम मनहर (जंजगीर) :

उपाध्यक्ष महोदय, हव सब कृषकों की बलाई की बातें तो करते हैं पर उन का जोषण रोक सकने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। आज देश में सब से ज्यादा जोषण उन्हीं का हो रहा है। उन की मेहनत की उचित कीमत उन्हें नहीं मिल रही है। घास कृषि में काम आने वाली बीजों की कीमतें अत्यन्त खू रही हैं। वे बी समय पर नहीं मिलती हैं। बीज, खाद, खाकी, कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, हल, बैल और अन्य उपकरणों की कीमतें कई गुना ज्यादा

हो गई हैं। इस से एक साधारण कृषक की मुख्यतः खेती पर निर्भर है की आमदानी दो से ठाई रुपये प्रति दिन है। वहीं पर एक साधारण मजदूर भी कम से कम 5—7 रुपये प्रति दिन मजदूरी पाता है। इस पर भी भाए दिन मजदूर, इंजीनियर, डाक्टर, एवं अन्य शासकीय प्रशासकीय कर्मचारिगणजो कृषकों से काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं वेतन भत्ता बोनस एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग में हड़ताल करते रहते हैं। संगठित होने से सरकार उन की मांगों को मान भी लेती है। उन्हें वेतन भी अधिक मिलना चाहिए तथा दूसरी ओर सस्ती कीमत में अनाज एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। मैं से तुलनात्मक दृष्टि से यह विचार रखा है किसी गलत भावना से नहीं।

इस तरह देखा जाय तो 80 फीसदी कृषकों को उन के उत्पादन की जो कीमत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। कृषकों से अनाज सस्ती कीमत में खरीदा जाता है तथा उन्हें स्वतः आवश्यकता पड़ने पर खोड़ी दुगुनी कीमत पर बेचा जाता है। इस प्रकार शासन कृषकों का संगठित हो कर अपनी मांगें रखने के लिए बाध्य रहा है। समय रहते शासन कृषकों की उक्त समस्याओं का हल करे अन्यथा उत्पादन पर उलटा असर पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में 70 प्रतिशत जोतें 10 एकड़ या उस से कम क्षेत्र की हैं। आबादी का 84 प्रतिशत कृषि पर आधारीत है। मध्य प्रदेश शासन ने भूमि सीमा बंदी नियम बनाया है, जिस में 5 आनाक एकड़ रखा है। प्रार्थना-सिंचित 10 एकड़ तथा अर्धसिंचित 15 एकड़ है। वह भूमि का मापदण्ड है। मैं शासन से धनना चाहता हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ के 5 आनाक एकड़ मालवा या हवेली क्षेत्र के 5 आनाक एकड़ की बराबरी कर सकता है? क्या बिना जमीन के उपजाऊपने की जांच के

सीमाबन्दी नियम बनाया जा सकता है—यह अनुचित है। दूसरी ओर शहरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी अभी तक लागू न कर सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

मैं छत्तीसगढ़ के काश्तकारों की ओर से छत्तीसगढ़ के 10 स्टैंडर्ड एकड़ के बदले या हवेली क्षेत्र के 5 एकड़ लेने का आकर देता हूँ। क्या वहाँ के काश्तकार इस तरह का बदला मंजूर करेंगे—मैं समझता हूँ कि वे अभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उपज एवं कृषि की अन्य दृष्टियों से पहाड़ी क्षेत्र एवं कछोरी क्षेत्र में कोई फर्क नहीं रखा गया है—जो कि छत्तीसगढ़वालों के साथ बोर अन्याय है।

दूसरी ओर शासन ने भूमिहीन बन्दी कानून को तो बनाया, लेकिन चकबन्दी के लिये कोई कानून नहीं बनाया। जैसा कि मैंने पहले बतलाया था—अधिकार, कृषक 10 एकड़ से कम करते के हैं, उन की जमीन 20 टुकड़ों में बँट-बँटती जगहों में है। वे अपनी खेती की तरक्की करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। उसे कंधा खुदवाने, पम्प लगाने के लिये विद्यार्थित तीन एकड़ का षक रखना आवश्यक है, जोकि उस के पास नहीं है। अतः वह शासकीय सहायता का उपयोग नहीं कर सकता। आज की आधुनिक पद्धतियाँ अपनाएने की प्रबल इच्छा रखते हुए भी वह उस से वंचित रह जाता है। आज वह अपने खेत में इन्टेन्सिव कल्टीवेशन नहीं कर सकता तथा न ही निष्पन्न कामिया कर सकता है, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध के पशु पालन नहीं कर सकता, बहु-फलती काँबेकड नहीं अपना सकता। अतः भूमि सीमा लागू करने के पूर्व चकबन्दी की अग्नि-बाँध किया जाना चाहिये जो कि कृषि की उपज बढ़ाने की दिशा में प्रथम चरण है।

उत्त. प्र. ग. में श्री. रा. क. शा. एच. न. न. स्टेट कर्मचारिगण का पोरिशन यत्नायत की कठिनाइयों के कारण विशेष विलक्षणी नहीं

[श्री ब्रज राम मनहर]

केते हैं, जब कि मान काफ़ी है तथा व्यापार की सुवाहक भी है। फलस्वरूप यह देखा गया है कि धान के क्षेत्र में आबन्धकतानुसार निजी सूत्रों से खाद उपलब्ध नहीं होता है और खाद के लिये पूर्णतः पूरा व्यवस्था पर ही निर्भर रहना पड़ता है जोकि सहकारिता के माध्यम से वितरित होती है। अतः नगद खरीदनेवाले खाद से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार सहकारिता विभाग का एकाधिकार होने से कृषकों को समय पर खाद नहीं मिलता तथा उस के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा डबोडा और दुगना दाम देना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ में कोयले का झूट भण्डार है। उस को एवं खाद की बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए शासन से मेरा अनुरोध है कि कोयला की तरह कोयला पर आधारित दूसरा फर्टिलाइजर प्लांट सरबुजा में भी शुरू करें ताकि छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश की रसायनिक खाद की आवश्यकता की पूर्ति कुछ मात्र में ही हो सके।

हमारे कृषि वैज्ञानिक ने अधिक पैदावार देनेवाली नई किस्मों का आबिष्कार कर हरित क्रान्ति में योगदान दे कर कृषि विभाग को इतने से बचाया है, इस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। उन के प्रयासों से ही अधिक फसल पैदा करने में हम कुछ सफलता प्राप्त कर सके हैं। इस में सन्देह नहीं कि पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन उन के मुँह (क्वालिटी), जैसे उस की सुगन्ध, मिश्रण क्वालिटी, खाद, इत्यादि में काफ़ी अन्तर आ गया है। कृषि वैज्ञानिकों से मेरा अनुरोध है कि इस विद्या में प्रयास करें कि फसलों की इस प्रकार की क्वालिटी कायम रहे।

मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में आधिक्य वाला प्रदेश है। 70,414 घण्टा मध्य प्रदेश में है, उन में से 31-12-73 तक 10,278

घण्टा में विद्युतिकरण किया गया है, जो 14.6 प्रतिशत है। इस के विपरीत सारे देश का औसत 26.2 प्रतिशत है। मेरा मतलब यह है कि अपने घर में झन्डोरा है जब कि हम दूसरे प्रान्तों को बिजली दे रहे हैं—ग्रामीण उत्पादन के प्रति मध्य प्रदेश शासन कितना जागरूक है, यह उस का उदाहरण है। आप इसके दूसरे पहलू को भी देखिये—कृषक को खेती के लिये 37 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है, जब कि औद्योगिक संस्थानों को, पूंजीपतियों को 5.3 पैसे से 9 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है। मेरा शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामों का विद्युतिकरण कर कृषकों को राहत प्रदान करने में।

श्री बशोश्वरनाथ शर्मा (प्रजपेठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत म.रा. 77 मसंधन करता हूँ। कृषि मंत्रालय के अधीन कुछ क्षेत्रों में कमियां व कमजोरियां होने के कारण भी हम बाजार में इन्कार नहीं किया जा सकता कि कई क्षेत्रों में हुई प्रगति और उपलब्धियां महत्त्वपूर्ण हैं, जिन पर देश को गर्व है।

मेरे पालन नीतिन समय होने के कारण मैं कृषि मंत्री जी का 57 वें आप के मसंधन में अपने-अपने विषय में मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में यदि हम ने समय रहते प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं की तो हमारे प्रशासनिक ढांचे को बमबारी जैसा उत्पन्न हो जायगा तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता की आस्था समाप्त हो जायगी। हमारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों को भी अच्छे नहीं लगेगा, यदि उन को क्रियान्वित हो सके, कुटिल और निहित स्वार्थों से प्रेरित है तो हमारी उपलब्धियां मसंधन को, विशेषकर गरीब तबके को, कभी प्रेरित नहीं कर सकेगी। हमारे देश की महान जनता जिस ने पिछले पांच साल चुतारा में प्रजापन्थ में विषयगत

श्रीर आस्था प्रकट की है, हमारे देश की जनता अपनी अकांक्षाओं और भावनाओं की पूर्ति के हेतु प्रगतिवादी ढंग से हमारे देश के वास्तविक और सामाजिक ढांचे को परिवर्तित करने का इच्छुक है। हमारे देश के महान नेताओं और संविधान के निर्माताओं ने प्रारम्भ से यह महसूस किया कि लोकतन्त्र की सुरक्षा के हेतु हमें सत्ता का निर्भीकता के साथ विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 40 में प्राप देखें—राज्य सरकारों को और केन्द्रीय सरकार को पंचायतों का संगठन करने के लिये प्रयत्न करने के लिये प्रेरित किया गया है। इस के साथ ही यह आदेश भी दिये गये हैं कि वे उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करें। यह बात ठीक है कि हमारी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को केवल मार्ग-दर्शन दे सकती है। मगर साथ ही साथ उन को यह भी महसूस करना चाहिये कि जितनी भी शीघ्रता से सत्ता का हम विकेन्द्रीकरण कर सकेंगे लोकतन्त्र को सुदृढ़ करने हेतु उतना ही मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे देश के महान नेताओं ने जो मकल्प लिया, उस के अनुरूप हम ने 1959 में बड़े उत्साह से पंचायत राज्य का उद्घाटन किया, अपनी शक्ति के लोकतान्त्रिक ढंग से हस्तांतरित करने का निश्चय किया। लेकिन जितनी सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना है, वह राज्यों की सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना है, अब हम पंगु के रूप में केवल मार्ग-दर्शन दे रहे तो वह विकेन्द्रीकरण कभी भी नहीं हो पायेगा।

आप ने देखा कि बड़े उत्साह के साथ 1959 में इस का प्रारम्भ किया गया, लेकिन शनैः शनैः उस का वह स्वरूप, जिस ढंग से हम अपनी उपसभ्यता करना चाहते थे, नहीं बन सका। यह निश्चित बात है कि जब तक हम संविधान के अन्दर परिवर्तन

और संशोधन नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हमारे संविधान के अन्दर, जो हमारा संघ है, उस के अधिकार अक्षेप्य है, जो हमारी राज्य सरकारें है उन के अधिकार अक्षेप्य है, उसी प्रकार में पंचायत राज्य की जितनी भी संस्थायें हैं, उनके मन्त्र में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इस प्रकार की धारयें उस में डालनी होंगी जिस में हम राज्य सरकारों को निर्देश दे सकें, वास्तविक रूप से कि वे अपने प्राप इस प्रजातान्त्रिक ढांचे को कायम रखने के लिये इस प्रकार की सत्ता हस्तांतरित करें, जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि हम लोकतन्त्र को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। आज जितनी भी योजनायें हैं, उन के अन्दर हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक भागीदार बने, लेकिन उस को भागीदार बनाने के लिये हमें सत्ता का निम्न स्तर तक चुने हुए प्रतिनिधियों में विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, उस को वास्तव में भागीदार बनाना होगा।

श्री मन्त्री मन्त्री स्वामी जी ने अपने विचार सदन के सामने रखे थे—कुछ माननीय सदस्य हम रहे थे, कुछ उन की मराहना कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे देश के प्रत्येक नागरिक की भावनाओं को सदन के सामने रख रहे थे। हम ने इतनी योजनायें बनाई, लेकिन वे कार्यान्वित नहीं होनी पाईं, उन में क्या दोष है, क्या त्रुटिया हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि हम जनता को अभी तक उसमें भागीदार नहीं बना सके। हम केवल अकसरशाही पर आधारित हैं। हमारी योजनायें और भावनायें बहुत अच्छी हैं। मैं मन्त्री मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इस समय प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाये तो बड़ी गम्भीर परिस्थिति पैदा हो सकती है। हर साल हमारे राज्यों के मंत्रियों की मीटिंग होती है और हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पंचायतों का

[श्री बलेश्वर नाथ भागंब]

हमने जाल बिछा दिया है। केवल बिहार में कुछ जगह और नागालैण्ड में कुछ जगह नहीं है लेकिन मैं वास्तव में यह कहना चाहता हूँ कि कई राज्यों में पंचायती राज मस्यौदा को चुनाव कितने वर्षों तक नहीं हुआ, आज अगर आप सोचें कि राज्य सरकारों का, विधान सभाओं का चुनाव न हो तो जनता का प्रजातंत्र में किम प्रकार की आस्था रहेगी? उसी प्रकार से हमें यह भी निर्णय करना चाहिए कि हम पंचायती राज संस्थाओं के ऐसे ढांचे को बनायें, हमारी एक अलग सूची हो जिसमें उनके अधिकारों का वर्णन दिया हो और उनके चुनावों की व्यवस्था हम निर्वाचन आयोग के द्वारा करवायें। जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका ही यह दायित्व हो कि वह ग्राम पंचायतों का निर्वाचन, रक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ इस ढांचे को हम एक अच्छा ढांचा बना सकेंगे। उसका दायित्व हमें निर्वाचन आयोग को देना चाहिए ताकि चुनाव समय पर हो सके और लोगो की आज जो आस्था पंचायतराज के प्रति है वह समाप्त न हो। यह हो सकता है कि राज्य सरकारें संकुचित दृष्टिकोण के कारण चुनाव नहीं कर पाती या दूसरी चीजें हैं कि अपने आप को मत्ता में बनाये रखने के लिए या उनको जिस प्रकार से उचित और ठीक लगे उसका उपभोग करनी हैं।

इसके प्रतिरिक्त मैं कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात पर भी दिलना चाहूंगा कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अधीन कुछ योजनायें उन्होंने चलाई जैसे कृषि, सीमान्त एवं भूमिहीन तथा लघु कृषक योजनायें हैं जो हमारे कृषकों में लघु सीमान्त और खेतिहर भजदूर हैं या हमारे राज्यों के जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन मैं उन का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन योजनाओं के द्वारा वास्तव में

इन कृषकों को जितना लाभ पहुंचाना चाहिये नहीं पहुंच रहा है। अभी अभी कृषि मन्त्री 21 अप्रैल को अजमेर गए थे और उन्होंने वहां पर सीमान्त और भूमिहीन अधिकरण के अधीन कार्यरत कुछ अधिकारियों को पारितोषिक भी वितरित किया लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर के अन्दर जो सीमान्त कृषकों की योजना चल रही है उसमें तीन वर्ष की अवधि में केवल 59 लाख का व्यय किया गया है जिसके लिए उन्होंने स्वयं निराशा व्यक्त की लेकिन इस योजना के अन्तर्गत सीमान्त कृषकों और भूमिहीनों के लिए करीब आठ लाख रुपया खर्चा हुआ और बाकी लगभग महानगरीय और सहयोग हमारी एजेंसियों को है। उन अधिकरण पर प्रशासनिक व्यय 4 5 लाख रुपया हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ यदि वास्तव में हम चाहते हैं हमारी योजनाएँ मफल हों तो हम जनता को आह्वान करें और उनकी उम्में भागीदार बनायें। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

श्री लालबी नारई (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृषि मंत्रालय के अनुदानों पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कांग्रेस पार्टी को इस देश में शासन करते 25 साल हो गए, इन 25 सालों में किसानों के सामने क्या क्या विकास की बातें आईं, क्या क्या नुकसान की बातें आईं और क्या क्या समस्याएँ उनके सामने आईं। सबसे पहली समस्या किसान के सामने मंहगाई की है। आज मंहगाई जितनी बढ़ गई है उसकी कोई सीमा नहीं। आज प्रत्येक खाद्यान्न, वस्त्र, चम

जी, मक्की तथा अन्य जिलानी जीवनोपयोगी वस्तुयें हैं वे इतनी मंहगी हो गई हैं कि प्रत्येक किसान उनको खरीद नहीं सकता है। तो सबसे पहली समस्या मंहवाई की है जिसके कारण वह जीवनोपयोगी वस्तुयें खरीद नहीं सकता है। किसान किसी प्रकार से इन भयंकर मंहवाई का सामना कर सकता है, कर रहा है लेकिन इस मंहवाई के प्रतिरिक्त उसके सामने दूसरी समस्यायें आ गईं। उसके सामने दूसरी समस्या जो है वह है अभाव की समस्या। अभाव के कारण उसको खाद्यान्न मिन नहीं सकता है, दूसरी जीवनोपयोगी वस्तुयें उसको मिल नहीं सकती हैं क्योंकि वह उपलब्ध नहीं हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभाव की समस्या, चीजों के उपलब्ध न होने की समस्या से बढ़कर और कौन सी समस्या हो सकती है। इस प्रकार से पहली समस्या तो मंहवाई की है, दूसरी समस्या अभाव की है। ऐसी स्थिति में यदि उसको कहीं से कुछ चीजें मिल भी रही हैं जैसे गेहू, कोयला, तेल, कपड़ा तो वह बड़ी मुश्किल से मिल रही है। इसके साथ साथ उसके सामने एक तीसरी समस्या आ रही है और वह समस्या है मिलावट की। आज देश में मिलावट के जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े उनके अनुसार जनवरी से नवम्बर तक की अवधि में 4087 मामले मिलावट के हुए हैं जिनमें धानक मामलों की संख्या 1063 है और साधारण मामलों की संख्या 3024 है। इस प्रकार से तीसरी प्रब्लम हमारे सामने आ रही है मिलावट की।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐं कौन से कदम उठाये गए हैं जिनसे पहले तो मंहवाई को रोक जा मके और दूसरे जो अभाव हैं, जीवनोपयोगी वस्तुयें नहीं मिलती हैं जैसे कोयला, पानी बिजली, तेल आदि कृषि सम्बन्धी जो चीजें हैं उनका अभाव न हो उसके लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। इसके उपरान्त जो मिलावट की समस्या है उसके लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। खाद्यान्न खाकर भ्रगर लोग बीमार पड जाते हैं तो यह आशा करते हैं कि हास्पिटल में उनकी दवाई होगी और दवाई होने से हम जिन्दा रह मकेगे लेकिन उनके बजाय सारे देश में आजकल अखबारों में यह आ रहा है कि ग्लूकोज के एम्बे इंजेक्शन लग रहे हैं जिनसे लोगो की मृत्यु हो रही है। इस प्रकार से दवाइयों पर भी लोगो को जो आशा थी वह भी समाप्त हो रही है। तो इसमें बढ़कर आज दूसरी और कौन सी प्रब्लम हो सकती है। मैं जानना चाहता हूँ इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। राज्यों की सरकारो ने तथा केन्द्र की सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाए हैं ?

14.54 hrs.

[SRI DINESH CHANDRA GOSWAMI in the Chair]

इसके साथ ही आज एक बड़ी प्रब्लम यह है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि नहीं मिल रही है। आज अधिकांश राज्य सरकारें भूमिहीनो को भूमि देने में विफल हो गई है। इसका कारण यह है कि जो बड़े बड़े किसान हैं उनका अधिकांश सरकारों पर दबन है जिसकी वजह से सरकारों

[श्री लाल जी धार्ड]

भूमिहीनों को भूमि नहीं दे रही है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि अधिकांश राज्यों में अतिक्रमण के मुकदमे चल रहे हैं। उसमें यह हो रहा है कि एक भूमिहीन जिमने नाजायज़ कब्जा कर रखा है उससे प्रति वर्ष एक बीघे पर 500 रुपया वसूल किया जा रहा है। यद्यपि सरकार ने उसका सारता निकाल रखा है, उनको एलाटमेंट करना या रेग्युलराइ करना— यह दो रास्ते हैं लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ऐसी हालत में एक गरीब भूमिहीन किसान से एक बीघे 'र' प्रति वर्ष 500 रुपया वसूल करना उसका कत्ल करने के समान है। इसके कारण उनमें बड़ा रोष फैल रहा है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के अतिक्रमण के मुकदमों का फ़ैसला करके वह भूमि उनको दी जाये। इसके अलावा जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, उसका सरकार बहाना लेती है लेकिन किसानों की मुसंबतों को सुलझाती नहीं है। और साथ ही साथ जंगलों को खत्म किया जा रहा है, उन को सतत ढंग से काटा जा रहा है जिस से होता यह है कि अधिकांश मैदान रेगिस्तान हो रहे हैं और वर्षा नहीं होती। तो सरकार कृषि के सम्बन्ध में ऐसे अनुसन्धान कार्य करे जिस से अधिक से अधिक शमीन भूमिहीनों को मिल सके और उन पर खेती हो सके।

15.54 hrs.

जितने भी हमारे बिजली पैदा करने के मृतासिक राज्यों में छोटे छोटे पिकनिक ज़ाब्र हैं उन पर जोर दिया जाय जिस से अधिक से अधिक बिजली पैदा हो सके और किसानों को लाभ पहुँचे।

श्री मानेश्वर द्विवेदी (मछलीसहर) :
सभापति जी, कृषि की ओर यदि स्वतंत्रता के बाद तुरन्त ही सन्तुष्टि रूप से ध्यान दिया गया होता तो आज देश में जो इतनी परेशानी की परिस्थिति पैदा हुई है और चारों तरफ़ वाहि वाहि मशी हुई है वह सम्भवतः न होती। उस समय अरबों ६0 का गल्ला विदेशों से मंगाया जा रहा था और खेती की तरफ़ इस तरह ध्यान न दिया गया कि हम अपने पैर पर खड़े होते। अरब 1965 का पाकिस्तान का युद्ध न होता और अमरीकी ने गल्ला देना बन्द न कर दिया होता तो हमारा ध्यान खेती की तरफ़ जाता भी नहीं। हल्के हल्के हाथों हम खेती का काम देखते। संयोग हुआ कि जब अमरीका ने हमें गल्ला देने से मना किया उस के बाद हमारा ध्यान गया और तत्काल प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा बिधा और देश ने निगाह डाली। उन्होंने वे एक बात उन संकट के समय यह भी कही थी कि सप्ताह में एक दिन लोग उपवास करें। लेकिन वे भी हालत बोड़े ही दिनों तक रही आज हालत ऐसी हो गई है कि उपवास की बात तो कोई सोचता ही नहीं, अरब कोई उपवास करता है तो दकियानूसी बात ममझी जाती है। लेकिन इसके पीछे अरब इस पर ही ध्यान दिया जाता हर सानप्रदाय में, हर धर्म में उपवास करने का नियम है, अरब नियमानुकूल ही उपवास करते तो भी हमारे देश की गल्ले की समस्या में बहुत कुछ सहयोग मिलता। लेकिन वह बात भी नहीं हुई। आज भी उन तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

खेती के साथ लगा हुआ पशुपालन का काम है, फल उद्यान का काम है। बड़ी तेजी से आजादी के बाद बाघ बनीचे कटे खलाने की लकड़ी के लिये और इमारती लकड़ी के लिये। उस का भी कृषि पर

बहुत बुरा भ्रसर पड़ा। पुराने जमाने में हर गाँव में पशुओं के चराने के लिये चरागाह होते थे, लेकिन उन चरागाहों की सरकारी कागज़ों में कोई गैट्टी नहीं होती थी परिणाम हुआ कि बड़ी बुरी तरह चरागाह टूट गईं। आज पशुधन पर एक बड़ी क्षीणता आयी है। गाय, बैल, भेड़, बकरी का पालन करना मुश्किल हो गया है, और इनका न पालन करने से हमारी कृषि पर बड़ा बुरा भ्रम पड़ा है।

दूध, घी के अभाव में जहाँ अन्न पर बोझ पड़ा, वहाँ पर खेती की कमी हुई और उससे पैदावार में कमी आयी। इस तरह अन्न बढ़ावा देना चाहते हैं तो आज इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि हर गाँव में जहाँ खेती के लिये जो दिया जाय, खेती के लिये जमीन छोड़ी जाय, वहाँ सामूहिक चरागाह के लिये जमीन छोड़ी जानी चाहिये। जहाँ जंगल और बगीचे लगाये जाते थे वहाँ उनसे जमीन का कटाव सकता था, फल और लकड़ी मिलती थी। जो इस बुरी तरह से जंगल बाग बगीचे कटे उससे खेत कट रहे हैं, वर्षा में मिट्टी कट रही है। इससे जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो रही है, पैदावार पर बुरा भ्रसर पड़ता है।

हमको स्वाभाविक खाद नहीं मिल रही है। उर्वरक खाद के लिये पहले तो प्रोत्साहन दिया गया, लोगों ने आजमाइश की सस्ते दामों पर। हमारे लोग जब उसका लाभ देखने लगे तो आज उसकी भी कमी हो गई है और जो कुछ सुलभ भी है वह ब्लैक मार्केट में इस तरह से मिल रही है कि वास्तव में उसकी जिनको जरूरत है वह तो नहीं पाते हैं बल्कि ब्लैक मार्केटियर्स उसके परमिट बनवा कर मुनाफ़ा कमा रहे हैं और उसका गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

कृषि बुनियादी चीज़ है। अगर कृषि ठीक नहीं रहती है तो दूसरे उद्योग-धंधे ठीक से नहीं चल पायेंगे। लेकिन कृषि को बुनियादी आज तक नहीं माना जा रहा है और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन जब कृषि का मामला डाबाडोल होता है तो सारे उद्योगधंधे डगमगा जाते हैं। इन्हीं देश के लोगों का अधिक में अधिक बोझा भी कृषि पर है, इस पर अधिक लोगों का जीवन निर्भर है, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे मजदूर के रूप में और चाहे व्यापारी के रूप में, चाहे कुछ लोग उनका वकालत करके अपना भरणपोषण करते हैं। लेकिन ज्यादा में ज्यादा जोर खेती पर है। और उसकी जो उपेक्षा की जाती है सरकार को उसी मात्रा में ध्यान देना चाहिये जितने उस पर लोग निर्भर हैं।

खेतों के साथ साथ अन्न कम करना है तो औद्योगिक क्षेत्र में, शक्ति क्षेत्र में। सहकारिता का एक बड़ा भारी आन्दोलन चलाया गया था। अन्न हम अन्नितगठ व्यापारियों का हठाना चाहते हैं, शक्ति सुझार लाना चाहते हैं, हम सामूहिक रूप में लोगों में तककी पैदा करना चाहते हैं तो सहकारिता का काम बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको भी बाये हाथ से देखा जा रहा है। इस पर उतना पूरा जोर नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि सहकारिता के काम में उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना उसमें अष्टाचार पैदा हो गया है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अष्टाचार को देख कर इसको उद्योग की जय यह देश के लिये हितकर नहीं होगा, गाँव के लिये ममता के लिये हितकर नहीं होगा। इन सहकारी समितियों का जन्म गाँव गाँव में चाँद उपभोक्ता सहकारी समितियों के रूप में ही चाहे क्रम देने वाला हो, चाहे पशुधन का पालन करने वाली सोम इटीव हो, इनका अधिक में अधिक निर्माण करना चाहिये, शक्ति में शक्ति इनके माध्यम से औद्योगिक

(श्री नागेश्वर द्विवेदी)

श्रीय आर्थिक कामों का संवर्धन करना चाहिये। अगर गांव-गांव में मजदूरी मर्मितियां बन जायें और उन की मरकत करने का लेने देने शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि वहां कुछ कठिनाईयां जो व्याप्तियों की वजह से पैदा होती हैं वह खत्म हो जायें। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान दे। अगर मजदूर करने को आप लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो किमान जो गन्ना पैदा करता है उससे राजस्वों की जांच सूची की जाय वह करने के रूप में लो जाय। इस तरह से आसानी होगी और यह मामला आसानी से सुलझ जायगा। मैं समझता हूँ इस में ज्यादा कठिनाई नहीं आयेगी।

एक वन मन्त्रीय भागव जी ने कही हमारे शासन के विकेन्द्रीकरण की, और उस के लिये पंचायतों के बनाने की बात हमारे संविधान में रखी गई है। लेकिन आज पंचायतों के काम की भी पूरी उपेक्षा की जा रही। प्रान्त वाले केन्द्र में तो अधिकार मांगते हैं, लेकिन केन्द्र वाले अपने अधिकार जिला परिषदों को, विकास क्षेत्रों को और गांव पंचायतों को नहीं देना चाहते। यह गांव पंचायतों देश के शासन की रीढ़ है। अगर उन के ऊपर आप विश्वास कर के काम करेंगे तो काम अच्छी तरह से चलेगा। आप ऊपर ऊपर से इंतजाम नहीं कर पाएंगे पंचायतों को आप को विश्वास में लेना पड़ेगा। यदि शासन जो मजदूर करना चाहते हैं, देश को मजदूर करना चाहते हैं, तो इन पंचायतों को जितना मजदूर बनाना सके उतना ही अच्छा होगा। यह देशकी रीढ़ और इन्हीं के बल पर शासन अच्छी तरह से चल सकता है। प्रबन्ध अच्छे से हो सकता है और हमारी जो आज की कठिनाईयां हैं वह हन हो सकती हैं। हम इन के द्वारा बेरोजगारी को समाप्त भी हो कर सकते हैं। अ टाचार का भी दूर कर सकते हैं। हमारी मारी

उसके उस तरफ जानी चाहिये। अगर हमने गांव पंचायतों की उपेक्षा की तो किसी दिन शासन प्रबन्ध में हमारी वहीं स्थिति होगी जो खेती की उपेक्षा करने से राजनीतिक क्षेत्र में हो गई है।

इन अवश्यों के साथ मैं इन अनुरोधों का समर्थन करता हूँ।

• SHRI S. N. SINGH DEO (Bankura): Mr. Chairman, Sir., I rise to support the Demands for Grants as have been placed before the House by the hon. Minister. It is needless for me to say that agriculture is the backbone of our nation as 70 per cent of our population is dependent on agriculture for their living. So, if we want to make any progress or development in our national life, then agriculture should be given first priority compared to any other subject.

But I am sorry to note that the outlay on agriculture has been reduced. If we take into account the comparative figures of the total plan outlay, we will find that in the fourth Plan while 35 per cent was set apart for agriculture, now, in the fifth five year Plan, it has been reduced to 33 per cent. This should not have been done. In the fifth Plan, more funds should have been allocated for the development of agriculture, because we have seen how our Green Revolution of which we boast so much, has gradually faded out as a result of two consecutive droughts followed by floods in some of our States. And now we are facing a grim situation due to acute shortage of food in our country. Now we have reached such a situation that if we cannot feed our evergrowing population, and if we cannot grow more, then we will have to starve.

MR. CHAIRMAN: Mr. Singh Deo, you are not audible to the interpreters. So, please come forward and speak.

SHRI S. N. SINGH DEO: So, if we want to avoid such an ugly situation, then proper and adequate arrangements should be made for the augmentation of food in our country. But I am sorry I do not find any proper co-ordination between one department of Government with the other. I do not know how the desired target of food production could ever be achieved under such circumstances.

Since the time allowed to me is very short, I will confine myself to the problems of agriculture in West Bengal and also the food situation there. You know as a result of partition of Bengal and the formation of East Pakistan, now Bangladesh the total area of West Bengal has been reduced to one-third. Over and above, nearly a crores of people from East Pakistan, now Bangladesh, have come here and permanently settled down in our State of West Bengal. Besides this, about one-third of its total agricultural land is now devoted to the growing of jute and tea which are both big foreign exchange earning items for our country. All these factors have resulted in reducing our State into a deficit State so far as food and agriculture is concerned. I therefore request the hon. Minister of Agriculture to take note of all these factors and provide more food and funds for the agricultural development of our State and make it self-sufficient in food.

Coming to the problem of food and agriculture in the two districts of Purulia and Bankura from where I actually come, I might say that these two districts are chronic drought-affected areas and are mostly inhabited by poor peasants and labourers. Whenever there is irregular or less rainfall the poor people are in grave distress. They are to depend on gratuitous relief and test relief by the Government for which every year crores of rupees are spent to provide them with temporary work for their living. But it is not a healthy practice. I am sorry that in spite of our repeat-

ed requests, nothing of a permanent nature has been done to solve this problem there.

In this connection, I might suggest that there are innumerable rivulets and 'nallas' in this area, and if embankments are constructed over them and rainwater is collected for irrigation purposes then the food problem could be solved to some extent. Tanks and wells should be dug both for irrigation and drinking purposes in the villages.

Over and above this, the method of dry cultivation should be introduced in this area as we find in some parts of South India, specially in Andhra Pradesh. I would request our hon. Minister of Agriculture to open dry-farming research stations at Purulia and Bankura so that the local people of this area take up such scientific methods of dry farming cultivation in those areas. But until and unless such development programmes and dry-farming methods of cultivation are actually taken up, I would request the Central Government to give more food and funds so that the poor and the helpless people of these chronically drought-affected districts could be saved.

Mr. Chairman, Sir, you would not believe that thousands of people are living below the poverty line, and they have been compelled to take grass-roots and leaves of trees to satisfy their hunger anyhow. I would therefore, request our Minister of Agriculture to take a serious view of the situation there and take all the necessary steps so that the poor and the helpless people in those areas are saved from starvation.

With these words, I support the Demands for Grants presented to the House.

श्री शिवशंकर प्रसाद यादव (बनारस)
सभापति महोदय, मैं आप को अन्यायवाद देता हूँ कि आप ने मुझे बोलने की इजाजत दी है।

(श्री शिवशंकर प्रसाद यादव)

यह कृषि विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि इस के लिए अनुदानों की जो मांग की गई है, वह ही क्यों, उस से और ही अधिक मांग की आवश्यकता थी क्योंकि इस कृषि पर देश का केवल मानव ही नहीं बल्कि सारे प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। इसलिए इस का महत्व सब से बड़ा है लेकिन दुःख की बात है कि आज 27 वर्षों की आजादी के बाद भी इस कृषि की ओर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह ध्यान आज तक नहीं दिया गया और आज जब कि परिस्थिति काबू से बाहर हो गई है, ऐसा लगता है जैसे कि हम हाथ-तोबा मचा रहे हैं। इस उपेक्षा का नतीजा यह हो रहा है कि केवल बिहार ही नहीं, केवल गुजरात ही नहीं बल्कि समूचे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में तो इस महंगाई, भ्रष्टाचार, भ्रम भ्रमाव और इन सब चीजों की वजह से जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, उस के चलते कितने ही आदमी मौत के घाट उटार दिये गये।

समापति महोदय, सरकार की ओर से अभी सत्ताधारी दल के कितने ही मंत्रियों ने भी कहा है कि कृषि की ओर सरकार का बर्तान सत्तेले बेटे जैसा है क्योंकि जहां उद्योगधंधों की सुविधा के लिए बिजली की लिए दर 5 पैसे, 7 पैसे प्रति यूनिट लगती है, वहां किसानों को 15, 17 और 20 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है। इस से पता लगता है कि सरकार की नीति किसानों के साथ वह नीति नहीं है जो कि इस महत्वपूर्ण विभाग के लिए होनी चाहिए थी।

हमारे सामने जो आंकड़े रखे जाते हैं, उन आंकड़ों को देख कर तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, भ्रम की कमी नहीं है लेकिन आंकड़े तैयार किस तरह से किये जाते हैं, इस की जानकारी अगर आप को सही हो,

तो मैं समझता हूँ कि उन आंकड़ों पर आप का विश्वास नहीं रहेगा। मैं देहात का रहने-वाला हूँ, मैं ज नता हूँ कि वहां कभी कोई अधिकारी जमीन पर जा कर न खत का एसेममेंट करता है और न पैदावार का एसेसमेंट करता है और दफ्तर में बैठे बैठे आंकड़े तैयार कर देता है।

बीज और खाद का जो वितरण होता है हमारे यहां बिहार में हम को इस बात का अनुभव है कि जिन लोगों के पास एक एक धूर भी जमीन नहीं है, उन को बीज दिये गये और उन को खाद दिया गया और उस के आधार पर आंकड़े तैयार किये गये कि इतनी जमीन आबाद हो गई अगर इस तरह से आंकड़े तैयार होंगे, तो सही आंकड़े हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

एक बात मैं लेवी के बारे में कहना चाहता हूँ। पिछले दफा जो लेवी लगाई गई थी देश में, तो 76 रुपये क्वींटल किसानों के लिये भाव तय किया गया था लेवी का गेहूँ देने के लिए मैं सिद्धान्त लेवी के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन उसमें कोई ध्वबहारिकता पर ध्यान नहीं दिया गया था। जो सरकारी उत्तरदायी लोग थे उन्होंने भी बिहार में यह घोषित किया था कि एक किसान को एक क्विंटल गेहूँ पैदा करने के लिए 105 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन उस समय 76 रुपये गेहूँ का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। अगर तभी किसान का जो खर्च आता है और जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खर्च आता है उस हिसाब से उसको भाव दे दिया जाता तो आज भ्रम की कमी नहीं होती। मैं नहीं मानता कि हमारे देश में गेहूँ का भ्रमाव है। लेकिन हुआ क्या है छोटं लोगों से तो लेवी वसूल कर ली गई है जबर्दस्ती लेकिन जो बड़े लोग थे जिन के यहां दो तीन हजार मन गेहूँ मौजूद था

मुझे इसकी जानकारी है कि वैसे लोगों से केवल बीज या पत्रहू निबंटल ही बसूल की गई है और उनको मुक्ति दे दी गई है। मैं आपको भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देता हूँ। साहेबपुर कमल में एक बी बी ओ साहब थे। उन्होंने वहाँ बड़ी धाधली मचाई। उसके खिलाफ मैंने धावाज उठाई, लिखापत्री की और उनके खिलाफ कई बार हमकायात्री हुईं। स्पेसिफिक चाबिज उनके ऊपर थे जिसके सबूत मेरे पास मौजूद थे लेकिन नतीजा क्या हुआ? उनको थोड़े दिन के लिए ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में उनको एक मिनिस्टर साहब ने अपना प्राइवेट सैक्रेट्री बना लिया। यह भ्रष्टाचार का हाल है। इन्हीं कारणों से हमारे देश में भ्रान्दोलन होते हैं, घेराव होते हैं और इस तरह की दूसरी चीजें होती हैं।

बिहार में नदियां बहती हैं। वहाँ पर बहुत कम गहराई में पानी मिलता है। लेकिन उसका उपयोग मिर्चाई के लिए करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। वहाँ निपट इरिगेशन द्वारा या बारिश द्वारा मिर्चाई को व्यवस्था की जा सकती है। ऐम. प्रान्त नहीं किया है। जिन लोगों ने बारिश किया भी है उनको बिजली नहीं मिल रही है और इस वजह से भी बड़ी परेशानी है।

दीलरशिप देना में बहुत प्रयत्न हो रहा है। सरकार की नीति है जिंजिम आदमी के पास मिले हों घाटा का उस का गेहूँ न दिया जाए। लेकिन हमें यहाँ मुस्लागत्र बाजार में कंत्रल उन्ही लोगों का गेहूँ दिया गया है बेचने के लिए जिन के पास भिन्न है इस तरह से भ्रष्टाचार को अत्यन्त रूप से सरकार बढ़ावा दे रही है। इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश का कल्याण नहीं होगा।

श्री इनीप सिंह (बाबू दिग्गी) : मैं कृषि मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रत्येक देश में खाद्यान्नों

की कमी के कारण चारों तरफ परेशानी महसूस की जा रही है। इससे दो तान कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है किसानों को ठीक भाव न मिलना। कोई भी चीज चाहे वह इंडस्ट्री में बने या खेत में पैदा हो जब तक उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो पैदा करने वाला परेशान तो होगा और वह उन्हीं पैदा नहीं कर सकेगा। मुझे 1971-72 ज.श.ना.याद है जो कि हरिन क्रान्ति का जन्मना था। तब किसानों ने बहुत ज्यादा अनाज पैदा किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को पुराना पर किसान देश को अन्न में भर देने के लिये तैयार हो गये थे और कहते तब कि हम वाहिर से अन्नको अन्न नहीं मंगाने देंगे। मुझे यह भी याद है कि गवर्नमेंट ने यह घोषित किया था कि 76 रुपये में बीघे अन्न पर किसान का गेहूँ बिकेगा तो उसको गवर्नमेंट खरीद लेगी। कई मिनिस्ट्रस में मैं तब गया था। मैंने उनको अनाज में अन्न देखा था तब लात्ता उनके मास को खरीदना नहीं था यह कह कर की यह खरीद के काबिल नहीं है। फूड कारपोरेशन के जो अफसर या इंस्पेक्टर वहाँ होते हैं वे भी उसको अन्नफिट कर देते हैं। नतीजा यह होता था कि परेशान होकर किसान 60-62 या 65 में लात्ता को उस को बेच कर चला जाता था। लात्ता अगले दिन उसी गेहूँ को फूड कारपोरेशन के हाथ में 76 रुपये में बेच देता था किमी हमने किसान के नाम से और कारपोरेशन उसको 76 में खरीद लेगी थी। कौसे यह हो जाता है इसको आप समझ सकते हैं। किसानों को उचित कीमत नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि 1973 में अनाज की कमी बका हुई। सरकार ने कहा कि हम 76 रुपये के भाव पर खरीदेंगे और क्रीट

[श्री शिवशंकर प्रसाद यादव]

ट्रेड को उसने नेशनलाइज कर दिया। अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि सरकारी फार्म तक में गेहूँ 105 या 107 रुपये से निकलता है। तब किसान उसको 76 रुपये में कैसे बेच सकता था। किसान न दिक्का का अनुभव किया। छुट्टा किसान मजबूर होकर ले आया और उसका गे 76 रुपये में बिका। उन दिनों में मैं राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में गया था। वहाँ किसान एक बात कहना था। सरकार मैक्सिम को 76 के बजाय 85 रुपये कीमत कर दे यानी तब रुपये बढ़ा दे और इसी तरह मे देनी गेहूँ कि 95 कर दे और उसको भी नौ दस रुपये पर हार बढ़ा दे तो किसान का राहत मिल सकती थी। मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री से यह बात कही। मैंने उनको कह कि नाथ के किसान इससे परेशान हैं और चाहते हैं कि 9-10 रुपये की क्विंटल कीमत बढ़ा दो ज ये उन्होंने मुझे घर साहब के पास भेजा। मैंने सारी बात उन्हें बताई। घर साहब ने कहा कि अभी तक हमने 76 रुपये का भाव दिया है अब आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे एक बात याद आ गयी है। रोहनरु के अन्दर एक पटवारी होता था जिसका नाम फूल सिंह था। वह रिश्तत बहुत लिया करता था। किसी से दो रुपये, किसी से पाच रुपये और किसी से दस रुपये। एक बार उसका अन्न आ गई और उसने ममम लिया कि वह गलती कर रहा है। उसने जिस किसी में भी रिश्तत ली थी जा कर उसको उसके घर पर वापिस कर दी। इस पद में भी उसने इस्तीफा दे दिया। वह भगत फूल सिंह कहलाया और रोहनरु और हरियाणा के अन्दर उसको भगत फूल सिंह के

नाम से पूजा जाता है। मैंने उनसे कहा कि आप इनको भी ज्यादा दे सकते हैं और जिनको कम दाम आपने दिये हैं उनको भी घर पर उनके जा कर आप नौ दस रुपये के हिस्सा में ज्यादा दे सकते हैं और वे आसानी से देगे, आशीर्वाद देगे और कहेंगे कि इतिहास गांधी की हकूमत में हम तरह में हमने साथ साथ किया गया है, हमारा अन्न किय गया है लेकिन हमारी खान नहीं सुनी गई। नतीजा यह हुआ कि इस बार किसान ने कम दाम। मैं भी शिमान हू। मैं जानता हू कि भाव कम होने की वजह से पे उन्हो एक संयोग। दूसरा कारण उत्पादन कम होने का यह है कि बारिश नहीं हुई, प्रकृति का प्रकोप हुआ। पूरा साल चला गया बारिश नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि जाड़ा पड़ गया, पाला पड़ गया गर्दी पड़ गई। अब इन चीजों पर किसान का कोई वश नहीं है। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन में कमी हुई है।

अब आपने 105 का भाव रखा है और यह कहा है कि जितना हुकातदार खीदेगा उसका आधा भाग उसको 105 के निश्चित मूल्य पर आपको बेना होगा फिर चाहे वह किसी भाव पर भी खरीदे। मैं नहीं जानता हू अबर फूड कारपोरेशन के लोग अब अच्छे हो गये हो। लेकिन 1971 और 1972 की आहापन है वह हमारे सामने है। अगर किसान ने 500 क्विंटल गेहूँ खरीदा तो मैं निश्चिन्त रहूँ। प्रकृति से प्रकृति चाहता ह कि आपके पास क्या सबूत है कि उसने इतना ही खरीदा। अगर किसी ने 500 क्विंटल खरीदा और फूड कारपोरेशन के इन्स्पेक्टर से मिलकर उसने 300

'लखवा दिया और डेढ़ सौ क्विंटल दिया तो उसके पास तो साढ़े तीन सौ क्विंटल बन गया इस तरह की दिक्कत को आप कैसे दूर करेंगे, इसका आपने क्या इलाज सोचा है ?

मैं चाहता हूँ कि छोटे किसान के लिये, खेतीकर मजदूर के लिये आप एग्री इंडस्ट्रीज हर गांव में खोले और उनमें उनका काम दे। नहूँ कई महीने खाली बैठ रहा है। जब वह खाली रहता है तो अपनी तरफ से एग्री इंडस्ट्रीज के जरिये आप उनको थोड़ा सा काम अगर दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका वे लोग गमगातू करेंगे। इससे उनकी आमदनी थोड़ी और बढ़ जायेगी

दिल्ली में 115 के करीब गांव हैं, जिनकी जमीन एकबापर हो गई है। वहां के लोगों ने हरियाणा में जमीन ले ली है और वे वहां खेती करते हैं। उनकी फैमिलीज यहां दिल्ली में रहती हैं। वे लोग हरियाणा में गेहूँ, बाजरे या दूसरे अनाज की पैदावार करते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपनी पैदावार को दिल्ली में लाकर अपनी फैमिलीज को खिला सकें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जमीन हरियाणा में बल्लभगढ़ के पास है। पिछले साल मेरे यहां जो गेहूँ पैदा हुआ, मुझे उसको 76 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ा और मैं उसको यहां अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिये नहीं ला सका। मैं श्री मोदी से दरबखान्त करूंगा कि जो लोग हरियाणा में खुद अपने पैदा किये हुए अनाज को दिल्ली में अपनी फैमिलीज को खिलाने के लिये ला

चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाजत दी जानी चाहिये।

मैं कृषि मंत्रालय की डिमांड्स का समर्थन करता हूँ।

श्री नागेश प्रसाद यादव (सीतामढ़ी) :
सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

मैंने सीतामढ़ी जिले के बारे में कृषि राज्य मंत्री से निवेदन किया था कि और इस संबंध में 5 अप्रैल को उन्हें एक पत्र भी लिखा था। सीतामढ़ी के सैकड़ों गांवों में 29 मार्च, को डेढ़ बजे रात्रि के समय एक भयंकर आंधी आई और करीब एक एक, डेढ़ किलो के झोले पड़े। बेचारे किसानों की परिश्रम से गेहूँ की रबी की—जो खेती की थी, वह बिल्कुल नष्ट हो गई। झोले पड़ने से सीतामढ़ी के किसानों को करीब दो करोड़ रुपये की क्षति हुई है। उन किसानों को मदद देने के संबंध में मैंने जो पत्र लिखा था, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि श्री शिन्डे ने 22 अप्रैल को—करीब बीस दिन बाद—उनके उत्तर में मुझे पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा है:

"Please refer to your letter dated the 5th April, 1974 regarding the damage caused by hailstorm in certain areas in Bihar. Bihar Government has reported that some areas in the districts of Sitamarhi and Motihari were affected by hailstorm towards the end of March 1974. The State Government has made necessary arrangements to deal with the situation and has already placed adequate funds at the disposal of the local officers for rendering immediate relief. Execution of hard manual labour schemes distribution of house building grant and other relief measures such as funds for advance for taccavi loans etc. are also being undertaken in the affected areas.

[श्री नागेंद्र प्रसाद यादव]

Reasonable quantities of food-grains have been made available to the State Government from the Central pool.

My Ministry has, however, forwarded a copy of your letter to the State Government.

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने जो पत्र श्री शिन्दे को लिखा, उसकी प्रति उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट—बिहार सरकार—के पास अन्न नहीं है। सीतामढी जिले के सैकड़ों गांवों में झोले पड़ने से किसानों की दो करोड़ रुपये की बर्बादी हुई है। लेकिन बिहार सरकार की ओर से एक छटांक अन्न भी नहीं दिया गया है, और न ही एक पैसा भी दिया गया है। पहले तो वहाँ पर चार दिन तक भारी बारिश होती रही। किसान अपने खलिहानों में रबी की फसल काट कर लाये थे, लेकिन उन बेचारा की फसल खलिहान में सड़ गई, और जो कुछ बची, वह 29 माचों को एक एक डेढ़ डेढ़ किलो के झोले पड़ने में नष्ट हो गई।

मैं दोनों राज्यों मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि दोनों में से एक मेरे साथ चले, तिथि निश्चित करे और सीतामढी चले। वहाँ सैकड़ों गांवों में जो बर्बादी हुई है उसको वह स्वयं देखें। वह सीतामढी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सखे करा ले कि वहाँ सैकड़ों गांवों में झोले गिरने में जो हानि हुई है, उसको देखने हुए वहाँ प्रति मास कितने अन्न की आवश्यकता है। भारत सरकार उस अन्न को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीतामढी को भेजने की व्यवस्था करे। इस के अनिश्चित वह उचित रेट पर गेहूँ और अन्य आन्नाएँ मुविधायें देने की भी समुचित व्यवस्था करे।

मैं आपके माध्यम में मंत्री महोदय का ध्यान देश में चीनी विनरण की वर्तमान व्यवस्था की ओर खींचना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में दखना हूँ कि वृषभ भवन और रेल भवन व गलममें सरकार का ए. ए. कानज्यूमर स्टार है। वहाँ चीनी 2-20 रुपये प्रति

किलो के हिसाब से बिकती है लेकिन बगल में एक दुकान पर चीनी 4 रुपये और 4.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। यह बहुत दुख की बात है। जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और पूज्यपति हैं, जिनके लिये राशन कार्ड की व्यवस्था है, उन को चीनी 2.20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। लेकिन जो गरीब और हरिजन हैं, जिनके लिये भी राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, उनको चीनी 4 रुपये और 4.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके, सरकार चीनी वितरण की इस दोषपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करे, और यदि चीनी की कमी है, तो सभी लोगों को एक तरह के रेट में चीनी बेची जाये। लेकिन यदि आप उम तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं देश में तो कम से कम हर एक प्रायमी के लिये चाँद चार छटाक प्रति हफ्ता देने के लिये नहीं है तो दो ही छटाक दे प्रति हफ्ता लेकिन सभी लोगों के लिये घनी गरीब सरकारी अधिकारी सभी के लिये 2 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से पूरे देश में चीनी के वितरण की व्यवस्था करे, यह मेरा निवेदन है।

हमारे बुजुर्ग साथी श्री डी० एन० तिवारी साहब से हम ससद सदस्यों को सीख लेनी चाहिये। ये अपने कम्पाउन्ड की पूरी जोतार्ई करके गेहूँ इत्यादि की पैदावार करने हैं और सन्जी भी इतनी पैदा करने हैं कि अपने भी खाते हैं और अपने साथियों को भी खिलाते हैं। लेकिन उनमें बानचीत करने से पता लगा कि सैकड़ों बोझ गेहूँ कट करके उनके कम्पाउन्ड में रखा हुआ है, अभी तक दौनी की व्यवस्था उस के लिये नहीं हो पाई है। इसलिये मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि जितनी जल्दी हो सके उसकी दौनी की व्यवस्था कर दे।

मैं आपके माध्यम से नीनी मंत्रियों का ध्यान ट्यूबवेल की ओर ले जाना चाहता हूँ। उत्तरी बिहार में ट्यूबवेल की कमी है। इस

लिये मेरा निवेदन है कि उत्तरी बिहार जहाँ करीब 20 फुट 15 फुट और 10 फुट पर पानी उपलब्ध है वहाँ के लिये 500 ट्यूबवेल खेने की व्यवस्था करे जिससे हम भ्रष्ट पैदा कर सकें। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समयभाब के कारण मेरे बहुत से प्वाइंट छूट गये। जो भी आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

(Interruptions)

MR CHAIRMAN. I have not given my permission to anyone. Nothing will go on record Mr N P. Yadav, you will please resume your seat

Shri R. P. Yadav

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (गधेपुरा)
सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। भारत के 70 प्रतिशत लोग खेती तथा खेती के संबंधित कारोबार पर निर्भर करते हैं। कृषि की तरक्की ही देश की तरक्की है। कृषि की तरक्की पर केबल गरीबी को दूर करना तथा आर्थिक आत्म-निर्भरता ही नहीं बल्कि जनतंत्र का स्थायित्व भी निर्भर करना है।

खेती की तरक्की मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली है सिंचाई, दूसरी है उन्नत बीज और तीसरी है उर्वरक। दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्षों के बाद भी भारत में खेती योग्य भूमि के 25 प्रतिशत में ही सिंचाई हो पाती है। उसमें से 15 प्रतिशत में तो एग्जॉस्ट इरीगेशन है और 10 प्रतिशत वर्षों पर निर्भर करता है। यह माना हुई बात है कि यदि हम पानी की व्यवस्था कर दें तो इतनी ज्यादा उपज होगी

जिसका कि भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। जहाँ तक 15 प्रतिशत एग्जॉस्ट इरीगेशन की बात है उस के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बिहार के उस भाग से आता हूँ जहाँ पर कोसी नदी का चैनल जाता है जिससे सिंचाई होती है। जिस समय कोसी नदी बाघी गई थी बहुत बड़ी आशा लोगों की थी कि उसके माध्यम से वहाँ की गरीबी मिट सकेगी। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि कोसी नदी का जो चैनल है उसकी आजा यह गति है कि हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपनी कोसी नदी को वापस ले जाओ, इसके चैनल को वापस ले जाओ। हमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं चाहिये। हम पूछते हैं कि क्यों? तो वह कहते हैं कि कारण यह है कि जिस समय सिंचाई की जरूरत होती है तो उस समय पानी नहीं मिलता। कहा जाता है कि बालू धा गया है। लेकिन पता नहीं क्यों जिस समय लोगों को पानी की आवश्यकता होती है उसी समय में उसमें बालू निकाला जाता है। कारण उसका क्या है, यह आप जान सकते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ। दूसरी बात यह है कि स्टैग-नेशन आफ वाटर इतना होता है कि जहाँ पहले जो भी उपज होती है हमारे इलाके में वहाँ पानी इस कदर फैल जाता है कि कोई उपज वहाँ नहीं हो पाती। उसके निकाल को कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो सरकार की तरफ से कमांड एरिया डिक्लेयर किया गया है कि इतनी जमीन में हम सिंचाई करेगे उसका वह बाजाक्ता रेन्ट लेते हैं, लेकिन पानी ले या न ले उस को उतने पानी का रेन्ट देना है। अब लोग परेशान हैं कि इस

[श्री. राजेन्द्र प्रसाद यादव]

सिचाई से आखिर हमें क्या फायदा है ? फायदे के बजाये बर्क नुकसान है। इसीलिये लोग कहते हैं हाथ जोड़ करके आप इस सिचाई की व्यवस्था को वापस ले जाइए। हम वैसे ही ठीक थे, अभी भी वैसे ही ठीक रहना चाहते हैं। तो मैं आप्रह करूंगा सरकार से कि इस आर बह ध्यान दें। जहा एग्जोर्ड इरीगेशन है 15 प्रतिशत उसकी यह स्थिति है। जहां एग्जोर्ड इरीगेशन नहीं है उस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है।

दूसरी बात है उत्तम बीज। उत्तम बीज की जबाबदेह राष्ट्रीय बीज निगम पर है। राष्ट्रीय बीज निगम का कुछ तस्करा मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। नेशनल सीड्स कारपोरेशन का जो भी हाल है उसके बारे में हाउस में भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है और कार्लिंग अटेशन के माध्यम से यह मामला सबन के सामने आ चुका है। पेपर में भी आ चुका है। उसमें इतना बड़ा गडबडघोटासा है कि जिसके बारे में कहना कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन हकीकत यह है कि जब 1971 में इस के अंदर बहुत सारी खराबियां आईं, इससे बड़े बड़े अफसर अष्ट हो गए। अभी आपने देखा होगा बंगला देश को सीड भेजना था मालू का उसमें सडा हुआ तो टैर भंज ही गया उसके अलावा ट्रासपोर्ट की जो कास्ट थी वह बहुत बढ गई। उमें डाइरक्ट यहां से गया देश भेजना था। वह न भेजकर कलकत्ता में ब्रेक किया। उसके अंदर इतना घाटा हुआ कि उसके बारे में हाउस में डिस्कुशन हुआ है और हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय

इस पर जरा ध्यान दें, केवल जबाब के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ईमानदारी से ध्यान दें ताकि कुछ स्थिति उसकी ठीक हो सके। 1971 में वहा की यूनियनो ने एक रेप्रेजेन्टेशन प्राइम मिनिगटर को दिया जिसमें उन्होंने बतावा कि इसके चार पाच पदाधिकारी इसमें जो अष्टाचार फैला हुआ है उसके लिये जबाबदेह हैं। तीन चार पदाधिकारियों का उममं जिक्क किया जिसमें सर्वश्री जी० सी० एन० चेहल, रीजनल मैनेजिंग डाइरेक्टर थे, दूसरे थे एम० एन० जोशी, रीजनल मैनेजर दिल्ली तीसरे थे, बी० एस० राना, रीजनल मैनेजर पूना और चौथे थे ए० सी० सक्सेना, डिप्टी चीफ प्रोडक्शन आफिसर, इन चार अफसरों के बारे में उन्होंने लिखा। इसी आधार पर कार्लिंग अटेशन भी राज्य सभा में आया जिसको ठीक मानकर सरकार ने कहा कि ठीक है हम एक एन्क्वायरी कमीशन नियुक्त कर देंगे हैं। एक ससदी एन्क्वायरी कमीशन बैठा जिसके चीफ हुये श्री बी० एन० गाडगिल, मेम्बर राज्य सभा जब यह एन्क्वायरी शुरू हुई तो उस पर इतने प्रेशर पडने लगे कि उनको साचार होकर रिजाइन करना पडा। एन्क्वायरी करने के पहले ही उनको रिजाइन करना पडा। ये ब्यूरो-क्रेटस, ये अफसर उसके लिये रीजन कुछ भी हैं। इन लोगों का कहना है कि उनका टाइम नहीं था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी वे उनको कोई भी फाइल नहीं देते थे, इसलिये साचार होकर जब उन्होंने देखा कि मैं एन्क्वायरी नहीं कर सकता हू तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस तरह की हालत नेशनल सीड कारपोरेशन की है जिस पर यह निर्भर है कि देश भर को अच्छा बीज सप्लाई करे। मैं चाहूंगा कि इस

का औरों प्रोब हो और वास्तव में इसको रीखा-गैनाइज किया जाये, ईमानदारी से, बचाव के दृष्टिकोण से नहीं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि उन के विभाग की बात है इसलिये शील्ड करने की बात नहीं होनी चाहिये।

नोमरी बान यह है कि देग में उबररु का प्रकाल है। बहुत मुश्किल में भारतीय फिन न ने यह बर्जाजव सम्पत्ता है कि जो केमि रल खाद उम पर निर्भर किया जाये। उन्होंने निर्भर करना शुरू किया लेकिन अब जलन यह है कि कही भी खाद नहीं मिलनी है। जहाँ भी मिलती है वह बिना बनेर के नहीं मिलती। सीधे तरीके में कही नहीं मिलती। अगर यहाँ स्थिति रही तो जो आरने हगिन क्रान्ति का नारा दिया है वह कदा तक पूरा हो सकेगा? इसलिये इस को भी मंत्री महोदय स्वयं तोर से देखें।

खाद किस जमीन में कितनी दे जाये उमकी जाच भी प्रावश्यक है और जाच के लिये या तो इन की तरफ से श्रेष्ठ उबनू गावों में हैं लेकिन यह आज क्या करने हैं कि जो गावों के मुखिया या मुख्य लाग हैं उनके पास रहने हैं और खाने हैं और उमके बाद आराम में रिपोट दालिखन करते हैं कहीं जमीन की जाच नहीं होती है कि किस जमीन में कितनी खाद देनी चाहिये, कितना पानी देना चाहिये, यह सब कुछ नहीं होत।

उन्नत खेती यदि करना चाहते हैं तो उम के लिये औरार भी उन्नत किम्म के होने चाहिये।

आप को मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर बनते हैं उन की कीमत 25-30 हजार होती है। आपने अभी नैड सीलिंग का कानून कागज पर बनाया है जिस से

छोटे छोटे प्लाट्स बनें—एना हानन में छोटा किमान 25-30 हजार रुपये का ट्रैक्टर कीमत खरीदेगा। इस लिए मेरा आग्रह है कि आप छोटे ट्रैक्टर बनाने की व्यवस्था करें, जो 5-7 हजार की कीमत के हों और जैसा अभी हमारे कुछ मन्त्रीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि आप कुछ ट्रैक्टर बनाने में रखें जहाँ लोग जलान पड़ने पर किराया दे कर ट्रैक्टर की सुविधा प्राप्त कर सकें।

ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में एन बान और कहना चाहना है—देखना है जो ट्रैक्टर खराब होते हैं उन का सम्भलन के लिए ट्रैक्टर हैडक्वार्टर्स में या नई बांर ता बहुत दूर ले जाना पडना है—इसमें बहुत तृषसान होता है। मेरा आग्रह है कि मोवाइल वर्कशॉप बनाये जाय तथा हर प्लान-लेवल पर ट्रैक्टर वर्कशॉप शुरू होना चाहिए ताकि उन की सम्भलत की जा सके।

प्लाट प्रोटेक्शन भी एक अत्यवश्यक समस्या है। नई और उन्नत फिनों के आने में कभी कभी क्रॉप में खराबी भी आ जाती है—जिस के लिए स्यदर्या होनी चाहिए। किसानों को प्लाट प्रोटेक्शन के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

एग्रीडें-मार्केट का जहाँ तक सम्बन्ध है—सरकार यदि ज्यादा दाम तय करती है तो जो उपभोक्ता है, वह शिकायत करता है। यदि कम दाम तय करती है तो किसान शिकायत करता है। इस लिए मेरा आग्रह है कि दामों में समतुलन रखते हुए इस तरह की व्यवस्था करें कि दामों के सम्बन्ध में न उपभोक्ता को शिकायत हो और न आराम को कोई शिकायत हो।

[श्री राजेश्वर प्रसाद यादव]

एक बात का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूँ—भूमि-सुधार कानून कागज़ पर तो पाम हा चुका है, लेकिन बहुत मारी स्टेड्स में अभी लागू नहीं हुआ है। अगर हम कानून को लागू भी करें तो इस में इस तरह के डिफेक्टिव क्लॉज़ है, इन क्लॉज़ हैं कि किनी को हज़ारों एकड़ ज़मीन है, लेकिन रागज़ में जो मॉनिग की गई है, वह नियम के मुताबिक है। नीजायत हो रहा है कि मरणाजवनन उनका नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार यात्रा कोई ऐसी व्यवस्था करे जिस में मरणाजवनन हरिजना और दूसरे भूमिहीन किसानों को खेती में मजदूरी को दी जा सके, जो वसतत में उस पर खेती कर सके।

बैंक का राष्ट्रीयकरण हम लिए किया गया था कि छोटे किसानों को खेती करने के लिए उन बैंक से ऋण मिल सके। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। 1969 तक जब कि बैंक का नेशनलाइज़ेशन नहीं हुआ था बड़े पूँजीपतियों को, बड़े बड़ घराना को 440 करोड़ 20 लाख रुपये उधार दिए गए, था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद एक वर्ष में ही 535 करोड़ रुपया उन को दिया गया, इन्फे क्रिस को फायदा हुआ? जो मरवाडी है, बड़े बड़े पूँजीपति हैं, वे इस का फायदा उठा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अप्रार्थ करूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि छोटे किसानों का बढ़ावा मिले तो उन के लिए ऋण को उचित व्यवस्था की जाये। ग्रंथे वीज की व्यवस्था हा, उबरका की व्यवस्था हा मिचार्ट की व्यवस्था की जाये, उन के क्राफ्ट का मरक्षण हा जिस से उन को खेती में आगे बढ़ सकें और उनका कल्याण में दिग भी आगे जा सके।

कुमारी मणिबेन घटेल (माया कठार) : सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में इस लिये भाग ले रही हूँ कि कुछ खाम बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान खींच सकें।

इण्डियन नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड बोर्ड ने 1969 में एक प्राजेक्ट रखा था। दो साल तक उस की मन्जूरी नहीं मिली, 1972 तक दिल्ली के कृषि मंत्रालय में उस पर खेती होती रही, दो साल के बाद उस की मन्जूरी मिली। 5हा डा० कोरियन ने वर्ल्ड फड प्राजेक्ट वालों से बात की थी और अप्रार्थ किया था कि मैं क्वालिटी के बारे में कोई कम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ। उन्होंने जो माल रिजेक्ट किया था वह माल आप की मिनिस्ट्री ने स्वीकार कर लिया और उसे बगला देश को दिया, जिस में हमारी सरकार की काफी बदनामी हुई। मैं पूछती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं अगर काम करना है तो जल्दी करे और ठीक से करें, तब उस का फायदा होगा।

हमारे इन्ही डा० कोरियन ने हमारी आमूल डेरी का विकास किया था। जब हम ने इस को शुरू किया था तो एक छोटा सा मकान केन्द्रीय सरकार ने करवाये पर लेकर शुरू किया था, देहात की 20 महेकारी मंडलियों से आरम्भ हुआ लेकिन आज 600 सहकारी मंडलियाँ इस में हैं जिन का सारा दूध इस डेरी को मिलता है और यह डेरी आज सारे एशिया में सब से बड़ी डेरी है। इन्हें लिये मेरा कहना है कि डेरी मही करनी च हिये। अगर आप फलड-आपरेशन का काम ठीक से चलाना चाहते हैं तो फौरन मन्जूरी दिया करे। आज वहाँ में मन्जूरी लेने के लिये बार बार आवसी को भेजना पड़ता है, आप के मंत्रालय में कोई न कोई रोडा अटकता ही रहता। चाहे आप का मंत्रालय हो, प्लानिंग कमीशन हो या कोई भी विभाग हो—यदि फलड-आपरेशन को सक्सेसफुल करना है, सारे देश में जो दूध की कमी है उस सफट में उस को निकालना है तो उस का एक ही राम्ना है कि जो यहाँ पर हर चीज में आप के मंत्रालय में या प्लानिंग कमीशन में या और जगहों पर जो रोडा डाला जाता है वह न डालिये और भीषणता में

कामों की मन्जूरी देनी चाहिये । जो बड़े उद्योगपति होते हैं वे तो अपने कामों के लिये माइनों आफिसर रखते हैं और उन के द्वारा आप के यहां दोनों का मामला चलता है, इस तरह मेहम तो नहीं कर सकते हैं, जिमसे देश का बहुत नुकसान होता है । मेरा आप से आग्रह है कि आप स्वयं इस को देखें कि एक बार मन्जूरी देने के बाद उस में रंड़ा नहीं डाला जाये । रंवेशन देने का काम जल्दी होना चाहिये ।

दूसरी बात—आप शहरों में अनाज रखने के लिये गोदाम बनाते हैं, उन में साम भर का अनाज भरते हैं—मैं पूछती हूँ—क्या आप ने कभी अपने घर में 12 महीने के लिये अनाज भरा है । यह काम तो देहातों में होना चाहिये । मेरी राय तो यह है कि आप इस को किसानों के पास ही रहने दें और उन को कह दें कि हम आप से तब लेंगे जब हम को जरूरत पड़ेगी और आप को य दाम देंगे । लेकिन आप क्या करते हैं—उन से 70 रुपये में लेते हैं और 170 में बेचते हैं—इस तरह से आप को किसानों से कैसे अनाज मिलेगा, उन का उत्साह कैसे बढ़ेगा ।

आप अखबारों में बेंते हैं कि अनाज के दाम गिरे हैं । लेकिन मैंने अहमदाबाद में देखा है गेहूँ के दाम नहीं गिरे हैं । गुजरात गवर्नमेन्ट जो दाम बतलाती है उस दाम में बाजार में गेहूँ नहीं मिलता है । आज बाजार में गेहूँ का दाम कितना है, चीनी का दाम कितना है, दूसरे अनाज का दाम कितना है—आप जरा बाजार में जाकर मालूम कीजिये । लेकिन अगर आप मोटर में बैठ कर और सिम्प्योरिटी आफिसर के साथ जायेंगे तो आप को सही दामों का पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप साधारण आदमी की तरह से जायेंगे, लोग आप को मिनिस्टर के रूप में नहीं पहचानेंगे तब आप को सही दामों का पता लग जायेगा ।

आप की राशनिंग की दुकानों पर आते हैं तो वहां जो अनाज मिलता है उस में आधा कंकर होता है और वह भी हर हफ्ते नहीं मिलता है । चीनी नहीं मिलती है—अब अगर हम को महीने में चीनी नहीं मिली तो जिस महीने की नहीं मिलती है उस महीने की सैफ्ट हो जाती है । यह कोटा कहा जाता है, कौन खाता है । जिस के पाम कार्ड है, जब उस को नहीं मिलती है तो वह चीनी कहा जाती है—ऐसी व्यवस्था किस काम की है । अगर ऐसी व्यवस्था करनी है तो आप राशनिंग छोड़ दें, सस्ते दामों की दुकानों का काम आप से नहीं चलेगा ।

16.00 hrs.

मैं खास तौर से इस बात पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि नेशनल डेरी डेवलपमेन्ट का जो काम है उसमें शीघ्रता आये और उसमें कोई रोड़ा मत डालें । यदि कोई उन्साह से काम करने वाला हो तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए । अमूल डेरी एशिया में बहुत बड़ी डेरी है उसको काम करने का मौका देना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) सभापति जी, कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है । विकसित कृषि के बल पर ही हम अपने देश को श्री सम्पन्न बना सकते हैं । मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आजादी के बाद हमारी सरकार ने इसको समझा और अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि के विकास पर जोर दिया । फलतः कृषि जगत में हलचल पैदा हुई, क्रान्ति हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई । किन्तु बावजूद इस बात के ऐसा लगता है कि इसमें मूलभूत कुछ त्रुटियां रह गईं, या अभी भी हैं जिनके चलते कृषि में जो विकास हुआ उसका फल अमीरों को ही ज्यादा मिला और गरीब वर्ग के लोग उपेक्षित ही रहे । यह बात इससे भी साफ होती है कि एक

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

लाख से ऊपर गांवों में हमने अभी तक शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं की है। 80 परसेन्ट ग्रामीणों में हमने अभी तक शोधघालय की व्यवस्था नहीं की है। कुल 55 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ खेतिहर हैं और 5 करोड़ कृषि लेबरर्स हैं और इन्हीं लोगों के जिम्मे सारे देशवासियों को खिला-पिलाने का दायित्व है। इसलिए इनका काम बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा कि इनको उचित सम्मान मिले खेती में वे सफल रहें इसके लिए उनको बढ़ावा दिया जाये और चाहिए कि सभी अपने किसान भाइयों को आज का देवता कहें तथा उनकी शोपड़ियों को अपना देवालय मानें। पूरी कृषि की 20 परसेन्ट जो जमीन है इस जमीन में साठ परसेन्ट जैसे लोगों के द्वारा खेती की जाती है जिनके पास तीन हेक्टर से 5 हेक्टर जमीन है और 38 परसेन्ट लोग 80 प्रतिशत जमीन को रखे हुए हैं। ये सभी चुनौतियाँ हैं कृषि मंत्रालय के सामने जिनको सबे स्वीकार करना है और उनको हल करने की तरकीब सोचनी है जिससे कृषि का विकास हो सके। 30 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों की संख्या 15-16 लाख है और सरकार के कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं लोगों को विकास के अवसर मिले हैं। जो पांच करोड़ लोग हैं जिनके पास 5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है वे ज्यादा लाभान्वित नहीं हो सके हैं।

जहाँ तक लैंड सीलिंग ऐक्ट का प्रश्न है, इसमें दो चीजें ऐसी हैं जिनके कारण यह ऐक्ट सफल नहीं हो रहा है। पहले तो जो भूमिचोर हैं उन्होंने, जब सरकार ने नियमों को लागू नहीं किया था तभी जो सरप्लस जमीन थी उसकी अवरवाइज व्यवस्था कर ली। दूसरे जो भी जमीन कानून के अन्तर्गत प्राप्त हो सकी है उसका वितरण एक और अनेक कारणों से रुका हुआ है, मुकदमे चल रहे हैं, यह होना है और वह होता है तथा

उसका नतीजा यह होता है कि गरीबों को जमीन नहीं मिल रही है।

बैंकों का जो नेशनलाईजेशन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीबों को कर्ज मिलने में सुविधा हो जिससे वे कृषि का काम कर सकें लेकिन हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो गए। उन को कर्ज मिलता नहीं है। एक तो नियम बड़े जटिल है और यदि नियमों के अन्तर्गत वे आभी जाते हैं तो अधिकारियों और कर्मचारियों के चलते उसको ऋण मिलता नहीं है। परिणामस्वरूप वे खेती में अपना मन नहीं लगा सकते हैं। उनको अबसर नहीं मिलता है कि अपनी खेती को विकसित कर सकें। यह बात सही है कि किसानों को, गरीबों को, हरिजनों को तथा ग्रन्थ कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से उचित सहायता मिले इसके लिए सरकार ने दो संस्थाओं की स्थापना की है—एक है स्माल फार्मर्स डेवलपमेन्ट एजेंसी और दूसरी है माजिनल फार्मर्स ऐंड एग्रीकल्चरल लेबर एजेंसी। यह बात भी सही है कि यह बहुत अच्छा काम है लेकिन इसको हम बहुत कम रुपया देते हैं। साल में एक किसान को मुश्किल से करीब 60-65 रुपया देते हैं। आप ही सोचें कि 60-65 रुपए में एक किसान क्या करेगा? उसमें वह क्या बीज खरीदेगा, क्या खाद खरीदेगा, क्या मीजार खरीदेगा या और क्या करेगा? तो यह रकम बहुत कम साबित होती है इसमें प्रबन्ध वृद्धि होनी चाहिए और इसके जरिए किसानों को यथेष्ट सहायता दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए—यह मेरा सुझाव है।

इसके बाद मैं इरीगेशन और एलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स पर आता हूँ। अब तक जो योजनाएँ बनी हैं उन पर 75 सौ करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा किया है। अब सारे

देश में जो होता हो लेकिन हमारे यहाँ भी एक-आध बड़ी बड़ी योजनायें चालू हुई हैं लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ है और मालम नहीं कब पूरा होगा। जैसे हमारे यहाँ कोसी और गण्डक योजनायें हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ी कोशिश की कि केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन का भार अपने ऊपर ले ले लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो सके हैं। यदि अब भी इस पर सरकार विचार करे तो अच्छा है नहीं तो स्टेट गवर्नमेन्ट को पूरा रुपया मिले ताकि इन योजनाओं का शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन हो सके और जनता को उसका लाभ मिल सके।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बड़ी योजनाओं के अलावा छोटी छोटी योजनायें ग हैं उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाये तब उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। हमारे क्षेत्र में दो छोटी योजनायें हैं, दो कॅनाल्स हैं उनका यदि जीर्णोद्धार कर दिया जाये तो सबसे हजारों एकड़ जमीन में धान का उत्पादन बढ़ जायेगा। जैसे भकुप्रा कॅनाल और किम कॅनाल—इन दोनों का जीर्णोद्धार हो जाये तो लाखों मन धान की पैदावार हो। मैं चाहूंगा सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे।

इसके अतिरिक्त जहाँ से मैं आता हूँ वह कोसी की बेल्ट है, वहाँ बहुत सारी जमीन बंकी पड़ी हुई है, बहुत कम जमीन में उपज होती है। मैं वहाँ की जो बास्तविक स्थिति है उसका वर्णन करना चाहता हूँ। वहाँ पर जमीन वे जो थोड़ी उपज होती भी है उस पर भी धाकड़मण बोल दिया जाता है और उस उपज को लूट लिया जाता है और किसान मुंह ताकते रह जाते हैं। (व्यवधान) आप इसको अपने पर न लें, इसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं।

साथ ही इस देश में जगल बहुत हैं लेकिन उनसे हम अधिक लाभ नहीं ले रहे हैं। यह इस बात से साबित होता है कि और देशों में प्रति वर्ष एक एकड़ में दो सौ रुपए की आय होती है जबकि अपने देश में हम एक एकड़ में मुश्किल से 10 रुपए प्राप्ति करते हैं। इसलिए वनों के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार स्टेट्स को कौश प्रोग्राम्स के अन्तर्गत रुपया देती है जिससे डेवलपमेन्ट का काम हो रहा है। उससे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ बिहार में रोड डेवलपमेन्ट का काम होता है। हमारे क्षेत्र में घोषरडीहा प्रखण्ड में दो सड़कों की मंजूरी हुई तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका कोआपरेशन इतना मिला कि राम्ने में जो घर थे उनको उन्होंने अपने से ही तोड़ दिया और योजना का स्वागत किया। लेकिन रुपए के अभाव में उन सड़कों का पक्कीकरण नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके समझ भी रुपए का सवाल है, महंगाई है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी काम हो रहे हैं उनमें यह कर्म: सबसे सफल है और इसकी सफलता और हो सके उसके लिए आप यथेष्ट सहायता दें ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो बिहार में काम शुरू हुआ है वह पूरा हो सके।

एक बात की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके सम्बन्ध में इस सदन में कालिग एग्रीमेंट के अवसर पर चर्चा चली, स्टार्ड रिवीजन में भी चर्चा चली और कल श्री गेदामिह जी ने भी उसकी चर्चा की थी। मैं भी ऐसा अनुभव करता हूँ कि यह जो शुगर इण्डस्ट्री है इसके नेशनलाईजेशन पर सरकार शीघ्रातिशीघ्र विचार करे। जिनके पास बंगला है, बहुत सारी जमीन है

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

वे इसमें भ्रम उपजाते हैं वे श्रीर ज्यादा उपजा सकें। इसलिये जो आवश्यक सामान है जैसे खाद, बीज, वह उनको मिले ताकि ज्यादा उपज हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): Mr. Chairman, I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture. I have no doubt that the price rise of foodgrains and defective distribution system are the root causes of the present riots in various parts of the country, specially in Bihar. So, immediate steps should be taken to tone up the food control and distribution machinery in the whole country. The officials of the Food Corporation of India and the Government depots and stores take high-handed action and they do not bother about distribution. I come from Jamshedpur where FCI has got a godown. Whenever we are short of foodgrains they wait till they get sanction from Delhi and Ranchi, which sometimes takes as much as 15 days, even when an SOS is sent. This should be looked into by the Agriculture Minister

Singhbhum and Jamshedpur are deficit areas in Bihar, so far as foodgrains are concerned. The Central Government dump their foodgrains in Patna in the godowns of the FCI and it takes two to three months for the foodgrains to reach Jamshedpur and Ranchi. Steps should be taken to expedite the movement of foodgrains already there and there should be direct supply to the big cities which are now depending on the Centre for foodgrains.

Coming to corruption, I was more shocked than surprised to read a report in the papers that the Maharashtra Government had to bribe the FCI officials to get the release of foodgrains

to Maharashtra. This was stated by Shri Shinde, Minister of Agriculture and Food, in Rajasthan. I hope the Minister will ensure that such things do not take place.

In 1972 the hon. Minister, Shri Shinde, announced in this august House that by 1973 we would be surplus in foodgrains and we would even export foodgrains, and the USA Aid through PL 480 was suspended. The result is that we have now to depend on other countries. In future, such statements should not be made on the advice of the bureaucrats.

The farmers should be exempted from agricultural income-tax. I would like to know what steps the Government propose to take against hoarders and blackmarketeers. The Government should amend the Food Control Act and those who contravene the Act should be awarded life sentence, if not death penalty. Government should not simply blame drought, flood and other natural calamities for shortfall in production. They should make alternative arrangements so that the impact of these calamities would not be much. We should not export foodgrains out of India, as long as we are short of food-grains.

Now the tribal and backward areas of Bihar are being neglected. The farmers are not given any guidance in agriculture. Nor are there any schemes of minor irrigation in Jamshedpur or Singhbhum. If the projects of construction of dams in suvarnrekha river, already sanctioned, are taken up, it can irrigate thousands of acres of land in Bihar, Bengal and Orissa. So, the construction of dams should be taken up without delay.

The water pump sets supplied to the farmers are of an inferior quality. The departmental officers who purchased them should be proceeded with for corrupt practices

The aid given to the farmers for the purchase of bullocks, cows and buffaloes do not reach them in full. Instead of money, they should be given bullocks and cows to avoid corrupt practices of the officers.

Lastly, I suggest that the Government should introduce two types of farms, just like in the Soviet Union, State Farms and Collective Farms. This will improve the production of foodgrains. The sooner the better. Our vast country will not prosper only with industrial progress if it is not backed by the agricultural surplus.

With these suggestions, I heartily support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.

जीमती लक्ष्मीबाई राय (सागर) :
सभापति जी, धन्यवाद है मुश्किल में मौका मिला । कई लोगों को तो कई कई दफा बोलते हैं और कुछ को मौका ही नहीं देते । मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ, साथ ही साथ यह भी कहना है कि 1947 में जो जमीन की हालत थी वह अब नहीं है सरकार ने कृषि में तरक्की की है और काफ़ी, जमीन में निचाई है । इस साल अपने जिले में और उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय एक ही चीज देखी और वह यह कि पाला पड़ने से धलसी, असूर, धरहर और चना मारा गया । लेकिन गेहूँ बहुत हुआ है । एक एक खेत में मुनहूना गेहूँ इनना हुआ है कि काटते समय खेत से बाहर हो गया है । किसानों के पास इस साल काफ़ी गल्ला हुआ है ।

रूखा सबाल को भूमिहीन हैं तो भूमि कहीं बची नहीं, बँडने तक को जमीन नहीं है । अब सरकार कहां से जमीन लखे । देशांतरों में औरतो की टुट्टी तक के लिये जयहूँ नहीं है । बकिहान और बाँब के मजदीक तक मकान

बन गये । अब जमीन सरकार कहां से लावे ? अब बचे जंगल । तो जंगल ही घाप कटवा दें और वह जमीन हरिजनों और धादिवासीको को दे दें । मैंने देखा है कि जमीन अगर किसी हरिजन, धादिवासी को दे भी दें तो पहले तो खेती करने के लिये बैल चाहिये । आजकल बैल ढाई, तीन हजार २० से कम नहीं मिलते हमनिये उन बेचारों के लिये बैल लेना ही समस्या है । घाप कहते हैं कि भैंस, बैल रख । जब जमीन नहीं बची तो कहा चरायेंगे उन को । लोग परेशान हैं । घाप ने जो धादिवासी और हरिजन को 4, 6 एकड़ जमीन दी है तो पहले तो खेती के लिये बैल चाहिये तीन हजार के, उम के बाद साल भर के लिये बीज वगैरह और खेती के उपकरण चाहिए । जब वह परेशान हो जाता है तो बगल का बड़ा किमान उम को अपने घर ले जाता है और कहता है कि 6,000 २० लो और जमीन हूँ दे दो । वह बेचारा उम जमीन को बड़े किमान को बेच देता है और फिर शहर को चला जाता है वहां जा कर रिषणा खरीदता है, कोई धंधा करता है जिम से 10, 20 २० रोज कमाता है ।

अगर भूमि घाप को भूमिहीनो में बांटनी है तो 4, 6 एकड़ न दीजिये बल्कि 10, 12 एकड़ दीजिये जिस से साल भर किसानी कर सके । वैसे तो अब कोई किसानी नहीं करना चाहता, कीच में कीन जाय । शहर में मज से मिनेमा देखेंगे, दूसरा धंधा करेंगे जिस में फ़ायदा है खेती में क्या रखा है । तो घापको इन तमाम बानों को मोच कर कदम उठाने चाहिये । जिस को जमीन दे 10, 12 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये । 4 एकड़ में वह बेचारा क्या करेगा ? हमारे मध्य प्रदेश में बीड़ी का धंधा है । लोग खेती भी करते हैं और बीड़ी भी बनाते हैं । लेकिन दूसरे प्रान्तो में दूसरा धंधा नहीं है, न कोई उद्योग है, न कुछ है । तो सब प्रान्त एच से नहीं हैं । जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश

[श्रीमती महोदरा बाई राय]

श्रीर उत्तर प्रदेश में गेहूँ ज्यादा होता है, जब कि दूसरे प्रान्तों में नहीं होता । अगर यह चार प्रान्त गेहूँ पैदा न करें तो सारा देश भूखी मर जायेगा ।

खेती की उन्नति के लिये आप कदम उठाएँ । जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है वहाँ सिंचाई के साधनों का भी प्रबन्ध कीजिये । हमारे मध्य प्रदेश में बैसे सिंचाई के साधन घीने घीने सब जगह हो रहे हैं । वहाँ ट्यूबवैल हैं, पम्प हैं । नदियों से भी सिंचाई होती है । काफी बागीचे लगने लगे हैं, आलू होने लगे हैं । जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं और उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ आप इनको उपलब्ध कराएँ ।

मिनिट्री के लोग जब निकलते हैं तो उनको हर जिले में जमीन दी जाती है । वे उमका जातते तो नहीं बचवाच कर रुपया ले कर चले जाते हैं । हमारे मागर कैंटोनमेंट के बारे में मैंने एक पत्र मौर्य जी का दिया है, एक प्रबान मंत्री का दिया है, एक गृह मंत्री का दिया है । वहाँ हमारे हमारे 25—30 हजार लोग बसे हुए हैं । वहाँ बं खेती कर रहे हैं । आलू, गेहूँ, मजियां उगा रहे हैं । अब मिनिट्री ने आदेश दिया है कि इसका खाली करो, गिटायंड लोग आएंगे और उनको वहाँ बसाएंगे । ऐसी बान नहीं है कि मागर कैंटोनमेंट से ही दरखवास्त आई हों । और चार छ जगहों से भी आई है । मैं चाहती हूँ कि आप इस बं से मोच ममझ कर कदम उठाएँ । अगर आपने जल्दी कदम कोई उठाएँ तो आन्दोलन एक और उठने वाला है यह मैं आपको चेतावनी दे देती हूँ, एक अकत और आने वाली है । तब काम कैसे चलेगा ।

गल्ले के बटवारे का भी मवाल है । योजना नो आप अच्छी बनाने हैं, प्रान्त के स्तर पर अच्छी बननी है, लेकिन जिले के स्तर पर,

कलैक्टर के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर जा कर बट खरब हो जाती है, समाप्त हो जाती है । पटवारी तक जाते जाते सब खत्म हो जाता है । वहाँ जैसे के बिना काम ही नहीं चल सकता है । इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये ।

बैंको से कर्जा लेना होता है तो दस बार तो दरखवास्ते ले कर जाना पड़ता है और चार हजार मिलने होते हैं तो चार सौ वहाँ देने पड़ने हैं, एक हजार लेना हो तो एक सौ पहले देने पड़ने हैं । रह जो अष्टचार हैं यह भी दूर होना चाहिये । कुमाँ खोदना होता है तो बाधा नो पहले दे देने हैं और बाकी का कहते हैं कि तीन किशनों में दिया जाएगा । इस तरह में कुमाँ अधूरा ही रह जाता है ।

मौर्य जी नए आए हैं । आप हवाई जहाज से हर प्रान्त और हर जिले में जाएँ और वहाँ जा कर देखें कि क्या हो रहा है । शिन्दे शहद्व भी जाएँ । देहात देहात में शहर शहर में जाएँ और वहाँ की कठिनाइयों को देखें और उनको हल करें । तब जा कर कृषि के मामले में आप आत्म निर्भर हों सकते हैं । तभी खेती की उन्नति हो सकती है ।

बटवारे की थोड़ी कमी हो जाती है तो दूसरी पार्टियाँ आन्दोलन करनी हैं, लोगों को उकसाना है । चूँकि बोट हमें मिले हैं, इनको नहीं मिलने है तो उनको कहते हैं कि यह—है नवीजा कांग्रेस को बोट देने का । इसी कारण में तुम्हारी यह हालत हुई है । उनको आप ऐसा करने का मौका ही न दें ।

जो ईमानदार अफसर हैं उसको दूसरे अफसर रहते ही नहीं देने हैं, उसका तबादला करवा दिया जाना है । इस तरफ आपको ध्यान जाना चाहिये । पटवारी तहसीलदार ही आपको तबता पलटेंगे । इस बास्ते आप इधर ध्यान दें कि बे ठीक तरह से काम करें ।

अष्टाचार का यह हाल है कि दूध की बोटल होटल से घ्राप लेने जाए तो बहा जितनी घ्राप चाहे घ्रापको एक रुपये बोटल के हिमाब से मिल जाएगी लेकिन डिपो वाले हम लोगों को कहते हैं कि खत्म हो गया है। कैसा घ्रापका इतजाम है ? इस तरह की चीजों तो हैं इनकी तरफ घ्राप ध्यान दे।

मैं अन्न म इनन' ही कहना चाहती हूँ कि मिनिट्री एग्रिया मे हमारी जो जमीन है कैंटोनमेंट म मे है वहा जो लोग खेतीबाडी कर रहे है उनको हटाया न जाए। मिनिट्री चले जा नग कर रहे है इसका बन्द किया जाए। नही तो आन्दोलन होगा। चार छः कैंटोनमेंट म इस तरह की दरखवागने आई है और उनकी तरफ घ्रापको ध्यान देना चाहिये। उन लोगों को घ्राप दूसरी जगहा पर शहरा मे, देहानो म दे सकते है। यह उन पर बमले भी नही है, बेच रर चले जाते है। भूमिहीन आदिब मिग का हरिजनो आदि का चार एरड नही बल्कि 8—10 या 12 एरड जमीन घ्राप दे ताकि साल भर उम जमीन पर वे काम कर सके और अपना गुजारा चला सके। लोगो का घ्राप वैन खरीदने के लिए बीज के लिए मिनाई के लिए, विजनी के लिए बीजारो के लिए कजं द। उनक लिए छोट-छोट पैकज का इतजाम करे। वे बीम नीम हजार इन पर खर्च नही कर सकते है।

भीर्य साहब तीसरे नम्बर पर घ्राए हैं। वे लडके है, नवयुवक हैं। वे ऐसे कदम उठाएं कि बीनो मंत्री पीछे रह जाए और बडे बडे मंत्री बन सके। बडे मंत्री तो घ्राब रिटायर होने वाले हैं, बूडे घ्रादमी हैं, उन से अधिक काम भी नहीं होता है। इन मे नया खून है। वे देश की उन्नति और कृषि मे उन्नति करके दिखाएं। विरोधी जो हम

लोगो को गालिया देते हैं वह ऐसी व्यवस्था करें कि वे न दे पाए और हमारी जनता खुश हो और हम फिर घ्राणे जीत कर घ्राते रहे।

श्री पद्मलाल बाबूपाल (गंगानगर)

मैं कृषि मन्त्रालय की मांगो का समर्थन तो करता हूँ लेकिन अनुशासन के नाते करता हूँ, परन्तु अन्तर्दत्ता से नहीं। मुझे डाक्टरो ने सलाह दी है कि मैं अधिक न बोलू। अधिक बोलने से मुझ को उन्होंने मना कर रखा है। लेकिन जिस जनता ने मुझ को पाचवी बार चुन कर भेजा है उस जनता की तथा उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने के लिए यदि मुझे ज्यादा बोलना पडे और इस में मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ।

यह कहा जाता है कि बीजो का अभाव है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभाव नहीं है। कोई भी बीज हो घ्राप उसको प्राप्त कर सकते है। लेकिन वह घ्रापको ब्लैक मे और दुगुने दामो मे ही मिल सकती है। यह बात घ्रापको माननी पडेगी कि वितरण व्यवस्था बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहा के किसान को न खाद मिलने है न सिमेंट मिना है, न ट्रेक्टर के लिए डीजल मिना है और न ही मिल रहा है। उन से घ्राप लेबी ले और उनको सिमेंट न मिले, लोहा न मिले तो यह ठीक नहीं है। हम उनको दे तो कुछ नहीं और लेबी ले यह मारे लिए शर्म की बात क्या नहीं है ? कोई भी बीज घ्राप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दुगुने दामो मे।

सारी यह बीज पैदा कैसे हुई और किस बजह से हुई ? हमारी प्रधान मंत्री ने समावाद का नारा लगाया था। उन्होंने कहा था कि हम देश मे समानता ला कर रहेंगे, गरीब बर्ग को उठा कर रहेंगे।

[श्री पन्नालाल बाहपाल]

सभी से साम्राज्यवादी शक्तियों ने, सामन्तवादी शक्तियों ने, पूँजीवादी शक्तियों ने, फ़िरकापरस्त शक्तियों ने एक जुट हो कर उनकी नीतियों के ऊपर हमला बोल दिया और अव्यवस्था पैदा कर दी। आप इनके द्वारा मेरा राज दे कर देख लें ये कुछ भी नहीं कर पायेंगे। ये लोग बिल्कुल असमर्थ हैं।

मैं आपने क्षेत्र की बात कहता हूँ। मेरे क्षेत्र में हमारी पोलिटिकल पावर नहीं है। पूरे डिविजन से कांग्रेस का एक ही मैं एम पी आता हूँ। 23 साल से मैं बराबर एम पी चला आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता है। पानी बीच में टूट जाता है। खाद उनको नहीं मिलती है।

मेरे क्षेत्र के ऊपर आप रहम करो। उस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आप कोई विशेष कमेटी बनाएं जो वहाँ जाए और समाधान आपको सुझाए। बहा पर कृषि महाविद्यालय भी खोला जाए। यह मान बहुत पुरानी है। उसको पिछड़ा हुआ इलाका भी घोषित किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। जब तक आप उसको पिछड़ा हुआ इलाका घोषित नहीं करेंगे तब तक वहाँ इण्डस्ट्री नहीं खुल सकती है, कुछ भी विकास का काम नहीं हो सकता है। मैं आप से मिला हूँ, प्लानिंग मिनिस्टर से मिला हूँ, वित्त मंत्री से भी मिला हूँ। सब मंत्रियों से मिला हूँ। आपका भी अपना प्रौसीजर होता है। लेकिन उधर आपका ध्यान नहीं जाता है।

हरिजनों के नाम पर तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि उनको जमीन दी गई है, दूसरी सुविधाएँ दी गई हैं। आपने हम लोगों को भूजा का पाव

बना दिया है। हम को वही जबाब दिया जाता है कि राज तुम्हारा है, खूब लूटते हो, खसोटते हो। मेरे पास यह पंद्रह हजार लोगों की सूची है जिन को राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीनें एलाट की गई हैं। इस में लगभग बारह हजार ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल बोगस हैं। वे या तो सरकारी नौकर हैं या फिर वे दूकानों में काम करते हैं या दूसरे काम करते हैं। हरिजनों को जो जमीनें दी गई हैं ऐसी जगह दी गई हैं जहाँ पानी नहीं लगता है या फिर उनको ऊँचे टिब्बों पर दे दी गई हैं और कह दिया गया है कि तुम को हमने इतना ऊँचा चढ़ा दिया है। या फिर ऐसी जमीनें उनको दी गई हैं जिन का कच्चा उनको नहीं मिलता है क्योंकि गोली बन्दूक लिए लोग वहाँ बैठे हैं और उनको कच्चा लेने नहीं देते हैं। राजस्थान सरकार ने एक हार्ड पावर्ड कमेटी बनाई थी इस मस की जांच करने के लिए। उसको बने तीन बरस हो गए हैं। उसकी एक मीटिंग भी नहीं हुई है। गवर्नर तीन तीन महीने करके उसके कार्यकाल को बढ़ाता जाता है। लेकिन एक भी मीटिंग नहीं होती है। मैं मांग करता हूँ कि जब तक एलाटमेंट्स की पूरी तरह जांच न हो जाए तब तक एलाटमेंट्स को परमानेन्ट न किया जाए। अफसर लोग धडाधड इसको परमानेन्ट कर रहे हैं। इस को आप बन्द कराएं। यह जो मांग पुलन्दा है इसको मैं यहाँ फेंकता हूँ। इसकी आप जांच कराएं।

MR. CHAIRMAN: Shri Barupal Ji, you are a very senior and sober Member. You have thrown that bundle, I think, in a moment of excitement. I hope you will apologise to the House for that.

श्री पन्नालाल बाहपाल: याचना करना मैंने सीखा ही नहीं है। मुझे आप बाहर निकाल सकते हैं, मेरे से आप इस्तीफा ले सकते हैं। माफी मैंने कभी नहीं माँगी।

MR. CHAIRMAN: I request you to apologise. You have, of course, done it in an excitement. This is not proper. You owe an apology to the House.

श्री पन्नालाल बाकपाल : जब मैंने शोर मचाया तो राजस्थान सरकार मे वह हाई पावर्ड कमेटी बनाई। लेकिन उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। फिर आप कहते हैं कि मैं माफी मांगूं, समझ में नहीं आता है। इसकी पूरी जांच आप कराएं। मैं आप से माफी मांगता हूं।

DR. H. P. SHARMA: (Alwar): Sir, if you see the record, he has already said 'Sorry'. I suppose that would do.

MR. CHAIRMAN: The thing that he has done is not a contempt as he has felt exercised because of the people of his constituency. I quite appreciate it. As he said 'sorry' I think the Members will take no notice of it. Mr. Barupal, you will please continue.

श्री पन्नालाल बाकपाल : हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अफसर लोग परमानेंट एलाटमेंट्स कर रहे हैं। इसको आप रोकें उस वक्त तक जब तक पूरी जांच न हो जाए। पिता जो है वह दिमाग से काम करता है और माता हृदय से करती है। बच्चे का पालन पोषण मां करती है क्योंकि वह हृदय से काम लेती है। वही अच्छे तरीके से उसको पाल सकती है। पिता को जब बच्चा बे दिया जाता है अवर वह उस पर पैसाब कर देता है तो वह उसको खलम फेंक देगा। उस में बुद्धि अकर है लेकिन बच्चा पालने की क्षमता नहीं है। मैं जो कहता हूं वह हृदय से कहता हूं।

आज देस में जो हालत है, उस की वजह से हम लोगों को मूंह नहीं दिखा सकते हैं। जगह जगह पर झण्टाचार और बरेक मार्कोटिंग है मेरा दो बोतल दूध का काई है, लेकिन मुझे दूध नहीं मिलता है। एम०पी० को समय पर राजन नहीं मिलता है। जो राशन 15 तारीख को मिलना चाहिए, वह 25 तारीख को मिलता है। मेरे परिवार में चार आदमी हैं और आठ आदमी रोज भेजे घर पर आने हैं। इस स्थिति में हम क्या खाये? हम वजह से मजदूर हो कर हम को चोरी करनी पड़नी है और कहीं न कहीं से अनाज का इन्तजाम करना पड़ना है। इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।

यहां पर चापलसी की जो बातें कही जाती है, मैं उन्हें पसन्द नहीं करता हूं। कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में अच्छी बात कही हैं। मैं उन से सहमत हूँ। "बाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा बेपरवाह, जाकू कुछ नहीं चाहिये, वही शाहन का शाह"।

मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मुझे पांच बफा चुनकर बहा भेजा है, या तो वे बेवकूफ हैं, या मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि सरकार मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती है और या बवर्नेमेंट बेवकूफ है, जो मेरी बातों को नहीं मानती है। मैं धाक्का करता हूँ कि मैंने जो बातें कही हैं, बंबी महोदय उन पर विचार करेंगे।

श्री रामाबल्लार शास्त्री (पटना) : मभा-पति महोदय, माननीय सदस्य, श्री बारूनाल, ने जिन भावनाओं को अभी व्यक्त किया है, वे भावनाएँ हमारे देश के कोने-कोने में, और रोम-रोम ममाई हुई हैं। सरकार की गलत मुनाफाखोर-और-गल्ला चोर पक्षी तथा देश में पूँजीवाद का विर्माण करने की नीति के कारण ही इनकी और महगाई, अभाव और अष्टाचार है, और तमाम तरह की बुराइयाँ हमारे समाज में व्याप्त हैं। देश के हर एक भाग में लोग भूख भर रहे हैं। खाने को नहीं मिल रहा है। अगर किसी के पास पैसा है, तो उसे अनाज नहीं मिलता है, और अगर कहीं अनाज है, तो लोगों के पास उसको खरीदने के लिये पैसा नहीं है।

यह स्थिति पूरे मुल्क की है। लेकिन मैं उम राज्य से आता हूँ, यानी बिहार प्रदेश से, जो बहुत ही भूखा राज्य है। वहाँ गल्ले की कमी है। आवश्यकता से कम गल्ला वहाँ भेजा जाता है। देश में गल्ले की इनकी कमी नहीं है, जिसकी वजह से महगाई इनकी बढ़ जाये और अभाव इतना ज्यादा हो जाये। कहा जाता है कि हमारे मुल्क में गल्ले की केवल दस प्रतिशत कमी है। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है—त्राहि-त्राहि मची हुई है—उमका अनुमान हम नहीं लगा सकते।

मैं खुद पटना में आता हूँ, जो बिहार की राजधानी है। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ साठ फीसदी लागू दाना टाइम खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा है भी, उनको अनाज नहीं मिलता है। राशन की सड़क दुकाने खाली पड़ी हुई हैं। और उन पर इस आशय की तख्तियाँ लटकी हुई हैं। वहाँ 500 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिस्से से गल्ला दिया जाता है और वह भी एक महीने पर, जब कि पहले 1350 ग्राम प्रति व्यक्ति गल्ला 15 दिनों में दिया जाता था। यही हालत पूरे सूबे की है।

इस समय बिहार को पच्चीस हजार टन गल्ला प्रति मास दिया जाता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहाँ एक लाख टन गल्ला प्रति मास भेजने की व्यवस्था की जाये, ताकि लोगों को नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में गल्ला उपलब्ध हो सके।

आज पूरे बिहार में छात्रों, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों में असंतोष है, क्योंकि उन सबको महगाई और अभाव का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग उम बात को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं कि सरकार अपनी मुनाफाखोर और गल्ला-चोर-पक्षी नीति को बदले।

सरकार ने गेहूँ के थोक व्यापार को छोड़ कर मुनाफाखोरो और गल्लाचोरो को व्यापार करने की जो इजाजत दे दी है, उससे वे और ज्यादा शोख हो गये हैं और वे जनता को और ज्यादा लूट रहे हैं। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार की वर्तमान नीतियों के प्रति बिहार के छात्रों नौजवानों, किसानों और मजदूरों में जो असन्तोष है उमका इम्तेमाल वे दक्षिणी-पश्चिमी तत्व और स्वयं की पूर्ति के लिये कर रहे हैं जो यहाँ पर हिटलरी राज्य कायम करने का सपना देख रहे हैं। सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण उनको यह मौका दे रही है।

इस मन्त्रालय में मुनाफाखोर-और-गल्ला-चोर-पक्षी अफसरगन भरे पड़े हैं। वे नहीं चाहते कि सरकार गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ में लेकर उसको ठीक ढंग से चला सके। स्वयं यंत्री महोदय भी इस स्थिति में नहीं हैं कि वह नीतियों को ठीक तरह से निर्धारित कर सकें और जो नीतियाँ निर्धारित की जायें उनको अपने मन्त्रालय और अपने अधिकारियों के द्वारा कार्यान्वित करा सकें।

इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सरकार जनता को भूख, अभाव, अष्टाचार और भूसखोरी से बचाना चाहती है, तो वह पूरे हिन्दुस्तान में शहरों में राशनिंग व्यवस्था लागू करे, ताकि तमाम लोगों को निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में गल्ला मिल सके। देहातों में गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिये जो राशन की दुकानें खली हुई हैं, उनमें गल्ला मगलाई करने की व्यवस्था करे। अभी मैं बोकारो गया था। वहाँ इस्पात मजदूरों का सम्मेलन था जिसमें पूरे हिन्दुस्तान से आये ये दो लाख कर्मचारियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे उन्हें तथा अन्य मजदूरों को मस्ते दर पर गल्ला देने की व्यवस्था की जाये वरना हमारे उद्योग धधे ठप्प हो जायेंगे। रेलवे में भी हड़ताल की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि रेल कर्मचारी भी मस्ते दामों पर गल्ले की सहूलियत मांग रहे हैं। उनके लिये भी व्यवस्था की जाये। ताकि हमारी जो लाइफ लाइन है, आर्थिक व्यवस्था है, वह चले। जमीन का बंटवारा कीजिए। जिस सूबे से मैं आता हूँ वहाँ 28-28 हजार एकड़ जमीन रखने वाले लोग भरे पड़े हैं, 14-14 हजार एकड़ जमीन रखने वाले पड़े हुए हैं जो आप की हुकूमत में मंत्री रह चुके हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं फिर मंत्री बनने के लिए। तो जमीन का बंटवारा कीजिए। जोलने वालों को जमीन दीजिए। सभी सचमुच में गल्ले की पैदावार बढ़ेगी। मुनाफाखोरों के खिलाफ, गल्लाचोरों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। छात्रों को डी० आई० धार० में बन्द कर

दिया जाता है। अभी हमारे रेल के एम्प्लॉईज को सैकड़ों की तादाद में मिसा और डी० आई० धार० में जेलों में बन्द किया जा रहा है। तो, ये जो मुनाफाखोर और गल्लाचोर जो अष्टाचार करने वाले हैं ऐसे लोगों को जेलखानों में बन्द कीजिए, उन को डी० आई० धार० और मिसा में बन्द कीजिए तभी आप स्थिति में सुधार ला सकते हैं और जनता के असंतोष को दूर कर सकते हैं। उम असंतोष को दक्षिण पंथी ताकतों द्वारा इस्तेमाल करने से आप तभी रोक सकते हैं। जो लोग हिटलर मंत्रों को लेकर हिन्दुस्तान में संसदीय जनतंत्र की हत्या करना चाहते हैं तभी उन को आप शिकस्त दे सकते हैं। यदि आप की नीति सही रही तो इस काम में मजदूर मदद कर सकते हैं, किसान मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वर्तमान नीति बनी रही गल्लाचोर और पंजीपरस्त नीति तो फिर किसी की मदद नहीं मिलेगी और उन के असंतोष को हिटलर की विचारधारा को मानने वाले इस्तेमाल कर लगे। यदि आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं तो माग करूंगा कि आप को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप के मन्त्रालय को ओवरहॉल करने की जरूरत है। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और हम चाहेंगे कि आज आप इस बात की घोषणा करें कि आप अपनी अब की नीति में और कृषि की नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। तभी देश की स्थिति में सुधार होगा। जिन भावनाओं को अभी आपकी ही पार्टी के सदस्य भी आरूपायल जी ने पेश किया उन भावनाओं को

श्री राव सह्याय बाहे (राजमंडलाबा) :
 खाद्य और कृषि मंत्रा नय के प्रति बंबई सह्याय
 भूति की दृष्टि से देखना हूँ। मब से पहली बात
 मैं आप के सम्मुख यह उपस्थित करना चाहता
 हूँ कि इस मंत्रालय को मजबूत करने की
 आवश्यकता है। इस मंत्रालय के ऊपर खेती
 को ममाने और खाद्य उत्पादन करने का
 दायित्व है लेकिन मब में जो मोनिक बात है
 खेती के मबध में वह है पानी/सिंचाई के
 संबंध में पानी और बिजली ये दो मुख्य बातें हैं।
 निफ्ट इरीगेशन के काम में या कुएँ से सिंचाई
 के काम में बिजली की आवश्यकता है, इसलिए
 इस को भी इस में जोड़ दिया जाय। मैं इस
 मंत्रालय के हाथ मजबूत करना चाहता हूँ और
 यह गय देना है कि बिजली और खाद जो एक
 पेट्रो-केमिकल वाई-प्रोडक्ट है पेट्रोनियम का
 वह भी इस में जोड़ दिया जाय और पंचवर्षीय
 योजना के बड़े भारी प्रावधान में खेती को सब में
 ज्यादा मजबूत बनाया जाय। क्यों कि 25 वर्ष
 का अनुभव हमारा यह है कि हम मब मदस्य
 किमान के द्वारा चुन कर घाते हैं। किसान
 मन्नदाना है। एक नये परिवेश में एक नई
 परिभाषा में हम ने उनको सम्बोधित किया है।
 उन के पास जहा जमीन नहीं है वहा उन्हें
 जमीन बाटनी चाहिए। पानी नहीं है, वहा पानी
 पहुंचाना चाहिए। 3 हजार 6 सौ मिलियन एकड़
 वाटर फीट पानी हमारे यहा ऊपर से बरसता है।
 83 ऐसी नदियां हैं जो पेरिनियल वाटर देनी
 हैं, बराबर फूलो करती हैं जैसे नर्मदा है और
 भी नदियां हैं। गैजेट बेल्ट में इनना ज्यादा
 वाउन्ड वाटर है कि आप बिजली और कुएँ की
 सिंचाई का प्रावधान कर दें, टैंक इरीगेशन,
 लिफ्ट इरीगेशन इत्यादि की व्यवस्था कर दें तो

मब की कमी न रहे। मगर हमारा द्वारा कमेंटेशन
 इरीगेशन पर ही जाय तो हम मब के मामले
 में बड़ी धासानी में धात्व-निर्भर हो सके हैं।
 वह मिबिल्ट्री आप ने मलग कर रखी है।
 बिजली का इस से संबंध नहीं है। तो मेरा यह
 कहना है कि इस को एक काम्प्रोहेंसिव मंत्रालय
 बनाया जाय, मिनिस्टर इसके नीचे चार पाच
 या छ. क्यों न रहे, एक काम्प्रोहेंसिव मिनिस्ट्री
 बनानी चाहिए यह मेरी माग है।

25 वर्ष के अनुभव के बाद और चार
 पच वर्षीय योजनाओं के अनुभव के बाद ऐसा
 लगना है कि यही एक खेती का सेक्टर है जिस
 में मारे बेलफेग के काम को इकट्ठा कर देना
 चाहिए और 53 हजार करोड़ रुपये का जो
 प्रावधान पंच वर्षीय योजना में है उस का
 अधिक से अधिक व्यय, उस का अधिक से
 अधिक पोटेभियलिटी की खोज हम को खेती
 के सेक्टर में करनी चाहिए। यह नहीं भूलना
 चाहिए कि टोटल फारेन एक्सचेंज की मनिग
 का 79 प्रतिशत खेती के सेक्टर से मिलता है
 जूट चाय बरैरह में। लेकिन यह सेक्टर सब
 से ज्यादा नेग्लेक्टेड है। जहा आज लडके नाबो
 में निकल कर केनोकरी के लिए सहरो में घाते
 हैं मगर सिंचाई का पानी का, हाईड्रिड लीड
 का, मोडाउन का, खाद इत्यादि का सारा
 इनमाम कर दिया जाय, जमीन का बटवारा,
 एफोरेस्टेशन यह सब हो जाय तो क्यों लडके
 सहरो में घाएँ। फिर यह जो मोबरकसी ही
 रहा है नाबों से सहरो की तरफ वह बक जाव वा
 और किमान के हाथ मिट्टी से गीले हो जाएँ।
 किसान के हाथों की काम मिल जावेगा। सिंचाई
 की व्यवस्था का टाय प्रावरिटी हूँ देनी हीनी

बरना बहने नी का बेल जहाँ से चला वही का वही रहता है। 25 वर्ष के बाद आज 57 करोड़ की आबादी का मापना हमें करना पड़ रहा है। हर प्रातः काल हमारे सामने उन्हें भोजन देने की समस्या खड़ी है। यह साथ दायित्व किम पर है। यह दायित्व हम मंत्रालय पर अगदर है जो इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए किमान को हमें मजबूत करना होगा। पंच वर्षीय योजना में तमाम काम अगदर आप बन्द कर दें और 53 हजार करोड़ पूरा खेती के सेक्टर पर लमा दें तो हम में प्रोमैसिंग इंडस्ट्री को भी फायदा होगा; बिजनी पानी का समन्वय ही मकेगा और खेती का बंटवारा भी ही मकेगा। हम त्राहि माम त्राही माम के संदर्भ में मां बिआ दे हिं कह कर जो भिख मागते हैं, दो मिलियन टन रूस में मिल गया तो उभ की जय जय कर करने लगे, पी एन 480 मिल गया तो उसको जय जयकार करने लगे, उभ के बजाय इंटरनेसनल पानिटिकम में भी हमें सम्मान के साथ और गौरव तथा गरिमा के साथ रहने के लिए भी यह आवश्यक है। इनने बड़े गणतंत्र की बात हम करने हैं। 15 या 10 प्रतिजन का अभाव जो है किमान कहना है कि हम उसको पूरा करेंगे। किसान सही माने में अन्नदाता है। खोरबाजारी तो किसान करता नहीं, वह तो पैदा करता है। सही माने में वह अन्नदाता है और वही मय से ज्यादा भुखा है और उनी के पाम साधनों का अभाव है। इसलिए इस मंत्रालय को मजबूत करना चाहिए।

दुनिया भर में हमारा सब से बड़ा बन्ध तब है लेकिन हर चीज का उत्पादन हमारे यहाँ

क है। जापान और जर्मनी की देखिए। जापान की आबादी बस करोड़ की है और 6 करोड़ की आबादी जर्मनी की है। एका-रेस्टेशन से पांच सौ साइपांच सौ करोड़ रुपये की इनकम पर-एकड़ वहाँ आती है और हमारे यहाँ कितनी आनी है—21 रुपये। हमारे यहाँ 7 सौ पींड में 11 वा 12 सौ पींड पैडी काप का ईल्ड आता है, 7 सौ पींड वेडू का ईल्ड आता है जब कि दुनिया में 3 हजार या 3500 के करीब आता है। यह क्यों आता है? 200 पींड प्रति एकड़ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जापान करता है और जापान के भूगोल की स्थिति आप देखें तो केवल 16 प्रतिशत धरती पर खेती होती है। हमारे यहाँ 100 में 72 आदमी गांव में रहते हैं और 44 करोड़ एकड़ धरती हमारे पास है। 83 नदियां हैं। 3500 मिलियन एकड़ वाटर फीट पानी ऊपर से गिरता है। एषयोड रेनफाल है। नदियां हैं, पानी है, कुए हैं, जमीन के नीचे पानी है लेकिन आज केवल हल जोतने से खेती नहीं होती। आब विज्ञान के द्वारा खेती होती है। विज्ञान के बाध्यन से खेती होगी। उस के साधनों को बटोर कर किसान की सोनी को भर देने से खेती होगी।

हम सब किसान के अनुबन्धी हैं कि वे हम को चुन कर क भोजते हैं। इसलिए मैं बहुत उत्सुक था कि उन की तरफ से और नहीं तो कम से कम आसू तो बहाऊं जो बेचारे विपन्न हैं, अकिंचन हैं, भूखे हैं, साधनहीन हैं और उन्हीं से हम सब आशाएं करते हैं। अंकुश नियंत्रण, आब तय करना इत्यादि सबकुछ उन्हीं को सफर करना पड़ता है। इसलिए बड़ी आबतना से और

[श्री राम सहाय पांडे]

हृदय से जैते कि वारूपाल जी ने कहा, उन्होंने भ्रात्या से कहा, हम भ्रात्या और हृदय दोनों से बो ते हैं और बुद्धि से भी बोलते हैं और हमारा खयाल है कि पंच वर्षीय योजना जितनी हमारी फेन हुई उन को देखने हर पूरा का पूरा हम सेक्टर को समान लिया जाय नाकि भिक्षा देहि भिक्षा देहि को बान कभी नो समाप्न हा कभी ता उम मे विराम लग जाय ।

श्री राम रत्न शर्मा : मैं कल कृषि मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री मौर्य जी का इस मन्त्रालय की मांगो के बारे में भाषण सुन रहा था । वे एक योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई । उन्होंने कहा कि जिस तरह से गल्ले का उत्पादन बढ़ा है, उसी तरह से जनसंख्या भी बढ़ी है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण हम लोग ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि हम को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, कम से कम पचास फीसदी आवादी को आधा पेट रहना पड़ता है । इन्हीं शब्दों से या इस से कुछ हेर-फेर कर के उन्होंने यह बात कही थी, लेकिन उस का आशय यही था ।

श्रीमन्, बड़े ही आश्चर्य की बात है— 1947 के पहले वर्ष-कन्ट्रोल जैसी कोई बात नहीं थी, बरना आज हम में से बहुत से लोग यहाँ नहीं होते । यदि 1930 के पहले यहाँ वर्ष-कन्ट्रोल जैसी बात होती तो शायद बहुत से मिनिस्टर या बहुत से पुराने सदस्य जो यहाँ बैठे हैं, वे यहाँ पर नहीं होते । इस लिये अपनी असफलता को किसी पर डाल कर या किसी बाद-विशेष पर डालकर या प्रकृति पर दोष डेकर नहीं छिपाया जा सकता । अगर उन्होंने

प्रारम्भ के ही छोटी इरिगेशन योजनाओं पर ध्यान दिया होता, बड़े बड़े बांध बनाने के बजाय लिफ्ट-इरिगेशन या छोटे छोटे बांध बनाये जाते, नालों से पानी उठाया जाता, ट्यूब-वैल बनाये जाते तो आज जिस तरह से आवादी बढ़ी है, उसी तरह से उपज भी बढ़ती और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो परेशानी आज आप को हो रही है, वह परेशानी इस तरह से न होती ।

महात्मा गांधी जी ने भी इसी बात को पहले कहा था । आप सब लोग उन के रास्ते पर चलते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से बहुत से लोग हृदय की भाषा बोलते हैं । मुझे आश्चर्य होता है कि आप में से बहुत लोगों के पास हृदय भी है—अभी तक तो मैं समझता था कि आप लोगों के पास विभाग है, हृदय नहीं है लेकिन आज वारूपाल जी की बात सुन कर मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उन के पास भी हृदय है, उन के पास भी हरिजनो और गिरिजनो के बारे में सोचने के लिये दिल में दर्द है । मैं आप को अपने जिन्ने के हरिजनो की बात बताना हूँ—मेरे यहाँ हरिजनो को भूमि वाटी गई—5-6 बीघा या 10 बीघा भूमि उन को दी गई, लेकिन इतनी कम भूमि से क्या होगा । वादा जैसी जगह में जहाँ ऊसर और बजर जमीन है, वहाँ 5-6 बीघे का क्या अस्तित्व है । जैसा एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा—अगर आप चाहते हैं कि उन का कुछ भला हो तो 14-15 बीघे से कम जमीन उन को न दें, ताकि ये अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें, उस में भी बहुत से लोग उन को कब्जा नहीं देते हैं । इतनी जमीन उन को अवश्य मिलनी चाहिये जिस से उन का संचारा हो सकें । साथ ही साथ यह देखने की भी

जरूरत है कि उन को कब्जा मिले, उन को वोलों के लिये ऋण मिले, उन को खाद और बीज समय पर मिले—यदि आप ये सब बातें नहीं देखेंगे तो आप का यहाँ कहना फाइलों पर ही रह जायगा, उस का कोई फल निकलने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं डम मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हू।

श्री मूल खन्व डागा (पार्लो) : सभापति जी, 2 अक्टूबर, 1952 को प० जवाहर लाल नेहरु ने नागौर में एक दीपक जलाया था . .

श्री राजराज सिंह—कोटा (मालवाड)
1952 में मन्त्री 1-58 में।

श्री मूल खन्व डागा ठीक है, 1958 में। उस के बाद आप ने सामुदायिक विकास योजनाओं का जाल सारे हिन्दुस्तान में फैला दिया और आज 6 हजार सामुदायिक विकास योजनाएँ हिन्दुस्तान में काम कर रही हैं। इस का 79 प्रतिशत पैसा केवल सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होता है, बाकी 21 प्रतिशत में आप का एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है मैं इस प्रश्न का जवाब चाहता हू। यह जाल आप ने क्यों बिछाया था, इस का क्या परिणाम निकल रहा है—इन बातों का जवाब दे। ये लोकतांत्रिक इकाइया खत्म हो गई हैं, पंचायत राज्य भंग बाकी नहीं है। आप ने राजस्थान का 1965 का डेटा दिया है, 1965 से जो पंचायतें बँठी हैं, 9 साल हो गये उन के चुनाव नहीं हुए—क्यों (अव्यवधान)... हिमाचल प्रदेश में 1965 में चुनाव हुए . . .

श्री बीरबल सिंह (जंसी) : हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं।

श्री मूल खन्व डागा : यहाँ तो 1965 लिखा है—या तो यह डेटा गलत है या माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। मैं इन के झगडावा और भी कई आकड़े बतला सकता हूँ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) :
कर्णाटक में 1968 में हुए थे।

श्री मूल खन्व डागा : मेरे पीछे बैठे हुए मदन्य मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। इन सामुदायिक योजनाओं पर आप रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन इन का क्या लाभ हो रहा है। वहाँ डवलपमेन्ट ग्राफिसर रखे हुए हैं, वॉटरनीरी डाक्टर्स रखे हुए हैं—लेकिन ये क्या करते हैं। डाक्टरो के पास औजार तक नहीं हैं। सेनीटेशन इस्पेक्टर हैं—ये क्या करेगे गाव में जहाँ पानी ही नहीं है सेनीटेशन का क्या काम होगा। आप क्यों ऐसी रिपोर्ट देते हैं, डम से क्या फायदा है? इनको लिखनेवाले कौन हैं, क्या इन की गर्दन कभी सच्चाई के सामने नीची होती है, क्या रिपोर्ट आप देते हैं—ये लिखते हैं—

“The mobilisation of local resources through taxation by the Panchayati Raj institutions on their own effort, has been on increase”

आप के इन आकड़ों पर कोई विश्वास नहीं करता इन पंचायतों में कुछ ऐसे अमानिजिक तत्व घुस गये हैं जो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, 9 साल से जमे बैठे हैं। श्री बलबल राय मेहता जी ने जब अपनी रिपोर्ट लिखी थी तो उन्होंने कहा था कि इस के द्वारा देश के अन्दर जागृति का शखनाद फूक दिया जायगा, गाव का भ्रामनी अपने पैरो पर खड़ा हो सकेगा और वह समझेगा कि यह हिन्दुस्तान मेरा है, मैं हिन्दुस्तान को बनानेवाला हूँ। लेकिन ये सारी लोकतांत्रिक इकाइया खत्म हो गई और अब यह रिजल्ट निकला है—

“There has been a steady fall in voluntary contributions mainly due to the fall in the Government expenditure on community works and amenities.”

[श्री मूल बन्द हागा]

It was Rs. 4.5 crores, during 1968-67, Rs. 2 crores during 1967-68, Rs. 2.2 crores during 1968-69, Rs. 1.8 crores during 1969-70 and Rs. 2.2 crores during 1970-71."

आखिर आप ने इन सामुदायिक विकास योजनाओं को क्यों बना रखा है—इसलिये कि आप ने इन में बहुत अरुसरों को लगा रखा है। मैं पूछना हूँ कि आप हमारे जवान लड़कों के साथ क्यों जुलम कर रहे हैं, वे वहाँ अपनी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन का जीवन बिगड़ रहा है, सैकड़ों को लगा रखा है, लेकिन बरा पुछिये कि वे गाव में क्या करते हैं, उन के पास क्या काम है, उन का फक्शन क्या है? सामुदायिक विकास के द्वारा देश की उन्नति की, देश के विकास की जो कल्पना की गई थी—क्या वह पूरी हो रही है? आप ने वहाँ पोष्टिक आहार की योजना चलाई है महिला मडल बनाया है युवक मडल बनाया है प्रोग्राम जाने कितने मडल बना रहे हैं—मैं इन रिपोर्ट लिखने वालों में पूछना चाहता हूँ—क्या वे फील करते हैं कि यह महिला मडल क्या काम करता है। यह युवक मडल क्या काम करते हैं? क्यों आप दुनिया में घोषणा देना चाहते हैं? और यह सब बड़ा घोषणा तो अपने आप को है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य पंडित जी और श्री बलबन्तराय मेहता ने 1965 में सामुदायिक विकास का जो स्वप्न देखा था उसका क्या नतीजा होगा?

17.00 hrs.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F. A. AHMED): Sir, during the last three days, a large number of members have participat-

ed in the discussion on the Demands of my Ministry. I know that many more members are anxious to participate in this discussion. That only shows to what extent importance is attached to agriculture and the allied subjects in this House. I am very grateful to those hon. Members for the many valuable suggestions and observations which they have made in the course of this discussion. But, before I go to the various matters which have been raised in the course of this debate, I would like to point out that I have been relieved of my task to a great extent because of the valuable intervention made by my two colleagues, who have very effectively and in detail dealt with many of the points which have been raised by the hon. Members.

So far as the performance of the Agriculture Ministry is concerned, there have been doubts in the minds of the people that during the past few years no such development, no such progress and no such effective steps have been taken of which the Ministry or the Department can be proud of. I do not for the moment take the stand that all that has been done was right, that no mistakes were made and that there is nothing more to be done, so far as the programme of production and the development in various fields of agriculture are concerned. But I would like to point out that those people who make these allegations that nothing has been done in the past few years are completely blind to the facts and figures.

If we look to the production of foodgrains, we will find that even in the Fourth Plan, when we had two very bad drought years, our average production was much more than the average production of the Third Plan. I would not like to quote the figures which have already been mentioned by Shri Shinde...

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): We do not want figures; we want food.

SHRI F. A. AHMED: ... but I would like to point out that so far as even the worst year of the Fourth Plan is concerned, we had a production of about 95 million tonnes last year, which was the highest figure during the Third Plan period.

My hon. friend said, "We want food; we do not want figures." I would like to point out that even what production we have in our country is sufficient to go round to all the people ... (Interruptions) For the disappearance of foodgrains it is not the Agriculture Ministry which is responsible but it is the hon. Members on the opposite side.... (Interruptions).

SHRI PILOO MODY (Godhra): I want to find out whether he was blaming the C.P.I. who pushed him to take over wholesale trade in wheat (Interruptions)

SHRI F. A. AHMED: Whatever suits the hon. Member, he may say. He can also take that remark. That is also meant for him.

SHRI PILOO MODY: I don't take foodgrains.

SHRI F. A. AHMED: I am very glad to hear it.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): If you make the Opposition responsible for hoarding and black-marketing, that is not a proper statement.... (Interruptions).

श्री राज वल्लभ धर्मा : अग्नर मिनलस्टर शाहल को यह बात बलकुल लय है कल बलरोधी पक्ष बालों ने यह लब कलबा है तो उनके बललाफ मुकदमा कयों नहीं बललाते हैं अग्नर उनको बेल कयों नहीं बलबलते हैं ? इल तरह का स्टेटमेंट डैकर देल में यह बललाबरन कयों

पैदा करना बाहले है कल बलरोधी पक्ष बलबने बलल रहा है जबकल बलललब में वे बलपनी केल्योर को छलपाना बाहले है ।

SHRI F. A. AHMED: When the hon. Members had their say, not for a moment I disturbed them. But when I am saying something, I do not see any reason, any justification, why they should not listen to me.

What I was trying to point out was that if it had not been for the fact that, on the one hand, they were asking the producers not to part with grains and, on the other hand, they were asking others to encourage hoarding, etc. there would have been no shortage. Therefore, what I was saying was, if we take into consideration what we have been producing during the past few years, what production of foodgrains we have in our country is sufficient to go round to all the people provided two or three things are accepted.

Firstly, it has to be admitted that there is inequality in production in different parts of the country. There are some States which are surplus States and there are other States which are deficit States so far as production is concerned. About the States which are surplus, there has been an anxiety on the part of those surplus States not to part with the surplus which they have in their own areas so that it may be taken to deficit areas. That is one aspect which has to be taken into consideration.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Is it that Opposition parties are ruling in the various States? Is hoarding also because of the opposition?

SHRI PILOO MODY: Will you please tell us as to what was the per capita production in the Third Plan and what was the per capita production in the Fourth Plan.

SHRI F. A. AHMED: I have given the figures. Even with the present rate of production, the hon. Member will see that even if we give 150 kg per capita per year, the food production which we are producing today is sufficient to go round in the country. It is unfortunate that to-day the production is not uniform, all over the country and it is because of this inequitable distribution in production that there is some sort of an imbalance in the country which has taken place during the past few years...

SHRI PILOO MODY: But where is all the food going?

SHRI DARBARA SINGH (Hoshiarpur): To Mr. Piloo Mody.

SHRI F. A. AHMED: The hon. Member is proof of the fact as to where all the food is going.

SHRI PILOO MODY: I do not mind his cracking a joke about my size I never objected to it. But I am asking a serious question as to where all this food is going. If the Minister maintains that it is all due to hoarding, then first of all you should know what a hoarder is. Hoarder is a person who goes on hoarding. But nobody can go on hoarding, he has to unload sooner or later. Where has it all gone?

SHRI A. K. M ISHAQUE (Basirhat): It has gone underground.

SHRI PILOO MODY: If the per capita consumption is sufficient, as you say, then where has all the food gone?

SHRI F. A. AHMED: I am sure Mr. Piloo Mody is not without food any day. He is getting the food every day.

SHRI PILOO MODY: I have already told you that I do not eat your food. So, you better talk about somebody else.

MR. CHAIRMAN: Then let somebody else put the question.

श्री लालजी बाई : क्या सरकार ने मुनाफाखोरी और जमाखोरी के मामले खुदने नहीं देके है ?

MR CHAIRMAN: You first permit him to have his say. After he completes, I will give you a chance.. (Interruptions) I am on my legs. Why do you not listen to me? If I permit questions while the Minister is speaking, there will be no end to it. So, let him complete. After that, if some clarifications are still required, I will give you a chance

श्री लालजी बाई : मैं इसी मुद्दे पर प्रश्न करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

MR CHAIRMAN: This is very unfair when I have told you that I will give you a chance. If you still persist, I shall have to ask the Minister to continue and I shall not give you a chance even though I said I would give you.

SHRI F. A. AHMED: In the course of the speeches, some hon. Members had expressed the dissatisfaction that sufficient provision was not made in the Fifth Five-Year Plan. It was said that while in the Fourth Five-Year Plan there was a provision of about 20.7 per cent of investment, so far as the Fifth Five-Year Plan is concerned, the investment has been reduced to about 20.1 per cent of the entire expenditure which is to be incurred during the Fifth Five-Year Plan. I would like to point out that though it is true that we would have liked more expenditure so far as agricultural production programmes are concerned, this matter however has got to be viewed in the context of the limitation of resources, in the context of requirements for other very necessary items. I would have been certainly more happier if more percentage of allocation had been made to the Agriculture Ministry for the purpose of carrying out its programmes. But at the same time I would like to point out that the provision of Rs. 1672 crores in the Third Plan

has been increased to Rs. 3466 crores in the Fourth Plan and this has been now increased to Rs. 7411 crores in the Fifth Plan. Apart from that the hon. Members would have seen the provision made for assistance from financial institutions and it is hoped that only for the short-term loans both from cooperatives and commercial banks instead of Rs. 725 crores towards the end of Fourth Plan (1973-74) now Rs. 1700 crores would be available by the end of the Fifth Five-Year Plan.

And so far as medium and long-term loans are concerned, as against Rs. 1200 crores of the Fourth Plan, now Rs. 2400 crores would be available for medium and long-term loans.

Apart from that hon. Members would no doubt realise that there is a big investment made so far as development of power is concerned, so far as machinery manufacture with which Agriculture Ministry is concerned etc. A good investment has been made there as also in the matter of production of fertilisers. If we take all these factors into consideration we can see that within the limitations within which we have got to work, there is enough consideration which has been given to Agriculture Ministry; somehow or other if we could manage, we would have welcomed even a higher allocation; and that would have yielded much more results.

I would like to point out that we have to look to this question of increased production in the country not only with regard to production of food but also with regard to production of commercial crops and also with regard to what investment is made in the shape of various infrastructure facilities in the country. If we look to the development of irrigation, particularly minor irrigation, the position is this. We fixed a target of about 7 million hectares of land; not only have we achieved the target, but we have exceeded the target by one million hectares more.

Instead of 7 million hectares of land, we have provided irrigation to 8 million hectares of land.

It is true that to-day the irrigation facilities which we need for our country are not sufficient so far as minor irrigation is concerned. We have taken a policy decision in the right direction. In the last two years, we are spending more and more so far as minor irrigation is concerned.

If we take the percentage of minor, medium and major irrigations, you will find that to-day, under the minor irrigation, the area that has been covered is nearly 55 per cent while, under the medium and major irrigations, the area covered is only 45 per cent. This fact has also to be taken into consideration.

Then, some hon. Members have said that so far as development of agriculture is concerned, the most essential thing is about the implementation of land reforms. I entirely agree with the observations that have been made by them. I would like to point out that so far as enactments of laws are concerned, practically, all the States have enacted the laws as far as land-ceiling is concerned. Except in the case of Tripura and Manipur where legislation has not yet been enacted, in the case of all other States, Legislation has been enacted as has been pointed out by my colleagues. We have to know the surplus lands which are made available. Till to-day, I have not received replies from all the State. But, of the States, it appears that the surplus land likely to be available with them will be about 37 lakhs acres. I hope that arrangements will be made by those States to distribute those lands to the landless people as early as possible.

The other day one of the hon. Members, I think, Shri Bhattacharyya, suggested that the ceiling in so far as irrigated lands are concerned, should

[Shri F. A. Ahmed]

be about 25 acres. I would like to point out to him that only the other day, the Central Land Reforms Committee went into this question after receiving various suggestions from the State Governments and various other bodies. They decided that so far as ceiling is concerned, for the irrigated area where we can have two crops or more, the same should be between ten to eighteen acres; so far as lands where we have irrigation for one crop only, the ceiling should be 27 acres. So far as the unirrigated land is concerned, the ceiling should be within 54 acres. After taking into consideration informations received, it seems that about 37 lakhs of acres of land is likely to be surplus. The question put to me was: how much of the lands would be found to be surplus that would be available. If we accept the suggestion made by Shri Bhattacharyya, I can tell him that so far as we are concerned, we have no basis on which we can give our assessment. Whatever figures we have got, we have to depend on State Governments. I hope that they will take our advice into consideration and expedite the matter as early as possible so that the laws may be implemented and the benefit of giving lands to the landless people may be implemented as early as possible. I would however like to point out one thing. Having regard to the lands which have become surplus, the hon. Members must realise whether the distribution of the surplus land will satisfy the requirements of all the landless people in our country. Perhaps, the hon. Members have no idea so far as landless labourers are concerned. In our country, their number will not be less than 47 million. I do not know whether, to-day, we have sufficient surplus lands in order to distribute them to these people.

Some of my hon. friends have suggested very rightly that in the matter of distribution of land, we should take every care so far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are concerned and we should see they are given adequate land for the pur-

pose of earning their livelihood so that it may be possible for them to have proper existence in those hilly and backward areas. That is the instruction which has been conveyed to all the State Governments and I have no doubt that this instruction will be carried out. In the matter of distributing land they will give first preference to such landless people who are Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they are economic holdings so that it may be possible for them to have a suitable existence. As regards government land also we shall take it up with the State Governments that it should be distributed as early as possible.

Another important point to which my hon. friend Shri Bhattacharyya made some observations was that nearly 10 per cent of the farmers operate on two-third of the agricultural land and nearly 50 per cent of the production is under their influence. I do not know wherefrom he has got those figures. I would like to have source from which he has collected the same. So far as we are concerned we are having agricultural census in 1970-71 which is still in the course of preparation and after the figures from the census are available it will be possible to indicate what number of people and what category of people are holding what area of land.

Then the question was raised about the credit facilities. A large number of Members made observations that so far as credit facilities are concerned they were not adequate and particularly so far as the small and marginal farmers were concerned they were not getting the necessary assistance from the financial institutions or the commercial banks. May I, first of all, inform the hon. Members that so far as the credit facilities are concerned I have already indicated the figures which have to be provided both through the cooperatives and commercial banks as a short-term, medium term and long-term loan and I hope that these credit institutions will pay their part

properly and see that these facilities are provided to the cultivators as early as possible. The action taken by various institutions is under continuous review and I am taking up the matter from time to time with the Finance Ministry to see that the policy laid down in this respect is fully implemented by these credit institutions. I would like to point out one thing that we have indicated to these institutions that so far our policy is that it has to be production oriented, that is, credit has to be provided to the people not on any other basis except on the basis that whatever programme comes before them they should examine whether it is production oriented or not. If it is production oriented then they have to see particularly so far as the small farmer and the weaker sections are concerned that they are not troubled with the requirements of mortgaging their land or providing any security. We have said for loans upto two to three thousand they need not ask for any security. They should straightaway give these loans without the insistence of mortgage and security.

We have also said that so far as the small farmers and other weaker sections are concerned, they should also fix lower margin and longer payment schedule etc. so that it may be possible for them to return these loans without any difficulty.

Therefore, I would like to point out that all these measures which we have undertaken whether in the direction of irrigation or in the direction of providing credit facilities, are measures which will help in increased production in our country, whether it be of foodgrains or of other commercial crops.

But I would like to point out that there is a constraint so far as fertiliser is concerned. During the past few years we have noticed that the

requirement of fertilisers is increasing beyond our capacity to meet it. For 1973-74, our capacity to produce indigenous fertilisers was 22 lakh tonnes. But unfortunately, in spite of our effort, for various reasons such as power shortage, labour strikes and various other things, our production of both kinds of fertilisers, nitrogenous as well as phosphatic, was not more than 13 lakh tonnes. Therefore, while we have a capacity of about 22 lakh tonnes, we could get only about 13 lakh tonnes of fertilisers.

In regard to the fertilisers to be imported from outside, at the last moment, the contract had to be cancelled even though we had increased the price and given them more price than what had initially been agreed upon. Because of the West Asian crisis, they were not able to manufacture fertilisers in their own country and because of this difficulty they were not able to keep up the contract, and therefore, we were not in a position to meet the requirement of the rabi crop during this year, with the result that our crop has been affected thereby.

So far as kharif is concerned, I would like to point out that in spite of this difficulty, we have somehow or other been able to make arrangements so far as the requirement for the kharif crop is concerned. The States had asked for 44 lakh tonnes of fertilisers only for the kharif crop. We went into the figures and after examining the requirements of every State on the basis of their previous performance and on the basis of their production with high-yielding varieties and other varieties, we have been able to make arrangements. But we are still on the look-out and we are still making an effort to see how to make up the requirement so far as the rabi of 1974-75 is concerned.

In this connection, a question was raised by my hon. friend from Andhra

[Shri F. A. Ahmed]

Pradesh that we gave them inadequate quantity of fertilisers. I would like to point that there is a misgiving in the minds of certain people that we are not being fair to some of the States and to some States we give a higher quantity of fertilisers than is necessary. What we are doing is this. Formerly, we used to distribute fertilisers for the kharif crop on the basis of 17 per cent increase over what we had given last year, and in the case of rabi an increase of 22 per cent over what we had given last year. But now we have changed that pattern. Now, we take into consideration the quantity consumed by every State and the production programme given by each state and on that basis we calculate the quantity required for every State and make the allocation out of what is available to us, and on that basis, we distribute the fertilisers. The Minister from Andhra Pradesh had come and pointed out some mistake. Unfortunately, the mistake was not on the part of the Central Government but it was on the part of the State Government because they had indicated that the area under the high yielding variety was only 7 lakh acres but later on he said that the area was 13 lakh acres. We verified and found that it was a bona fide mistake, and we have given them a further increase: about 10,000 tonnes more fertiliser has been given to Andhra Pradesh, and I hope that it will be possible for them to meet their requirement with this.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Can you not link it up with procurement at the farmers' level and at the State level?

SHRI B. V. NAIK: Why not link it up with effective demand?

SHRI F. A. AHMED: So far as distribution of fertiliser is concerned, as hon members are aware, I have control over fertiliser which is the Pool fertiliser which is imported from foreign countries. I have laid down as a policy that the entire quantity

will be given out of that quota to the State Governments and the State Governments have been instructed to distribute it through co-operative societies. So far as fertiliser which is produced in the country is concerned, I took up this matter with the Ministry of Petroleum and Chemicals and they have agreed that 50 per cent of the indigenously manufactured fertiliser will also be given to the States for distribution through the co-operative societies, but the other 50 per cent will have to be distributed through individuals.

AN HON. MEMBER: Why?

SHRI K. SURYANARAYANA: The Ministry of Petroleum and Chemicals is not the producer of food. You are responsible to the House for food production.

SHRI F. A. AHMED: They say they are in a difficulty because under the terms on which these units were set up, one of the conditions was that this will also have to be distributed through individuals. The Ministry is looking into the matter and will see to what extent they can have this changed so that it may be possible for them to see that this is also distributed through co-operatives (*Interruptions*).

SHRI K. SURYANARAYANA: You have changed the Constitution..

MR. CHAIRMAN: I have not permitted any questions now. If you have any question, I will permit you later on.

SHRI F. A. AHMED: I think it will be better for hon. members to raise this question when my colleague, the Minister of Petroleum and Chemicals, is here. They can persuade him to have this 50 per cent also distributed through co-operatives (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: Yes are a Cabinet Minister. You should do it.

SHRI F. A. AHMED: As for the other question which some hon. members raised that it should be linked

up with procurement, this is for the State Governments to manage. If they can manage it, I have no objection.

SHRI BHOGENDRA JHA (Jaunagar) The whole sales can manage it. Why not hand over the country to them?

SHRI F. A. AHMED: No question of wholesalers.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Food has been handed over to the wholesalers and Agriculture to the State Ministries. Why not dissolve the Ministry?

SHRI F. A. AHMED: I would like to point out that in spite of these difficulties we are making an effort. But we have to depend to a certain extent on the vagaries of the weather. We have to depend also on circumstances which are not within our control. But I can say that if nothing goes very seriously wrong, we are in the right direction of having increased production in the country; given good weather, good monsoon, it was possible for us to have a very good khariff crop. Whatever target we had fixed had almost been achieved. I have no doubt that so far as the rabi crop is concerned, in spite of these difficulties, we shall be very near the target which we have fixed. But after two bad years, one after the other particularly when our previous buffer stock had been exhausted, there have been difficulties so far as availability of foodgrains in the country is concerned. But let us hope that we have a good monsoon next time and also one or two good rabi crops and then that will help us out of our difficulties.

Now, some hon. Members have raised the question about the crash scheme for rural employment. An hon.

Members are aware, this scheme was taken up in the year 1971, and it was a three-year scheme. The idea was that through this scheme employment in the rural areas should be generated and at least employment should be provided to about 1,000 people in every district. Also, the idea was that in that process some infra-structure should be created in the rural areas in the direction of construction of roads, minor irrigation, and so forth. Hon. Members have insisted that this crash scheme for unemployment should be continued, but as it was a fourth five year Plan scheme, a Centrally-sponsored scheme that is not proposed to be continued during the fifth Plan. The reason is that under the Plan, they are providing Rs 500 crores for the construction of rural roads. Therefore, they say that when a provision is being made for a programme like the drought prone area programme, dry area programme, construction of rural roads programme and also the minimum need-based programme, there is no necessity for extending this programme. That difficulty is there, and so this scheme will not be continued in the fifth five year Plan period.

So far as the drought-prone area programme is concerned, that also has been taken up in many of our districts. I would like to point out that last year, on account of the limitation on our resources, our expenditure on this programme has been cut down from Rs 100 crores to about Rs 81 crores and that is why there is some complaint from some of the States. I think for the next year we are still waiting to know what amount would be available. But this is a very useful programme and as some of our areas are areas where you have either no rain or scanty rain, it is desirable that this programme should also be continued but should also be extended so that the difficulty of the people in those areas may be met. This is so far as agricultural production is concerned.

[Shri F. A. Ahmed]

I would now like to revert to the question of food for a while. Though many Members have not made many observations so far as food is concerned, I would like to take this opportunity of removing some doubts and misgivings which have been expressed by some of the hon. Members. It was said that we have not been able to give an adequate price to the cultivators. First of all, I would like to point out that before we took the decision of fixing the price of Rs. 105 per quintal for wheat, we had before us the cost of production figures prepared by the Agricultural Universities in Uttar Pradesh and Punjab and also other figures and on that basis we thought that the price which we have fixed covered the cost of production. Even taking into consideration the fact that this was considered to be a suitable price in the year 1970-71 when, at that price, the cultivator was not able to sell his wheat to a private grain dealer and had to come to us to sell it and at that time he did not get more than Rs. 65 to Rs. 66 from the grain dealers—even taking that into consideration—and adding to that the rise in the cost since that period to this period which comes to about 37 per cent or 38 per cent, I personally feel that the price which has been given so far as wheat is concerned will not only meet the cost of production of the cultivator, but also will give him some incentives, some profits for the purpose of increasing the production from year to year. Some Members have said that this price is not adequate. I do not know what the hon. Members want. On the one hand, those very Members say that the price is not adequate. On the other hand, they are opposed to the increase in price so far as the consumer is concerned. I do not understand how they can have both the ways. If the price to the cultivator has to be increased, because it does not meet the cost of production, the consumer has to take the grain at a higher price.

In fact, we are very grateful to our farmers in the country for the very

valuable work which they have been doing in increasing our production. They are our back-bones and there is nothing that we will not do to encourage the farmers in our country. We want that they should be given all the necessary assistance and all the necessary help so far as they are concerned. We would also ask them that they should also try not only to take advantage of the various facilities which the Government are providing, but they should also attend to crop management. A good deal of increase in production and increase in productivity depends on crop management and that has been shown by the farmers in very progressive areas like Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh etc. Wherever farmers have given personal attention to crop management, productivity has increased.

Unfortunately, my friend Mr. Mavalankar is not here. The other day, he raised a very pertinent question, what has been the effect of intensive area development programme which we have taken up in the year 1962 or 1963. I would like to point out to him that it is true that we took up that programme to begin with under foreign aid. Now, the programme is being continued in some of the States, and whatever has been done in some of those States, I think, is something of which we can be proud of. I would mention only one district in Punjab, that is, Ludhiana. There, the yield of wheat has been 33 quintals per hectare, which is even higher than the average yield in the United States. This has shown that if they are given an opportunity, they can surpass the record set in other countries. Today, our average yield of wheat is about 13 or 14 quintals. If, today, our country, particularly those wheat growing areas like Punjab, Haryana, UP, Madhya Pradesh and Bihar can take up their yield to about 33 quintals per hectare, you can see what production of wheat we can have in our country. There is no reason why we should not be able to do it. During the past few years, we have almost doubled our wheat pro-

duction. We are proceeding in that direction. We are trying to help these areas by providing facilities for irrigation, by giving them as much fertiliser as possible, and wherever chemical fertiliser is not available, we are asking them to mix it with organic fertiliser.

SHRI M RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): What about the destruction of forests?

SHRI F. A. AHMED: So far as the price is concerned, we consider that it is adequate. While we are trying to help the farmers, I would very strongly appeal to them that they should help us, help the State Governments, help the Central Government, by bringing all their produce to the mandis and give them to the Government for the purpose of purchase.

Here I would like to point out that if there is a farmer or producer who wants to take out the produce to Maharashtra or West Bengal in order to get a higher price, I have no objection. I will not stand in his way. But he will have to take a licence from me, take permission from me and give me half the foodgrains. If they really want to be helpful to the consumers, they can do that, but they should take permission from me. (Interruptions) an hon Member has asked as to who will give the licence. The order has to be issued by us and the licence has to be given by the State Government. I hope the State Governments will co-operative with us in this matter.

So far as the Tamil Nadu Government is concerned, it has raised a very important matter about the Bill which it has sent us for our approval, regarding the Essential Commodities Act. Since we are ourselves bringing an amendment to the Essential Commodities Act, which we hope to place before this House during this session, where we want to tighten the provisions dealing with hoarders and so on, I hope that will

serve the purpose which the Tamil Nadu Government has in view.

The hon. Member, Shri Swaminathan, from Tamil Nadu said that he was very much grieved that we had instructed the State Governments to remove the restriction on movement of coarse grains. The hon. Member must realise that we are one country and we must have an all-India outlook. It is not enough for us to think in terms of only one state.

SHRI C T. DHANDAPANI (Dharampuram): Why this is applied only to foodgrains? What about water supply? The Central Government will not interfere there. They interfere only in the case of food.

SHRI F. A. AHMED: Even though we may be coming from different parts of the country, we are all Indians. So, it is necessary for all of us that we should not do anything which is likely to endanger or damage the unity of India. That is one aspect which we have to keep in mind. Whether we come from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh or Tamil Nadu, we should not be parochial. If we have surplus foodgrains, we should try to help other States which are deficit. If we do not take that view, then you can realise what difficulties we can have in our country and how injurious it can be to our cause, to our interest and to our integrity. Therefore, I would make an appeal to Tamil Nadu. They wanted an assurance from me, so far as rice is concerned, whether I am going to remove the existing arrangement of zonal restrictions. I will not do anything of the sort. But I would like Tamil Nadu also to help me in that connection and see that whatever has been fixed should be given to me for the purpose of distribution to other States. I hope, my hon. friend will convey our sentiments.

SHRI C. T. DHANDAPANI: This is not the correct approach that he is making.

SHRI F. A. AHMED: I knew that his Chief Minister, whenever we have asked for assistance, has given that assistance. I have no doubt that whatever has been agreed upon will be ultimately given by him. Now, they have a good crop. If they can certainly give us rice according to an arrangement fixed upon, that will be helpful to us for distribution from the Central pool.

There are many other points which have been raised by some of the hon. Members. I would like to point out one thing that some of the observations that have been made do not really concern us. They really concern the State Governments. But I would like to tell the hon. Members that we have taken note of those points and we shall convey the views of the hon. Members so that the suggestions are accepted by the State Governments and implemented in the interest of the country.

Before I conclude, I would like to point out that there should be no misgivings so far as our new policy of take-over is concerned. I would like to point out the three main objectives in our policy which we adopted last year and which we have modified this year. What are the three main objectives? The first main objective is that the producer should get a proper price so that he may have the incentive for increasing production in our country. The second objective is that the foodgrains in our country should be available throughout the country. The third objective is that so far as vulnerable sections of our society are concerned, they must be supplied with foodgrains at a reasonable price. These are the main objectives of our policy.

So far as the procedure is concerned, it is the means, not an end in itself. We tried a particular method. Whatever may be the reason, that did not help us in meeting these objectives. Therefore, we are trying another procedure. I would like to seek the cooperation of the hon. Members

to see that these objectives are not interfered with so that it may be possible for us to make foodgrains available to all the people throughout the country without much difficulty. There was no justification for foodgrains being available in one State at about Rs. 100 or Rs. 105 or Rs. 110 and in another State at about Rs. 250 or Rs. 300 a quintal.

I hope, the steps that we have taken will enable us to remove the distortion and make the foodgrains available to all the people throughout the country. I can say this much that there is no agreement between grain dealers and ourselves. There is no understanding or any agreement whatsoever. They have to function under a licence under certain restrictions, under certain terms and conditions. Whenever those conditions are not implemented or there is any breach of those conditions, those licences will be cancelled. And necessary action will be taken under the law. Therefore, I would like the hon. Members to realise that to-day we are faced with a difficult situation and I am sure that it is in the interests of all of us to whichever Party we may belong that we should try to see that these difficulties are removed as early as possible. I will seek their co-operation and hope that they will be able to rise above their politics so far as this matter is concerned and that they will give their fullest co-operation.

18 00 hrs.

SEVERAL HON MEMBERS ROSE—

MR CHAIRMAN: There is no time left. I will permit only Shri Lalji Bhai to put a question. I have promised him. ..(Interruptions) Shri Lalji Bhai.

श्री लालजी भाई: मैं जानना चाहता हूँ राजस्वान प्रदेश में सन् 1968 से लगातार 1971 तक जिन आदिवासियों का कब्जा है

जमीन पर और सरकार उनके ऊपर अतिक्रमण के मुकदमे चला रही है, अभी तक इतने सालों से उनका फैसला नहीं हो रहा है और उन आदिवासियों से एक बीघे पर प्रति वर्ष पांच सौ रुपये लेकर उनको बेदखल किया जा रहा है जिसके कारण लोगों में बहुत रोष बढ़ रहा है, क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार को निर्देश देंगे कि उन मुकदमों के फैसले जल्दी किये जायें और उन्हीं लोगों के नाम से वह जमीन एलाट या रेग्युलराइज की जाये ?

SHRI F A AHMED Let the hon. Member send it to me in writing and I will forward it to the State Government

MR CHAIRMAN Now, there are a number of cut motions. If the hon. Members agree I will put them all together to the vote of the House

SHRI BHOGENDRA JHA My cut motion No 1 may be put to vote separately

MR CHAIRMAN Now, the question is

"That the demand under the head 'Department of Agriculture' be reduced to Re 1"

[Failure to implement the amended land ceiling laws and distributing the surplus land among the landless particularly in the Union territories (1)]

The Lok Sabha divided.

Division No. 12]

[18 08 hrs.

AYES

Banerjee, Shri S M

Bhaura Shri B S

Dandavate, Prof Madhu
Dhandapani, Shri C. T.
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Halder, Shri Krishna Chandra
Huda, Shri Noorul
Jha, Shri Bhogendra
Mehta Shri P M.
Mukherjee, Shri Samar
Pajanor, Shri Aravinda Bala
*Shastri, Shri Ramavatar

NOES

Ahmed, Shri F A
Bhanamali Babu Shri
Baiupal, Shri Panna Lal
Basappa Shri K
Bramatari, Shri D
Bhargava Shri Basheswar Nath
Bhatia Shri Raghunandan Lal
Brij Raj Singh-Kotah, Shri
Chakleshwar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chikkahingaiyah Shri K
Daga, Shri M C
Darbara Singh, Shri
Das, Shri Anadi Charan
Dumada Shri L K.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ganesh, Shri K R
Gangadeb, Shri P
Gavit Shri T H
Gill, Shri Mohinder Singh
Gomango Shri Giridhar
Gopal Shri K
Gotkhinde Shri Annasaheb
Gowda Shri Pampan

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly.

Hari Kishore Singh, Shri
 Ishaque, Shri A. K. M.
 Jadeja, Shri D. P.
 Jha, Shri Chiranjib
 Kakodkar, Shri Purushottam
 Kamble, Shri T. D.
 Kapur, Shri Sat Pal
 Karan Singh, Dr.
 Kedar Nath Singh, Shri
 Kotrashetti, Shri A. K.
 Kushok Bakula, Shri
 Mahishi, Dr. Sarojini
 Mandal, Shri Jagdish Narain
 Mandal, Shri Yamuna Prasad
 Manhar, Shri Bhagatram
 Maurya, Shri B. P.
 Mohsin, Shri F. H.
 Murmu, Shri Yogesh Chandra
 Naik, Shri B. V.
 Negi, Shri Pratap Singh
 Oraon, Shri Kartik
 Oraon, Shri Tuna
 Painuli, Shri Paripoornanand
 Pandey, Shri Damodar
 Pandey, Shri Krishna Chandra
 Pandey, Shri Narsingh Narain
 Pandey, Shri R. S.
 Paswan, Shri Ram Bhagat
 Patnaik, Shri J. B.
 Peje, Shri S. L.
 Pradhani, Shri K.
 Purty, Shri M. S.
 Raghu Ramaiah, Shri K.
 Rai, Shrimati Sahodrabai
 Raj Bahadur, Shri
 Ram Dhan, Shri
 Rao, Shri P. Ankineedu Prasad
 Rathia, Shri Umed Singh
 Raut, Shri Bhola
 Reddy, Shri M. Ram Gopal
 Reddy, Shri P. Ganga
 Rohatgi, Shrimati Sushila

Rudra Pratap Singh, Shri
 Sadhu Ram, Shri
 Saini, Shri Mulki Raj
 Saksena, Prof. S. L.
 Samanta, Shri S. C.
 Sankata Prasad, Dr.
 Sarkar, Shri Sakti Kumar
 Savant, Shri Shankerrao
 Shailani, Shri Chandra
 Shankaranand, Shri B.
 Sharma, Dr. H. P.
 Sharma, Shri Nawal Kishore
 Shastri, Shri Biswanarayan
 Shastri, Shri Sheopujan
 Shenoy, Shri P. R.
 Shinde, Shri Annasaheb P.
 Sinha, Shri Dharam Bir
 Sohan Lal, Shri T.
 Sokhi, Shri Swaran Singh
 Surayanarayan, Shri K.
 Unnikrishnan, Shri K. P.
 Verma, Shri Sukhdeo Prasad
 Vikal, Shri Ram Chandra
 Virbhadra Singh, Shri
 Yadav, Shri N. P.

MR. CHAIRMAN: The result of the division is:

Ayes: 12; Noes: 91.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put Cut motions Nos. 2, 12 and 15 were put and negatived

Cut motions Nos. 2, 12 and 15 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put Cut motion No. 16 to the vote of the House.

Cut motion No. 16 was put and negatived:

SHRI BHOGENDRA JHA: Cut motion No. 17 may be put separately.

MR CHAIRMAN: As the Lobbies have already been cleared, I am not asking for the clearance of the Lobby again, if the House agrees to it

Now the question is.

'That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1'.

[Failure to take over entirely wholesale trade of all foodgrains and to procure entire marketable surplus through a system of graded levy to ensure a regular supply at controlled prices to the weaker sections in rural areas and vulnerable sections in urban and industrial areas (17)]

The Lok Sabha divided.

Division No. 13]

[18 11 hrs.

AYES

Banjara, Shri S M
Bhauria, Shri B S
Dandavate, Prof Madhu
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Haldai, Shri Krishna Chandra
Jha Shri Bhogendra
Mehta Shri P M
Mukherjee, Shri Samar
*Shastri, Shri Ramavatar

NOES

Ahmed, Shri F A
Banamali Babu, Shri
Barupal, Shri Panna Lal
Basappa, Shri K
Bhargava, Shri Basheshwar Nath
Bhatia, Shri Raghunandan Lal

Brij Raj Singh-Kotah, Shri
Chakrishwar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chilkalingaiah, Shri K
Daga, Shri M. C.
Darbara Singh Shri
Das, Shri Anadi Charan
Dumada, Shri L K
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ganesh, Shri K R.
Gangadeb, Shri P
Gavit, Shri T H
Gill, Shri Mohinder Singh
Gomango, Shri Gindhai
Gopal, Shri K
Gotkhinde, Shri Annasaheb
Govda, Shri Pampan
Hari Kishore Singh, Shri
Ishaque Shri A K M
Jadeja Shri D P
Jha Shri Chiranjib
Kerkodkar, Shri Pulushottam
Kherke, Shri T D
Khopal, Shri Sat Pal
Karan Singh, Dr
Kedar Nath Singh, Shri
Kotrasetti, Shri A K
Kushok Bakula Shri
Mahushi, Dr Sarojini
Mandal, Shri Jadish Narain
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Manhar, Shri Bhagatram

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly.

Maurya, Shri B. P.
 Mohain, Shri F. H.
 Murmu, Shri Yogesh Chandra
 Negi, Shri Pratap Singh
 Oraon, Shri Kartik
 Oraon, Shri Tuna
 Painuli, Shri Paripoornanand
 Pandey, Shri Damodar
 Pandey, Shri Krishna Chandra
 Pandey, Shri Narsingh Narain
 Pandey, Shri R S
 Paswan, Shri Ram Bhagat
 Patnaik, Shri J. B
 Peje, Shri S L.
 Pradhani, Shri K
 Purty, Shri M S

 Raghuramaiah, Shri K
 Rai, Shrimati Sahodrabai
 Raj Bahadur, Shri
 Ram Dhan, Shri
 Rao, Shri P Ankinedu Prasad
 Rathia, Shri Umed Singh
 Raut, Shri Bholu
 Reddy, Shri M Ram Gopal
 Redy, Shri P Ganga
 Rohatgi, Shrimati Sushila
 Rudra Pratap Singh, Shri
 Sadhu Ram, Shri
 Saini, Shri Mulki Raj
 Sakanna, Prof S L
 Samanta, Shri S C
 Sankata Prasad, Dr
 Sarkar, Shri Sakti Mumar
 Savant, Shri Shankarrao
 Shailani, Shri Chandra
 Shankaranand, Shri B
 Sharma, Dr H P

 Sharma, Shri Nawal Kishore
 Shastri, Shri Biswanarayan
 Shastri, Shri Sheopujan
 Shenoy, Shri P R.

Shaunde, Shri Annasaheb P.
 Sinha, Shri Dharam Bir
 Sohan Lal, Shri T.
 Sokhi, Shri Swaran Singh
 Suryanarayana, Shri K.
 Unnikrishnan, Shri K. P.
 Verma, Shri Sukhdeo Prasad
 Vikal, Shri Ram Chandra
 Virbhadra Singh, Shri
 Yadav, Shri N P.

MR CHAIRMAN: The result* of the division is

Ayes: 9, Noes: 89:

The motion was negatived.

MR CHAIRMAN: Do you want to press any other Cut Motion?

SHRI S M BANERJEE: Let the Lobbies be cleared because many Members might wish to vote for that

MR CHAIRMAN: Let me first put the other cut motions to the vote of the House

I will put Cut Motions Nos. 19 to 23, 39 to 43, 49, 51 to 53, 54 to 59, 60 and 61, 69 to 71 and 74 to 81 to the vote of the House

The cut Motions were put and negatived

MR CHAIRMAN: I shall put Cut motion No 72 to the vote of the house

SHRI S M BANERJEE: I would like to press for a division

MR CHAIRMAN: Let the Lobby be cleared

Now, the question is:

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1."

[Failure to nationalise sugar mills in U.P and Bihar (72)].

*Shri Noorul Huda also recorded his vote for AYES.

Division No. 14

18.18 hrs.

Gill Shri Mohinder Singh

Gomango, Shri Giridhar

Gopal, Shri K.

Gotkhinda, Shri Annasabeb

Gowda, Shri Pampan

Hari Kishore Singh, Shri

Ishaque, Shri A. K. M.

Jadeja, Shri D. P.

Jha, Shri Chiranjib

Kakodkar, Shri Purushottam

Kamble, Shri T. D.

Kapur, Shri Sat Pal

Karan, Singh. Dr.

Kedar Nath Singh, Shri

Kotrashetti, Shri A. K.

Kushok Bakula, Shri

Mahishi, Dr. Sarojini

Mandal, Shri Jagdish Narain

Mandal, Shri Yamuna Prasad

Manhar, Shri Bhagatram

Maurya, Shri B. P.

Mohsin, Shri F. H.

Murmu, Shri Yogesh Chandra

Naik, Shri B. V.

Negi, Shri Pratap Singh

Oraon, Shri Kartik

Oraon, Shri Tuna

Painuli, Shri Paripoornanand

Pandey, Shri Damodar

Pandey, Shri Krishna Chandra

Pandey, Shri R. S.

Paswan, Shri Ram Bhagat

Patnaik, Shri J. B.

Peje, Shri S. L.

AYES

Banerjee, Shri S. M.

Bhaura, Shri B. S.

Dandavate, Prof. Madhu

Dhandapani, Shri C. T.

Goswami, Shrimati Bibha Ghosh

Halder, Shri Krishna Chandra

Huda, Shri Noorul

Jha, Shri Bhogendra

Mehta, Shri P. M.

Mukherjee, Shri Samar

Sakesena, Prof. S. L.

*Shastri, Shri Ramavtar

NOES

Ahmed, Shri F. A.

Banamali Babu, Shri

Barupal, Shri Panna Lal

Basappa, Shri K.

Basumatari, Shri D.

Bhargava, Shri Basheshwar Nath

Bhatia, Shri Raghunandan Lal

Brij Raj Singh-Kotah, Shri

Chakleshwar Singh, Shri

Chandrakar, Shri Chandulal

Chikkalingaiah, Shri K.

Daga, Shri M. C.

Darbara Singh, Shri

Das, Shri Anadi Charan

Dumada, Shri L. K.

Dwivedi, Shri Nageshwar

Ganesh, Shri K. R.

Gangadeb, Shri P.

Gavit, Shri T. H.

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly.

Pradhani, Shri K.
 Purty, Shri M. S.
 Raghun Ramasiah, Shri K.
 Rai, Shrimati Sahodrabai
 Raj Bahadur, Shri
 Ram Dhan, Shri
 Rao, Shri P Ankinreedu Prasada
 Rathia, Shri Umed Singh
 Raut, Shri Bhola
 Reddy, Shri M Ram Gopal
 Reddy, Shri P. Ganga
 Rohatgi Shrimati Sushula
 Rudra Pratap Singh, Shri
 Sadhu Ram, Shri
 Samanta, Shri S C.
 Sankata Prasad, Dr
 Sarkar, Shri Sakti Kumar
 Savant Shri Shankarrao
 Shastri, Shri Chandra
 Shankaramand, Shri B
 Sharma, Dr H P
 Sha Shri Nawal Kishore
 Shastri Shri Biswanarayan
 Shastri, Shri Sheopujan
 Shenoy, Shri P R.
 Shinde, Shri Annasaheb P.
 Sinha, Shri Dharam Bir
 Sohan Lal, Shri T
 Sokhi, Shri Swaran Singh
 Suryanarayana Shri K
 Unnikrishnan, Shri K P.
 Verma, Shri Sukhdeo Prasad
 Vikal, Shri Ram Chandra
 Virbhadra Singh, Shri

MR CHAIRMAN The result of the division is:

Ayes: 12, Noes 87.

The motion was negatived.

MR CHAIRMAN: I shall put cut motion No 73 to the vote of the House

Cut motion No 73 was put and negatived.

MR CHAIRMAN: The question is

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos 1 to 10 relating to the Ministry of Agriculture"

The motion was adopted

(The motions for Demand for Grants, which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—
 (Ed))

DEMAND NO 1—DEPARTMENT OF
 AGRICULTURE

That a sum not exceeding Rs 136,00,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Agriculture'

DEMAND NO 2—DEPARTMENT OF
 AGRICULTURAL RESEARCH AND
 EDUCATION

'That a sum not exceeding Rs 6,50,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

*Shri Narsingh Narain Pandey also recorded his vote for NOES

the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Agricultural Research and Education'."

DEMAND NO. 3—AGRICULTURE

"That a sum not exceeding Rs. 65,23,26,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 3,06,60,42,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Agriculture'."

DEMAND NO. 4—FISHERIES

"That a sum not exceeding Rs. 6,17,97,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 1,06,50,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Fisheries'."

DEMAND NO. 5—ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY DEVELOPMENT

"That a sum not exceeding Rs. 26,41,11,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 2,40,33,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Animal Husbandry and Dairy Development'."

DEMAND NO. 6—FOREST

"That a sum not exceeding Rs. 7,49,00,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 45,83,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Forest'."

DEMAND NO. 7—PAYMENTS TO INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURE RESEARCH

"That a sum not exceeding Rs. 29,11,80,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Payments to Indian Council of Agricultural Research'."

DEMAND NO. 8—DEPARTMENT OF FOOD

"That a sum not exceeding Rs. 100,10,53,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 10,99,83,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Food'."

DEMAND NO. 9—DEPARTMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT

"That a sum not exceeding Rs. 24,65,11,000 on revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Community Development'."

DEMAND NO. 10—DEPARTMENT OF CO-OPERATION

"That a sum not exceeding Rs. 5,53,68,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 17,59,37,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1975, in respect of 'Department of Cooperation' "

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Half an-Hour discussion standing in the name of Shri Chandra Shailani.